वर्ष 13 • अंक 24 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 16 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 3

आभूषण खरीद में आया ठहराव

नरेंद्र मोदी ▶▶ पृष्ठ 12

दक्षेस के लिए आपात कोष जरूरी

एक नज़र

येस बैंक मामले में अनिल अंबानी को ईडी का समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ चल रहे धन शोधन के मामले के सिलसिले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिलायंस समूह ने येस बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। ईडी के एक अधिकारी ने अंबानी को समन भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि बैंक के सभी बड़े कर्जदारों और फंसे हुए कर्ज की जांच की जा रही है। ये कर्ज कपूर के कार्यकाल के दौरान आवंटित किए गए थे। अंबानी को सोमवार को जांच में शामिल होने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि अंबानी को उनके ग्रुप को मिले ऋण और उसकी शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। पृष्ठ 2

कोरोना और फेडरल रिजर्व से तय होगी बाजार की चाल

शेयर बाजारों में इस सप्ताह और उतार-चढ़ाव की आशंका है। विश्लेषकों का मानना है कि कोरोना के कारण पिछले सप्ताह आई भारी गिरावट के बाद बाजार में थोड़ा सुधार दिख सकता है। हालांकि दुनिया के केंद्रीय बैंकों एवं सरकारों से मिलने वाले प्रोत्साहन उपायों पर भी निवेशकों की निगाह होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस सप्ताह नीतिगत दर के बारे में फैसले की घोषणा करेगा। वृहद आर्थिक मोर्चे पर थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा सोमवार को जारी होगा।

थोक में कॉल डेटा आंकड़े जुटा रहा दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग की कुछ इकाइयां कई सर्किलों में नियमित रूप से बड़ी संख्या में लोगों के कॉल के आंकड़े जुटा रही हैं। दूरसंचार कंपनियों ने इस पर चिंता जाहिर की है। इन कंपनियों का कहना है कि यह सरकार द्वारा तय मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लंघन है। सूत्रों ने बताया कि उद्योग की कंपनियों ने इस तरह के व्यवहार पर चिंता जताते हुए दूरसंचार सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने दावा किया कि दूरसंचार विभाग की दिल्ली इकाई ने 2, 3 और 4 फरवरी 2020 के दौरान पूरे राज्य का कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) मांगा है।

मप्र में विश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान संभव!

राजनीतिक संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को आरंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ नीत कांग्रेस सरकार को सोमवार को बहुमत साबित करने को कहा है। उधर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बहुमत साबित करने से जुड़े सवालों को काल्पनिक करार देते हुए कहा कि इस विषय में सोमवार को सारी जानकारी सामने आ जाएगी। कांग्रेस ने जयपुर गए अपने विधायकों को वापस भोपाल बुला लिया है। कोरोनावायरस को देखते हुए सभी विधायकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है।

बाजार में गिरावट थामेगा सेबी!

सर्किट फिल्टर, शॉर्ट सेलिंग व उतार-चढ़ाव वाले शेयरों के इंट्रा-डे पर रोक के होंगे उपाय

श्रीमी चौधरी और समी मोडक
नई दिल्ली/मुंबई, 15 मार्च

शेयर बाजार में अचानक चौतरफा बिकवाली से भौचक बाजार नियामक उतार-चढ़ाव को रोकने के उपाय तैयार कर रहा है। कोरोनावायरस के प्रसार से दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का रुख बना हुआ है।

मामले के जानकार लोगों ने बताया कि बाजार नियामक ने शॉर्ट सेलिंग पर रोक, आपूर्ति आधारित ट्रेडिंग की अनिवार्यता और ज्यादा उतार-चढ़ाव वाले शेयरों के लिए अतिरिक्त निगरानी प्रणाली जैसे कुछ उपाय किए गए हैं।

अगर बाजार में गिरावट बनी रहती है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इनमें से कुछ उपायों की घोषणा कर सकता है ताकि अटकलों पर रोक और गिरावट पर लगाम लग सके।

> दुनिया के अन्य देशों ने बाजार में गिरावट को थामने के लिए उपायों की घोषणा की है, ऐसे में सेबी पर भी दबाव बना हुआ है

सूत्रों ने कहा कि पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने बाजार नियामक की खिंचाई करते हुए बाजार में आ रही तेज गिरावट को थामने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।

बीते शुक्रवार को निफ्टी 10 फीसदी तक फिसल गया, जिसकी वजह से 2008 के बाद पहली बार कारोबार रोकना पड़ा। दोबारा कारोबार शुरू होने के बाद निफ्टी ने शानदार वापसी की और निचले स्तर से 16 फीसदी की बढ़त पर बंद हुआ। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रोत्साहनों की घोषणा से बाजार में सुधार हुआ और कोरोना संकट से हुए नुकसान की भरपाई करने में बाजार सफल रहा। अगर भारत शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाने के उपाय करता है तो वह दक्षिण कोरिया, स्पेन और इटली जैसे देशों में शामिल हो जाएगा, जिसने बाजार में स्थिरता लाने के लिए इस पर रोक लगाई है। शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग रणनीति होती है जिसमें शेयर भाव में गिरावट पर दांव लगाया जाता है। इसमें ट्रेडर्स शॉर्ट करने के लिए शेयर उधार लेता है या फिर डेरिवेटिव बाजार का इस्तेमाल करता है जो उक्त शेयर के नहीं रहने पर भी शॉर्ट सेलिंग की इजाजत देता है।

एक्सचेंज के एक अधिकारी ने कहा, 'अन्य देशों ने बाजार में गिरावट को थामने के लिए उपायों की घोषणा की है, ऐसे में सेबी पर भी दबाव बना हुआ है। घरेलू बाजार के ढांचे के आधार पर सेबी ऐसे उपायों को अपना सकता है जिससे निवेशकों के बीच घबराहट न बढ़े।'

हालांकि कुछ का कहना है कि ऐसे उपायों से बाजार का भला होने से ज्यादा नुकसान होने का जोखिम है। उद्योग के एक विशेषज्ञ ने कहा, 'शॉर्ट सेलिंग पर पाबंदी एकदम विषम परिस्थिति में करना चाहिए। इसका लाभ अल्पावधि में होता है और बाजार में व्यापक तौर पर लाभ नहीं होता है।'

विशेषज्ञों ने कहा कि शार्ट सेलिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की जगह सेबी डेरिवेटिव्स खंड में शॉर्ट करने पर रोक लगा सकता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को केवल अपने नकद पोजिशन को हेज करने के लिए शॉर्ट करने की अनुमति होगी। पार्टिसिपेटरी नोट के जरिये निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए भी इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं।

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से ज्यादा उतार-चढ़ाव वाले कारोबार (एचएफटी) और अल्गोरिद्मिक पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। कई लोगों का मानना है कि शुक्रवार को आई 10 फीसदी की गिरावट अल्गो और एचएफटी की वजह से आई है क्योंकि काफी कम वॉल्यूम के बावजूद शेयर भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने सेबी को वित्तीय बाजार से जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में नियमित जानकारी देने तथा बाजार में उतार-चढ़ाव को काबू में करने के उपाय करने को कहा है। इस बारे में पक्ष जानने के लिए सेबी कोई ईमेल किया गया किया उसका जवाब नहीं आया।

निफ्टी की चाल

एक महीने से भी कम में 2,000 अंक लुढ़का निफ्टी

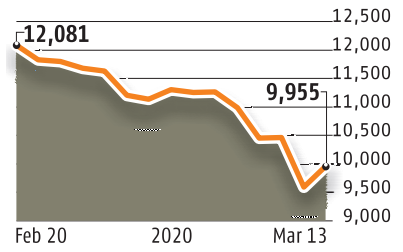

गिरावट रोकने के उपाय

- स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शॉर्ट-सेलिंग पर लगाई रोक
- सेबी भी गिरावट थामने के लिए करेगा इसी तरह के उपाय
- कोरोना संकट की वजह से बाजार में हो रही चौतरफा बिकवाली
- कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक से नहीं होगा फायदा

लघु बचत पर ब्याज में हो सकती है कटौती

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 15 मार्च

वित्त मंत्रालय अप्रैल-जून तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को सूत्रों से यह जानकारी मिली है। इस कटौती का मकसद क्रेडिट की लागत को कम करना है ताकि वित्तीय व्यवस्था को ज्यादा नकदी मुहैया कराई जा सके। कोरोनावायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती और घरेलू बैंकिंग संकट के कारण वित्तीय व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

वित्त मंत्रालय ने इससे पहले 2019 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 12 लघु बचत योजनाओं में से एक को छोड़कर बाकी सभी योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती की थी। अक्टूबर-दिसंबर 2019 और जनवरी-मार्च 2020 तिमाहियों में दरों को यथावत रखा गया था।

केंद्र को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भी नीतिगत दरों में कटौती करेगी जिससे पूंजी की लागत में और कमी लाने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'अर्थव्यवस्था को गति देने और दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए सरकार उधारी गतिविधियों में सुधार के लिए कुछ कदम उठा सकती है।' अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि लघु बचत योजना की ब्याज दर में कटौती पर विचार किया जा रहा है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'वित्तीय क्षेत्र को पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं लेकिन इसका अल्पकालिक प्रभाव यह है कि क्रेडिट के कुछ रास्ते अवरुद्ध हैं। कोरोनावायरस ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे समय में हम क्रेडिट गतिविधियों में सुधार करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आरबीआई भी दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए उपायों का अनुसरण करेगा।'

अधिकारियों ने स्वीकार किया कि संभव है कि येस बैंक प्रकरण से लोगों का वित्तीय क्षेत्र पर भरोसा डगमगा गया है और पूंजी की लागत कम करना इस भरोसे को फिर से कायम करने का एक उपाय है। उन्होंने कहा कि लघु बचत योजनाओं में ब्याज की दरों में कटौती से बैंक भी दरों में कटौती के लिए प्रोत्साहित होंगे।

कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने कोरोनावायरस के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। इनमें अमेरिकी फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंगलैंड शामिल है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोरोनावायरस के कारण कई देशों में मंदी आ सकती है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 31 मार्च, 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को होनी है। अप्रैल-जून तिमाही के लिए लघु बचत ब्याज दरों की अधिसूचना 31 मार्च को जारी होने की संभावना है।

...घटेगा ब्याज

- अप्रैल-जून तिमाही में लघु योजनाओं पर घट सकती है ब्याज दर
- पिछली दो तिमाहियों में ब्याज दर में नहीं किया गया था बदलाव

कोरोना से एयर इंडिया का घटा मूल्यांकन

देव चटर्जी
मुंबई, 15 मार्च

कोरोनावायरस के प्रसार से एयर इंडिया का मूल्यांकन करीब आधा घट गया है, वहीं संभावित बोलीदाताओं का कहना है कि आने वाले महीनों में सभी विमानन कंपनियों के राजस्व और मुनाफे में गिरावट आने का अनुमान है।

विश्वव्यापी महामारी का असर विमानन कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर भी दिख रहा है। यूनाइटेड एयरलाइंस का शेयर भाव इस साल जनवरी से अब तक 58 फीसदी और लुफ्थांसा का शेयर 36 फीसदी तक लुढ़क चुका है।

एयर इंडिया के संभावित बोलीदाताओं ने कहा कि कोरोना संकट के बाद वे भारत और विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते एयर इंडिया के लिए बोली लगाएंगे। एब बोलीदाता ने कहा, 'भारत और विदेशी बाजार में कई विमानन कंपनियां सूचीबद्ध हैं और एयर इंडिया के मूल्यांकन के लिए यह एक अच्छा संकेतक है। विमानन उद्योग को 2020 में करीब 67 अरब डॉलर का नुकसान होने का अंदेशा है और आने वाले महीनों में कई विमानन कंपनियां दिवालिया आवेदन कर सकती हैं।'

- कारोबार प्रभावित होने से दुनिया भर की विमानन कंपनियों के शेयरों में आ रही गिरावट
- एयर इंडिया का मूल्यांकन करीब आधा घटने का अंदेशा
- कोरोना के कारण विमानन कंपनियों को भारी नुकसान
- संभावित बोलीदाता घटा सकते हैं अपनी बोली

बोलीदाता ने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स और डॉयचे लुफ्थांसा एजी मुनाफा कमा रही हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस 1250 विमानों के बेड़े के साथ 369 गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती हैं, वहीं लुफ्थांसा 400 बेड़ों के साथ 220 गंतव्यों के लिए उड़ान भरती है। डेल्टा एयरलाइन का शेयर भाव 1 जनवरी को 58 डॉलर प्रति शेयर था जो शुक्रवार को 38.36 डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिका की इस विमानन कंपनी के पास 909 विमानों का बेड़ा है और वह 325 गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती हैं।

एयर इंडिया घाटे वाली कंपनी है और इसके पास 140 विमानों का बेड़ा है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के 2007 में विलय से ही यह कंपनी मुनाफा कमाने में विफल रही है। एयर इंडिया के अलावा सरकार इसकी सहायक इकाइयों एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ही एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज में 50 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रही है।

हिंदुजा के अलावा अदाणी समूह और अमेरिका की कंपनी इंटरप्स के साथ ही टाटा समूह द्वारा बोली लगाए जाने की उम्मीद है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए अभिरुचि पत्र जमा कराने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। एक संभावित बोलीदाता ने कहा कि वह बोली के बारे में अप्रैल के अंत में निर्णय करेगा, वहीं एक अन्य ने कहा कि मौजूदा स्थिति में वह शायद बोली न लगाए।

येस बैंक में 250 करोड़ रुपये लगाएगा आईडीएफसी फर्स्ट : आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे येस बैंक में 250 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा। इस निवेश से बैंक को यस बैंक के 25 करोड़ शेयर मिलेंगे। *भाषा*

दफ्तर-रेस्टोरेंटों में घटी चहल-पहल

अर्णव दत्ता, समरीन अहमद, राघवेंद्र कामत, गिरीश बाबू और अभिषेक रक्षित
गुरुग्राम, बेंगलूरु, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 15 मार्च

एन95 मेडिकल मास्क पहने दो सुरक्षा गार्ड इन्फ्रारेड थर्मोमीटर से हर आगंतुक के तापमान की जांच कर रहे हैं। उनके बीच एक तख्ती लगी है, जिस पर लिखा है, 'तापमान की जांच चल रही है, कृपया सहयोग करें।' मास्क पहने करीब एक दर्जन लोग परिसर की सफाई कर रहे हैं।

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित वन होराइजन सेंटर टावर में घुसने पर आपको यह नजारा दिखता है। इसके साथ ही टू होराइजन सेंटर है। इन दोनों टावरों में ऐपल, कोका-कोला, सैमसंग और जीएसके कंज्यूमर हेल्थकेयर सहित कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं। साथ ही इसमें कई शोरूम और रेस्त्रां भी हैं। अमूमन इस परिसर में काफी चहल-पहल रहती है लेकिन आजकल इसमें सन्नाटा पसरा है।

- देश भर के कार्यालयों में कोरोना से बचाव के हो रहे उपाय
- सभी आगंतुकों की इन्फ्रारेड थर्मोमीटर से हो रही जांच
- अधिकांश कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा

देश में हर जगह कारोबार पर कोरोनावायरस का व्यापक असर दिखाई दे रहा है और यह वाणिज्यिक परिसर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यहां आने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। दिल्ली क्लब हाउस जैसे लोकप्रिय रेस्त्रां में नियमित रूप से आने वाले ग्राहक आजकल नदारद हैं। रेस्त्रां के कर्मचारियों के मुताबिक उनकी बिक्री में पिछले 10 दिनों में करीब 50 फीसदी गिरावट आई है। गुरुग्राम में युवाओं का लोकप्रिय अड्डा साइबर हब का भी यही हाल है। इसमें स्थित अधिकांश रेस्त्रां खाली पड़े हैं। कारोबार पर कोरोनावायरस के प्रभाव की थाह लेने निकले बिज़नेस स्टैंडर्ड के संवाददाताओं को देशभर में ऐसे दृश्य देखने को मिले।

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर आजकल खाली पड़े हैं। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कोरोनावायरस से बचाने के लिए उन्हें घर से काम करने की सुविधा दी है। इनमें कोका-कोला इंडिया भी शामिल है जिसका दफ्तर वन होराइजन की 16वीं और 17वीं मंजिल पर स्थित है। कंपनी के 17वीं मंजिल कार्यालय में फिर से तापमान की जांच हो रही है और उसके बाद हाथों पर सैनिटाइजर लगाने को कहा जा रहा है। ऑफिस करीब 25 फीसदी खाली है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर कुछ किलोमीटर आगे चलने पर नेस्ले इंडिया का दफ्तर है। कंपनी अपने उन कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर करीबी नजर बनाए हुए है जिन्हें हाल में स्वास्थ्य समस्या हुई थी और जो विदेश से लौटे हैं।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

संक्षेप में

कोरोना की मार के बीच हुंडई को उम्मीद

कोरोनावायरस महामारी के बीच दक्षिण कोरिया की वाहन कंपनी हुंडई को उम्मीद की किरण दिख रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वाहन बाजार में सुस्ती के बीच इस महामारी की वजह से लोग परिवहन के लिए खुद के वाहन को तरजीह देना चाहेंगे। ऐसे में वाहन बाजार के लिए उम्मीद बढ़ी है। कंपनी अपने वाहनों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई हुंडई मोटर इंडिया लि. की राष्ट्रीय स्तर पर क्लिक टु बाय कार्यक्रम शुरू करने की है। पिछले महीने ऑटो एक्सपो के दौरान इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के जरिए उपभोक्ताओं को वाहन खरीदने के लिए भीड़भाड़ वाली डीलरशिप पर जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कंपनी ने कई आंतरिक उपाय किए हैं। *भाषा*

स्कूटर की कुछ इकाइयां वापस मंगा रही होंडा

होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने अपने तीन स्कूटर मॉडलों की कुछ इकाइयों को बाजार से वापस मंगाया है। इन स्कूटरों के रियर कुशन बदलने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी ने बयान में कहा कि वह डियो, ऐक्टिवा 125 और 6जी की 14 से 25 फरवरी, 2020 के दौरान विनिर्मित इकाइयों को वापस मंगा रही है। कंपनी ने कहा कि इन मॉडलों के रियर कुशन के साथ कुछ समस्या है। यह वापसी मार्च के मध्य से शुरू होगी। *भाषा*

येस बैंक में तीन साल तक निवेश फंसे रहने का मामला

बाजार नियामक सेबी से संपर्क करेंगे म्युचुअल फंड

जश कृपलानी
मुंबई, 15 मार्च

येस बैंक के शेयरधारकों का 75 फीसदी निवेश तीन साल तक फंसे रहने के मामले ने म्युचुअल फंडों को परेशानी में डाल दिया है और एक्सचेंजों के साथ म्युचुअल फंड बाजार नियामक सेबी संपर्क करेगा कि सरकार की अधिसूचना के असर को इंडेक्स फंडों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों पर कम किया जा सकता है। क्योंकि इन फंडों को येस बैंक से निकलना होगा जब उसे 27 मार्च को इन सूचकांकों से बाहर निकाल दिया जाएगा।

रूपीवेस्ट के आंकड़ों के मुताबिक, येस बैंक में म्युचुअल फंडों की इक्विटी योजनाओं का निवेश 29 फरवरी तक 492 करोड़ रुपये था और इस निवेश का 62 फीसदी विभिन्न इंडेक्स व ईटीएफ में है। 29 फरवरी को 50 इंडेक्स और ईटीएफ का येस बैंक में निवेश था। एक फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, येस बैंक में जिन योजनाओं के जरिए निवेश किया गया है उनमें से कुछ का आकार बड़ा है और उनकी परिसंपत्तियां 40,000 से 60,000 करोड़ रुपये के बीच है। उनके लिए यह मसला काफी बड़ा हो सकता है। हम इस मामले को सेबी के सामने उठाएंगे।

उद्योग के एक अधिकारी (जो ईटीएफ व इंडेक्स फंड पर उद्योग निकाय की समिति का हिस्सा हैं) ने कहा, हम एक्सचेंजों और उद्योग निकाय एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। इस मसले पर दोनों सेबी से स्पष्टीकरण मांगेंगे।

3,400 करोड़ रुपये का गैर-प्रवर्तक फंड फंसेगा

निवेशक श्रेणी	हिस्सेदारी (फीसदी)	मौजूदा कीमत (करोड़ रुपये)	75 फीसदी लॉक
खुदरा	43.66	2,840	2,130
एफपीआई	15.17	986	740
म्युचुअल फंड	5.09	492	369
एचएनआई	4.3	280	210

स्रोत : एक्सचेंज, रूपीवेस्ट से एमएफ के 29 फरवरी के आंकड़े
अन्य श्रेणियों की वैल्यू मौजूदा कीमत और 31 दिसंबर के निवेश पर आधारित

27 मार्च से येस बैंक को निफ्टी और बैंक निफ्टी सूचकांकों से बाहर कर दिया जाएगा।

शुक्रवार को सरकार ने येस बैंक की योजना को अधिसूचित कर दिया। इस अधिसूचना की धारा 8 में कहा गया है कि योजना के लागू होने से तीन साल की अवधि तक 75 फीसदी निवेश लॉक रहेगा। उद्योग के प्रतिभागी चिंतित हैं क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा व नए निवेशक कम से कम तीन साल तक 25 फीसदी से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे।

निवेश के लॉक इन से निवेशकों के भरोसे पर भी चोट पहुंच सकती है, जिन्होंने गुरुवार या शुक्रवार को बैंक के शेयर खरीदे। स्टॉक लेंडिंग ऐंड बॉरोइंग के तहत शेयर उधार देने वाले संस्थागत निवेशकों को भी शायद सारे शेयर वापस नहीं मिल पाएंगे।

किसी इंडेक्स या ईटीएफ की 95 फीसदी परिसंपत्तियां अंतर्निहित इंडेक्स के मुताबिक होनी जरूरी है। एक फंड मैनेजर ने कहा, हालांकि मोटे तौर पर इंडेक्स व ईटीएफ बाकी 5 फीसदी हिस्सा नकदी रखती हैं ताकि रीडम्पशन के दबाव से निपटा जा सके। साथ ही तीन साल तक येस बैंक के शेयरों में निवेशित रहने से भी काफी मुश्किल होगी।

येस बैंक को निफ्टी व बैंक निफ्टी से हटाया जाएगा और इन सूचकांकों में नए शेयर जोड़े जाएंगे। फंड मैनेजर ने कहा, बैंक निफ्टी से जुड़े फंडों को बंधन बैंक को शामिल करने में काफी मुश्किल हो सकती है, जो येस बैंक की जगह लेगा और इसके साथ उसे येस बैंक के शेयरों में भी आंशिक निवेश बनाए रखना होगा। इसी तरह श्री सीमेंट अब निफ्टी में येस बैंक की जगह लेगा। उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, म्युचुअल फंड व एक्सचेंज सेबी के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं कि इंडेक्स को पुनर्संतुलित करने की तारीख 27 मार्च से आगे बढ़ा दी जाए ताकि सरकार इस मसले पर स्पष्टीकरण दे सके।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा, येस बैंक के शेयरों को अलग पोर्टफोलियो में बनाए रखना और योजनाओं के यूनिटधारकों को अलग यूनिट का आवंटन इसका समाधान हो सकता है। एक फंड हाउस के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, हालांकि सेबी ऐसी कवायद पर छूट देनी होगी क्योंकि मौजूदा नियामकीय ढांचे के तहत साइड पॉकेट का सृजन डेट योजना में हो सकता है जब रेटिंग घटाकर निवेश श्रेणी से नीचे किया गया हो।

2,100 करोड़ रुपये से ज्यादा खुदरा रकम फंसेगी

एमएफ के अलावा अन्य मौजूदा शेयरधारकों की अच्छी खासी हिस्सेदारी येस बैंक में फंसने के आसार हैं, अगर मौजूदा सरकारी अधिसूचना में संशोधन नहीं किया जाता या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाता। खुदरा निवेशकों के पास येस बैंक के 2,839 करोड़ रुपये के शेयर हैं, जिसकी गणना मौजूदा शेयर कीमत और 31 दिसंबर 2019 की शेयरधारिता के आधार पर की गई है।

खुदरा निवेशक पर इसके असर का आकलन करना हालांकि मुस्किल है क्योंकि प्रावधान सिर्फ उन्हीं निवेशकों पर लागू होगा जिनके पास 100 से ज्यादा शेयर हैं। 75 फीसदी खुदरा निवेश के फंस जाने का मतलब 2,129 करोड़ रुपये के शेयर लॉक हो जोंगे। 31 दिसंबर 2019 को 16 लाख से ज्यादा आम शेयरधारकों का बैंक में निवेश था। उधर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का इस बैंक में 986 करोड़ रुपये निवेशित है। एचएनआई के पास येस बैंक के 280 करोड़ रुपये के शेयर हैं। इस निवेश का 75 फीसदी लॉक होने का मतलब यह है कि एचएनआई के 209 करोड़ रुपये फंस जाएंगे। इसी तरह एफपीआई के 739 करोड़ रुपये लॉक हो जाएंगे।

300 करोड़ रुपये निवेश करेगा फेडरल बैंक

केरल का फेडरल बैंक लिमिटेड आरबीआई की पुनर्गठन योजना के तहत येस बैंक में 300 करोड़ रुपये निवेश करेगा। बैंक ने येस बैंक का इक्विटी शेयर लेने के लिए प्रतिबद्धता पत्र जारी किया है। फेडरल बैंक ने कहा कि 10 रुपये प्रति शेयर पर येस बैंक के 30 करोड़ शेयर खरीदने के लिए उसने प्रतिबद्धता पत्र जारी किया है।

अनिल अंबानी को ईडी का समन

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 15 मार्च

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ चल रहे धन शोधन के मामले के सिलसिले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिलायंस समूह ने येस बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

ईडी के एक अधिकारी ने अंबानी को समन भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि बैंक के सभी बड़े कर्जदारों और फंसे हुए कर्ज की जांच की जा रही है। ये कर्ज कपूर के कार्यकाल के दौरान आवंटित किए गए थे। अंबानी को सोमवार को जांच में शामिल होने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि अंबानी को उनके ग्रुप को मिले ऋण और उसकी शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर उनका येस बैंक के साथ कोई साइड अनुबंध है तो उसका भी खुलासा करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र को आवंटित बैंक का एक बड़ा हिस्सा अनिल अंबानी के समूह को मिला था और जांच एजेंसी ऋण के आवंटित की प्रक्रिया को समझना चाहती है।

इस बारे में रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता को शनिवार को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने येस बैंक के पांच शीर्ष कर्जदारों की एक सूची तैयार की है जिन्हें कपूर के कार्यकाल के दौरान भारी कर्ज दिया गया था। इनमें से अधिकांश कर्जदारों ने भुगतान में चूक की है और उनका कर्ज फंसा हुआ ऋण बन गया है। इसलिए इनमें से हर खाता ईडी की जांच के दायरे में है और आने वाले दिनों में उनके प्रबंधन/प्रवर्तकों से पूछताछ की जाएगी।

पिछले सप्ताह रिलायंस ग्रुप ने कहा था कि उसका कपूर परिवार या उसके द्वारा नियंत्रित किसी भी कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई निवेश नहीं है। ग्रुप ने एक बयान में कहा कि येस बैंक का सारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित है और यह लेनदेन कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है। समूह येस बैंक के ऋण के भुगतान के लिए कटिबद्ध है।

येस बैंक के ऋण के भुगतान में चूक करने वाली बड़ी कंपनियों में वोडाफोन इंडिया, दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल), इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस), एस्सेल ग्रुप, सीजी पावर, कॉक्स ऐंड किंग्स तथा रेडियस डेवलपर्स शामिल हैं। आईएलऐंडएफएस, डीएचएफएल और सीजी पावर पहले से ही वित्तीय अनियमितताओं के कारण कई एजेंसियों की जांच का सामना कर रही हैं।

येस बैंक के शीर्ष कर्जदार

- रिलायंस एडीएजी ग्रुप, एस्सेल ग्रुप, वोडाफोन इंडिया
- रिलायंस एडीएजी ग्रुपः 12,000 से 14,000 करोड़ रुपये
- कुल फंसा कर्जः 30,000 करोड़ रुपये

येस बैंक के निवेशकों के लिए नई मुश्किल

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 15 मार्च

यह सप्ताहांत अप्रत्याशित रहा, जिसमें येस बैंक के निवेशकों के लिए कई निराशाजनक बातें हुईं। बैंक की पुनर्गठन योजना में खुदरा व संस्थागत शेयरधारकों के लिए 75 फीसदी निवेश पर तीन साल की पाबंदी लगाई गई। इसमें सभी मौजूदा शेयरधारक शामिल हैं, जिनके पास बैंक के 100 से ज्यादा शेयर हैं।

दूसरी मुश्किल ने अतिरिक्त टियर-1 बॉन्डधारकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिनका येस बैंक में 8,415 करोड़ रुपये निवेश है क्योंकि बैंक के प्रशासक ने संकेत दिया है कि इन प्रतिभूतियों को पूरी तरह से बट्टे खाते में डाला जाएगा। यह भले ही पुनर्गठन योजना के मसौदे का हिस्सा रहा हो, लेकिन एटी-1 बॉन्डधारकों को भरोसा था कि उनके बॉन्ड को शेयर में परिवर्तित किया जाएगा, चाहे उन्हें 80 फीसदी कटौती क्यों न झेलनी पड़े। इस मामले को कानूनी चुनौती दी गई है, लेकिन अभी येस बैंक के एटी-1 बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका दिसंबर तिमाही के नतीजे के तौर पर आया। 24,765 करोड़ रुपये के प्रावधान की पृष्ठभूमि में बैंक का शुद्ध नुकसान 18,564 करोड़ रुपये रहा, लेकिन इसने निवेशकों को चौंकाया। दूसरी तिमाही से जमाएं 21 फीसदी सिकुड़कर 1,65,755 करोड़ रुपये रह गई है, साथ ही लोनबुक क्रमिक आधार पर 17 फीसदी घटकर 1,86,099 करोड़ रुपये रही, जो उम्मीद के मुताबिक थी।

तीसरी तिमाही में सीईटी-1 घटकर 0.6 फीसदी रह गई, जो वैधानिक स्तर 7.375 फीसदी से काफी कम है, वहीं तीसरी तिमाही में बैंक पर 86 करोड़ रुपये का जुर्माना न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात व तरलता कवरेज अनुपात को तोड़ने पर लगाया गया। बैंक के अंकेक्षकों ने तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में कहा है, ये चीजें बताती है कि अनिश्चितता बनी हुई है, जो बैंक के चालू बने रहने पर संदेह जताता है। ये आंकड़े हालांकि अन्य छोटे बैंक लक्ष्मी विलास बैंक से भी खराब हैं। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य निजी बैंकों ने इस बैंक में 10,000 करोड़ रुपये लगाने पर सहमति जताई है, पर सीईटी-1 और नकद आरक्षी अनुपात क्रमशः 7.6 फीसदी और 13.6 फीसदी पर लाना असंभव जैसा होगा।

हालांकि 29,594 करोड़ रुपये का प्रावधान यानी 40,709 करोड़ रुपये का एनपीए कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, जिसके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि यह बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता की पूरी स्थिति नहीं बताती। यूबीएस, जेपी मॉर्गन और मैक्वेरी जैसी ब्रोकरेज फर्मों ने 60,000 करोड़ रुपये का दबाव वाला कर्ज माना है, वहीं येस बैंक ने विगत में खुद 30,000 करोड़ रुपये के कर्ज को दबाव वाले कर्ज के तौर पर वर्गीकृत कर चुका है।

उस लिहाज से तीसरी तिमाही में 40,709 करोड़ रुपये का एनपीए छोटा आंकड़ा नजर आ रहा है। एक विदेशी ब्रोकरेज के विश्लेषक ने कहा, शायद पूंजी के अवरोध से पूरी परेशानी की पहचान नहीं हो पाई। प्रावधान कवरेज अनुपात दूसरी तिमाही के 43.1 फीसदी से सुधरकर तीसरी तिमाही में 72.7 फीसदी पर पहुंच गया, लेकिन विस्लेषकों को और बेहतर आंकड़े की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, इस लिहाज से निवेशकों को पूंजी निवेश, एनपीए में बढ़ोतरी और संभावित नुकसान के एक और दौर से लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। एमके ग्लोबल फाइनैंशियल के विश्लेषकों ने कहा, बैंक को आगे बढ़ने के लिए और पूंजी की दरकार होगी।

अंकेक्षकों ने यह भी कहा है कि बैंक के चालू हालत में बने रहने की संभावना अंतिम पुनर्गठन योजना की सफलता, बैंक में लगाई जाने वाली पूंजी और आरबीआई की तरफ से रोक हटाए जाने के बाद अपने जमाओं के संतुलन को स्थिर रखने की क्षमता पर निर्भर करेगा। नई पूंजी का निवेश निवेशकों के लिए हालांकि अभी सकारात्मक है, लेकिन येस बैंक की तीसरी तिमाही के नतीजे ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।

कैसे खराब हुई परिसंपत्ति गुणवत्ता

	दूसरी तिमाही (फीसदी)	तीसरी तिमाही (फीसदी)
सकल एनपीए	7.39	18.87
खुदरा	1.03	1.36
एमएसएमई	1.29	1.63
कॉरपोरेट	11.07	29.3
शुद्ध एनपीए	4.35	5.97
पीसीआर	43.05	72.7
नया फंसा कर्ज *	2.58	11.98

* सालाना नहीं। वित्त वर्ष 2021 के लिए 5 फीसदी फंसे कर्ज का अनुमान जताया गया था
स्रोत : निवेशकों के सामने रखे गए आंकड़े

सकारात्मक ग्रामीण माहौल से ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी

फरवरी में ट्रैक्टर की बिक्री 13.52 फीसदी बढ़ी जबकि पूरे वाहन उद्योग की खुदरा बिक्री 2.60 फीसदी बढ़ी

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 15 मार्च

एक ओर जहां पूरा वाहन क्षेत्र दबाव का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रबी की अच्छी फसल और फसल की मौजूदा कीमतों से ट्रैक्टर की बिक्री बेहतर रही है। साथ ही सरकार की तरफ से ग्रामीण व कृषि पर खर्च में बढ़ोतरी भी उद्योग के लिए बेहतर रहा।

ट्रैक्टर की बिक्री फरवरी 2020 में करीब 13.52 फीसदी बढ़ी, वहीं पूरे वाहन उद्योग में खुदरा बिक्री में 2.60 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विश्लेषकों ने कहा, आने वाले समय में फंडों की कमी से ट्रैक्टर की बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा कि ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री फरवरी 2020 में बढ़कर 41,485 वाहन हो गई, जो एक साल पहले 36,543 रही थी।

इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि ट्रैक्टर उद्योग की बिक्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित सुधार का उत्साहजनक संकेत दिया है।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट क्षेत्र (20.7 अरब डॉलर वाले महिंद्रा समूह का हिस्सा) की देसी बिक्री फरवरी 2020 में 21,877 इकाई रही, जो फरवरी 2019 के 18,105 इकाई के मुकाबले 21 फीसदी ज्यादा है।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के अध्यक्ष (फार्म इक्विपमेंट सेक्टर) राजेश जेजुरिकर ने कहा, ट्रैक्टर की मांग की प्रवृत्ति में और मजबूती होगी क्योंकि रबी की फसल अच्छी रही है और फसल की मौजूदा कीमत बेहतर है। आने वाले समय में ग्रामीण व कृषि से जुड़ी प्रमुख योजनाओं पर सरकार की तरफ से खर्च में बढ़ोतरी उद्योग के लिए बेहतर रहेगी।

देश में सबसे बड़ी ट्रैक्टर विनिर्माताओं में से एक टैफे की चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा, हम सर्तकता के साथ आशावादी हैं। मॉनसून बेहतर रहा है, हालांकि इसमें देर हुई और खरीफ फसल को फायदा नहीं हुआ। देश में पानी की अच्छी स्थिति को देखते हुए कृषि संकेतकों के लिहाज से आगामी सीजन शानदार नजर आ रहा है।

आय टूटने से कर्जदार फर्मों को मुश्किल

तात्कालिक प्रभाव धातु क्षेत्र में दिखेगा जहां अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया गिरावट से आय को लगेगा झटका

कृष्ण कांत
मुंबई, 15 मार्च

अगले कुछ महीने भारतीय उद्योग जगत के लिए वित्तीय लचीलापन का परीक्षा साबित हो सकता है। जिंस एवं ऊर्जा कीमतों में आई हालिया गिरावट और कोरोनावायरस के फैलने से आर्थिक उथल-पुथल के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में नरमी के मद्देनजर भारतीय उद्योग जगत अपने राजस्व और आय अनुमानों में भारी कटौती कर रहा है। विश्लेषकों को धातु एवं खनन क्षेत्र और तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनियों के लिए तात्कालिक प्रभाव दिख रहा है लेकिन वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति से भी गैर-बैंकिंग फाइनैंस, बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'धातु एवं ऊर्जा कीमतों में आई हालिया गिरावट के कारण अगली कुछ तिमाहियों के दौरान इन क्षेत्रों की अधिकतर कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे को झटका लगेगा। कई कंपनियां घाटा भी दर्ज कर सकती हैं।'

लाभप्रदता में कोई भी भारी गिरावट अधिक ऋण बोझ तले दबी और कम ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) वाली कंपनियों के लिए वित्तीय तौर पर कष्टदायक हो सकती है। आईसीआर किसी कंपनी की ऋण पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने का पैमाना है। इसका आकलन किसी खास अवधि के दौरान कंपनी के परिचालन लाभ को उसकी ब्याज देनदारी से भाग देकर किया जाता है। अधिक अनुपात को बेहतर माना जाता है जबकि 1.5 से कम अनुपात का मतलब साफ है कि कंपनी मार्जिन पर है और मार्जिन अथवा मुनाफे में मामूली गिरावट से भी वह ब्याज भुगतान में चूक कर सकती है।

हालांकि अन्य विश्लेषकों का कहना है कि उन कंपनियों को सबसे अधिक झटका लगेगा जहां प्रवर्तकों की अधिक हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी सर्विसेज के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम ने कहा, 'सबसे अधिक परेशानी उन कंपनियों को होगी जो अधिक ऋण बोझ तले दबी हुई है और उसके प्रवर्तकों की अधिकांश हिस्सेदारी गिरवी है।'

इसे ध्यान में रखते हुए हमने सबसे अधिक ऋण बोझ तले दबी उन दस कंपनियों की सूची तैयार की है जिनका आईसीआर वित्त वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों की अवधि में 3 गुना से कम रहा है। इस लिहाज से देश की अधिकतर धातु उत्पादक कंपनियों को आगामी तिमाहियों में वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों के दौरान 2.2 गुना ब्याज कवरेज अनुपात दर्ज किया जो एक साल पहले 4 गुना था। इस दौरान कंपनी के परिचालन मुनाफे में 46 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई जबकि उसकी ब्याज देनदारी में सालाना आधार पर करीब 2 फीसदी की कमी आई। वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में समेकित आधार पर इस इस्पात कंपनी का कुल ऋण बोझ करीब 1.24 लाख करोड़ रुपये था। जबकि उसका बाजार पूंजीकरण घटकर करीब 32,300 करोड़ रुपये रहा गया। ऐसे में कंपनी के लिए ताजा रकम जुटाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया।

इसी प्रकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) का ब्याज कवरेज अनुपात वित्त वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों के दौरान घटकर 1.7 गुना रह गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 3.2 गुना रहा था। इस दौरान कंपनी के परिचालन लाभ में 41.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई जबकि उसकी ब्याज देनदारी 9.6 फीसदी बढ़ गई। इस क्षेत्र में कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली अन्य कंपनियों में जिंदल स्टील ऐंड पावर और जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल हैं।

ऋण बोझ तले दबी शीर्ष कंपनियों की वित्तीय स्थिति (करोड़ रुपये में)

कंपनी	आईसीआर*	कुल सकल ऋण	बाजार पूंजीकरण
टाटा स्टील	2.19	1,24,787.7	32,311.40
टाटा पावर	2.00	55,630.9	10,954.34
अदाणी पावर	1.40	54,490.3	11,705.81
सेल	1.74	53,951.6	10,223.05
जेएसडब्ल्यू स्टील	2.87	49,417.0	49,081.66
जिंदल स्टील	1.79	37,901.6	11,628.18
पीरामल इंटरप्राइज	1.68	36,033.2	23,379.30
आईआरबी इन्फ्रा डेवलपर्स	2.13	29,862.8	2,261.58
रिलायंस पावर	1.36	29,593.9	384.30
रिलायंस इन्फ्रा	2.15	24,212.0	356.35

*वित्त वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात
स्रोत : कैपिटालाइन *संकलनः बीएस रिसर्च ब्यूरो*

टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2020 के नौ महीनों के दौरान 2.2 गुना ब्याज कवरेज अनुपात दर्ज किया जो एक साल पहले 4 गुना था

आभूषण खरीद में आया ठहराव

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 15 मार्च

सोने के दामों में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव की वजह से जौहरियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ा है क्योंकि कोरोनावायरस की वजह से उपभोक्ता दुकानों में जाने से बच रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं के गैर-जरूरी खर्चे में कमी आ गई है और जौहरियों की बिक्री तकरीबन रुक गई है। इसके अलावा अग्रिम कर भुगतान से भी उन पर दबाव बन गया है।

सोने के दामों में गिरावट जारी है तथा शनिवार को भी दामों में और गिरावट आई है। अगले 10 दिन महत्त्वपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि माना जा रहा है कि एक महीने बाद मांग में इजाफा शुरू हो सकता है। जौहरियों ने रख-रखाव की अतिरिक्त लागत से बचने के लिए अपना स्टॉक कम करना शुरू कर

दिया है। पहले जौहरी 35 से 45 दिनों का स्टॉक रख रहे थे, जबकि अब वे स्वयं को दामों की अस्थिरता से बचाने के लिए केवल सात से 10 दिनों का ही स्टॉक तैयार कर रहे हैं। जौहरियों ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान बिक्री के अनुमान से अग्रिम कर और चालू वित्त वर्ष की पिछली तीन तिमाहियों से यदि कोई प्रतिपूरक कर रहता है, तो उसके रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान किया था। इस साल सोने के दामों में तेज उछाल की वजह से कर घटक में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। सोने की कीमतों में उछाल के कारण आयकर विभाग ने जौहरियों से स्टॉक के बढ़े हुए दामों पर अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए कहा है।

रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन और चेन्नई स्थित खुदरा आभूषण विक्रेता एनआईसी ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक अनंत पद्मनाभन ने कहा कि जौहरियों के लिए यह दोहरी मार है क्योंकि कोरोनावायरस तथा सोने के दामों में अधिक अस्थिरता के डर से बिक्री में ठहराव आ गया है। बिक्री में इस गिरावट ने जौहरियों के लिए नकदी की समस्या पैदा कर दी है। इसके साथ ही उन्हें स्टॉक के बढ़े हुए दामों पर अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। इसलिए यह हमारे लिए दोहरा झटका है।

सितंबर के बाद से सोने के दाम महत्त्वपूर्ण रूप से 25 प्रतिशत बढ़कर फिलहाल 41,000 रुपये (शनिवार का भाव) प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहे हैं। स्टैंडर्ड सोने का भाव लगभग 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद शनिवार को मुंबई के जवेरी बाजार में सोने के दामों में कमी आई है। इसी तरह चांदी का भाव 1,500 रुपये तक टूटकर 42,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

प्रमुख बाजारों में भैंसा मांस निर्यात रुका

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 15 मार्च

भारत के तीन प्रमुख निर्यात गंतव्यों - मलेशिया, वियतनाम और तुर्की द्वारा ऑर्डर देना बंद करने के बाद भैंसे के मांस निर्यात में रुकावट आ गई है। विश्वव्यापी महामारी कोरोनावायरस (कोविड-19) फैलने के बाद भैंसा मांस और खाल निर्यातकों के लिहाज से यह सबसे बुरी स्थिति है। वर्ष 2013-14 के बाद से भैंसे का मांस कृषि जिंस बास्केट की सबसे बड़ी निर्यात वस्तु रहा है।

जनवरी में जब से चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप का पता चला था, तब से भारतीय निर्यातकों को एशियाई और पश्चिम एशियाई देशों से कोई नया ऑर्डर नहीं मिला है। देश के कुल भैंसा मांस निर्यात में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 65 प्रतिशत योगदान रहता है। चीन के साथ व्यापार करने वाले देशों में कोरोनावायरस के निरंतर प्रसार और 100 से अधिक देशों में फैलाव की वजह से भैंसे के मांस निर्यात में ठहराव में आ गया है।

25 जनवरी, 2020 को चीन में नए साल के जश्न से पहले हॉन्ग कॉन्ग, वियतनाम और

कोरोनावायरस

- हाल में भेजी गईं खेप बंदरगाहों में फंसी, बड़ी मात्रा में भुगतान रुका
- निर्यातकों को लाखों डॉलर की भुगतान चूक का सता रहा डर, इससे भविष्य में पैदा हो सकती है व्यापारिक रुकावट

मलेशिया जैसे देशों को भेजी जाने वाले कई खेपें अब भी काम बंदी की वजह से बंदरगाहों पर अटकी हुई हैं। जिन्होंने चीन के नव वर्ष से पहले ही अपनी खेपें भेज दी थीं, वे अब भी आयातकों द्वारा भुगतान किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निर्यातकों को डर सता रहा है कि यह भुगतान चूक लाखों डॉलर में हो सकती है और इससे भविष्य में व्यापारिक बाधा पैदा हो सकती है।जम्मू और कश्मीर में अनुबंध 370 और 35ए निरस्त किए जाने के संबंध में मलेशिया और तुर्की के भारत विरोधी रुख के कारण इन देशों के साथ किए जाने वाले कारोबार को भी नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद स्थित भैंसा मांस के कारोबारी फ्रेश एन फ्रोजन टेक के प्रबंध साझेदार शोएब खान ने कहा, 'जब से चीन में कोरोनावायरस का प्रकोप हुआ है, तब से कोई ऑर्डर नहीं मिला है। निर्यात किए गए कई टन भैंसा मांस के लिए अलग-अलग बंदरगाहों पर मंजूरी का इंतजार है। विदेशों में काम बंदी की वजह से लाखों डॉलर का भुगतान अब भी लंबित हैं। हम आयात करने वाले देशों के स्थानीय अधिकारियों को खेपों को मंजूरी देने और माल को वहां कोल्ड स्टोरों में रखवाने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं।'

विदेशी बंदरगाहों पर खेपों को मंजूरी मिलने में देरी के परिणामस्वरूप कंटेनरों और ढुलाई शुल्क के अलावा भारी-भरकम डिमरेज (माल उतराई में देरी का शुल्क) चुकाना पड़ रहा है। खान ने कहा कि इस अतिरिक्त डिमरेज का भुगतान करने से भैंसा मांस के निर्यातकों पर भारी बोझ पड़ रहा है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2019 और जनवरी 2020 के बीच मूल्य के हिसाब से भारत का भैंसा मांस निर्यात आठ प्रतिशत तक गिरकर 2.8 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 3.05 अरब डॉलर था।

स्वर्ण आयात 8.86 प्रतिशत घटा

देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 11 माह (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 8.86 प्रतिशत घटकर 27 अरब डॉलर (1.90 लाख करोड़ रुपये) रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सोने के अधिक आयात से चालू खाते का घाटा (कैड) प्रभावित होता है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में सोने का आयात 29.62 अरब डॉलर रहा था।

सोने के आयात में कमी से वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में देश का व्यापार घाटा कम होकर 143.12 अरब डॉलर रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि में 173 अरब डॉलर रहा था। पिछले साल दिसंबर से सोने का आयात लगातार घट रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का आयातक है। भारत मुख्य रूप से सोने के आयात से घरेलू आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करता है।

देश का सालाना सोना आयात 800 से 900 टन है। व्यापार घाटे और कैड पर सोने के आयात के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने इस पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। स्वर्णाभूषण उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र की कंपनियां ऊंचे शुल्क की वजह से अपने विनिर्माण कारोबार को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित कर रही हैं। रत्न एवं आभूषण निर्यातकों ने आयात शुल्क को घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से फरवरी अवधि में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 8.25 प्रतिशत घटकर 33.78 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2018-19 में मूल्य के हिसाब से देश का सोना आयात तीन प्रतिशत घटकर 32.8 अरब डॉलर रहा था। *भाषा*

कोयला आयात 14 प्रतिशत घटा

कोरोना वायरस की मार से देश का कोयले का आयात भी प्रभावित हुआ है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में कोयले का आयात 14.1 प्रतिशत घटकर 1.70 करोड़ टन पर आ गया। एमजंक्शन सर्विसेज के अस्थाई आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। फरवरी, 2019 में देश का कोयला आयात 1.98 करोड़ टन रहा था। एमजंक्शन टाटा स्टील और सेल का संयुक्त उद्यम है। यह एक बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी है जो कोयला और इस्पात पर शोध रपट भी प्रकाशित करती है। एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय वर्मा ने कहा कि जैसी संभावना थी फरवरी में कोयला आयात कम रहा है। घरेलू उपलब्धता बढ़ने, गैर कोकिंग कोल कीमतों में उतार-चढ़ाव और कोरोना प्रकोप को लेकर अनिश्चितता से कोयले का आयात घटा है।

वर्मा ने कहा कि आगे चलकर कीमतों में गिरावट आ सकती है और आयात मांग सुस्त रह सकती है। फरवरी, 2020 में कुल आयात में गैर-कोकिंग कोल का हिस्सा 1.22 करोड़ टन रहा। जनवरी में इसका आयात 1.23 करोड़ टन से अधिक रहा था। इसी तरह कोकिंग कोयले का आयात फरवरी में 31.5 लाख टन रहा, जो इससे पिछले महीने 39.5 लाख टन था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के पहले 11 माह अप्रैल-फरवरी के दौरान देश का कोयले का आयात 3.7 प्रतिशत बढ़कर 22.15 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 21.36 करोड़ टन रहा था। *भाषा*

पीएनबी की 5 ग्रामीण बैंकों को दुरुस्त करने की तैयारी

अभिजित लेले
मुंबई, 15 मार्च

ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (यूबीआई) के साथ विलय के पहले पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) अपने 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कारोबार और रणनीति में बदलाव करने की ओर है, जिनका कुल मिलाकर 1.03 लाख करोड़ रुपये का कारोबार है।

पीएनबी अपने आरआरबी के लिए खाका तैयार करने हेतु सलाहकार की तलाश कर रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह कवायद डिजिटलीकरण व एनालिटिक्स जैसे मसलों के लिए हो रही है। कंसल्टेंसी या सलाहकार फर्म प्रमुख कारोबार की संभावनाओं का आकलन करेगी और समग्र परिचालन मॉडल की समीक्षा करेगी। सूत्रों ने कहा कि आरआरबी की आंतरिक टीम के साथ काम करने का मकसद उनके प्रदर्शन के अनुमान, बैंकिंग में सुधार है।

पीएनबी द्वारा चलाए जा रहे 5 आरआरबी पांच राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हैं और 93 जिलों में इनकी 3,350 शाखाएं हैं। इस साल एक अप्रैल को ओबीसी और यूबीआई का विलय पंजाब नैशनल बैंक में होना है। यह पीएनबी के लिए मिल जुलकर काम करने और भविष्य के कारोबार की क्षमता तैयार करने का एक अवसर है। एक बैंक अधिकारी ने कहा इसमें आरआरबी जैसी इकाइयों को जोड़ना शामिल है। इन आरआरबी का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा और वह अपने क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय जरूरतों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आकलन और योजना लागू करने की पूरी कवायद 21 महीनों तक दो चरणों में चलेगी। इस कवायद में लागत का अधिकतम इस्तेमाल, जोखिम प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, तकनीक और खरीद के माध्यम से मुनाफा बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट शामिल है। लागत का अधिकतम इस्तेमाल की संभावना है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों के आधार पर सलाहकार विभिन्न घटकों का विश्लेषण करेंगे।

दीर्घावधि बिजली खरीद समझौते पर होगा विचार

श्रेया जय
नई दिल्ली, 15 मार्च

राज्यों और बिजली उत्पादकों के बीच दीर्घावधि बिजली खरीद समझौते (पीपीए) जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकते हैं। बिजली मंत्रालय पीपीए पर फिर से काम करने की योजना बना रहा है, जिससे राज्यों द्वारा इन समझौतों का पालन न करने की स्थिति से निपटा जा सके।

बिजली खरीद समझौते 25-30 साल तक के लिए होते हैं। मंत्रालय 'नीति पत्र' तैयार कर रहा है, जिससे दीर्घावधि पीपीए का विकल्प मिल सके। इस नीति में लागत बढ़ने की समस्या के समाधान की भी कवायद होगी, जो पीपीए के तहत हुए अनुबंध के प्रावधानों में होते हैं।

ऊर्जा पर बनी संसद की स्थायी समिति के समक्ष बिजली मंत्रालय के सचिव ने कहा है, 'पीपीए बड़ा मसला है। बिजली उत्पादक दीर्घावधि पीपीए करते हैं क्योंकि अगर उत्पादकों ने दीर्घावधि बिजली खरीद समझौते नहीं किए हैं तो उन्हें कोई बैंक या वित्तीय संस्थान बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं करते हैं। लेकिन मसला यह है कि कीमतें तय हो जाती हैं, लागत बढ़ती रहती है और तकनीक पुरानी पड़ जाती है।'

उन्होंने कहा कि ज्यादातर सरकारी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बाजार की ताकतों या तकनीकी बदलाव के कारण लागत में बदलाव की पहेली में उलझी हैं, लेकिन वे पीपीए की शर्तों से बंधी हैं। सचिव ने कहा, 'बिजली के दाम बढ़ने के लिए डिस्कॉम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर शुल्क बढ़ता है तो यह डिस्कॉम पर है कि वे बिजली खरीदें या नहीं। अगर बिजली की लागत बढ़ती है तो उसका खामियाजा डिस्कॉम को क्यों भुगतना चाहिए?'

यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है, जब ताप बिजली क्षेत्र बिजली वितरण कंपनियों की ओर से भुगतान न किए जाने के संकट से जूझ रहा है। वहीं तमाम राज्य अक्षय ऊर्जा कंपनियों से अपने समझौतों पर फिर से बात कर रहे हैं और बिजली दरें घटाने को कह रहे हैं।

इस दशक के दौरान केरल को छोड़कर किसी भी राज्य ने निजी ताप बिजली उत्पादकों से बिजली खरीदने के लिए नया दीर्घावधि पीपीए नहीं किया है। निजी बिजली उत्पादकों से हुए मौजूदा पीपीए भी संकट के घेरे में हैं। देश में 40,000 मेगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र दबाव में हैं, जिनमें से 11,000 मेगावॉट के लिए बिजली खरीद समझौते नहीं हुए हैं या मामूली हुए हैं। इसकी वजह से भी बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बढ़ रही है। इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति निर्माता बिजली के लिए 'बाजार आधारित आर्थिक लेनदेन' पर विचार कर रहे हैं। इस विधि में बाजार में मांग के मुताबिक बिजली खरीद तय होती है। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) ने पूरी दुनिया के कुछ मॉडलों का अध्ययन किया है, जिससे बाजार आधारित बिजली आपूर्ति मॉडल को समर्थन मिलता है। अधिकारी ने कहा, 'राज्य इस तरह की पहल को इच्छुक होंगे। बाजार आधारित तरीका शुल्क की डिजाइन को दुरुस्त करेगा। इसी के मुताबिक कोयला आपूर्ति आवंटन में भी बदलाव होगा।' कुल ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी और ताप बिजली संयंत्रों का घटता परिचालन अनुपात देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गतिशील बाजार मिश्रित ऊर्जा के पक्ष में है।

ताप बिजली उत्पादन इकाइयों का औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) गिरा है। जनवरी में पीएलएफ 57.61 प्रतिशत रहा है, जो 5 साल का निचला स्तर है। 2019 के दौरान ज्यादातर महीनों में पीएलएफ में दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।

ताप बिजली इकाइयों का पीएलएफ वर्षों से घट रहा है, जिसकी एक वजह अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ना है। बहरहाल पीएलएफ में मौजूदा गिरावट बिजली की मांग में कमी की वजह से भी है। जनवरी दिसंबर 2019 में बिजली की मांग में बढ़ोतरी महज 0.28 प्रतिशत रही, जो 2014 के बाद की सबसे कम वृद्धि दर है।

स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, 'समिति ने जब बिजली की मांग में कमी की बात उठाई तो मंत्रालय ने कहा कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मांग व आपूर्ति के बीच अंतर मामूली रहा। मंत्रालय ने कहा कि मांग-आपूर्ति में अंतर पारेषण व वितरण नेटवर्क व उप पारेषण की कमी, वाणिज्यिक वजहों व राज्यों की वितरण कंपनियों की वित्तीय समस्या की वजह से हुआ है।'

अभी 25-30 साल के लिए होते हैं बिजली खरीद समझौते

- दीर्घावधि बिजली खरीद समझौते नहीं करने वाली उत्पादन कंपनियों को नहीं मिलता बैंकों से कर्ज
- राज्यों की खस्ताहाल वितरण कंपनियां इस समय उत्पादकों को नहीं कर पा रही हैं भुगतान
- कई राज्य कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा की दर फिर से तय करने के लिए बात
- अब सरकार बाजार आधारित बिजली दरों पर कर रही है विचार
- 2014 में मांग 0.28 प्रतिशत बढ़ी, जो 2014 के बाद सबसे कम

संक्षेप में

बिजली बचत के नियम अनिवार्य कर चुके हैं राज्य

वाणिज्यिक इमारतों को कम बिजली खपत वाला और ऊर्जा दक्ष बनाने की योजना ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को अब तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 15 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अनिवार्य कर चुके हैं। बीईई के महानिदेशक अभय बाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओड़िशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी इसे अनिवार्य कर चुके हैं। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और गोवा अधिसूचना जारी करने के अंतिम चरण में हैं। *भाषा*

एनसीएलएटी का अब चेन्नई में भी पीठ

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के एक पीठ का गठन चेन्नई में किया जा रहा है। यह पीठ दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखेगा। चेन्नई पीठ के गठन को अधिसूचित कर दिया है। यह 18 मार्च से काम करने लगेगा। *भाषा*

कर और कोविड ने बढ़ाई ट्रांसपोर्टरों की चिंता

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 15 मार्च

भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र को अब हाल में ईंधन पर बिक्री कर में बढ़ोतरी से भी जूझना पड़ेगा। विनिर्माण क्षेत्र और पूंजीगत वस्तु उद्योग में सुस्ती और कोविड 19 की वजह से यह क्षेत्र पहले से ही दबाव में है।

इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) के मुताबिक मांग कम होने और कच्चे तेल के वैश्विक दाम कम होने की वजह से ढुलाई के मुख्य मार्गों पर फरवरी में मालभाड़ा 2 से 3 प्रतिशत कम हुआ है। कम और मध्यम अवधि के हिसाब से ट्रांसपोर्टरों को अब एकमात्र उम्मीद रबी की फसल के बंपर उत्पादन से है, जो पहले ही शुरू हो चुका है।

सरकार ने शनिवार को ईंधन पर लगने वाला कर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जबकि कच्चे तेल के वैश्विक दाम में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे अगले कुछ दिनों में पेट्रोल व डीजल के दाम में तेजी से गिरावट की उम्मीद की जा रही है।

दिल्ली स्थित आईएफटीआरटी के सीनियर फेलो एसपी सिंह ने कहा, 'पिछले पखवाड़े कीमतों में जो कमी हुई है, उसका मुनाफा सरकार ने हड़प लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कीमतों में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी।' उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर पहले से ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ विपरीत चल रहा है, सरकार को कुछ दया दिखानी चाहिए थी।

ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी चिंता है कि वह कर बढ़ोतरी को ग्राहकों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि मांग कमजोर है। बल रोडवेज के बलमलकीत सिंह कहते हैं, 'चाहे वह बीमा हो, टोल हो, पंजीकरण हो या टायरों के दाम हर चीज की लागत बढ़ी है। मांग में कमी की वजह से इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला गया। बाजार में करीब 40 प्रतिशत ट्रक खड़े हो गए हैं।'

उन्होंने कहा, 'रबी की फसलों की खरीद शुरू हो गई है, इसी से एकमात्र उम्मीद है। आर्थिक मंदी से ढुलाई सुस्त पड़ी है और इसमें अगले 15 दिन में 25 से 30 प्रतिशत तेजी आने की उम्मीद है। 40 प्रतिशत ट्रक कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं। बंपर उत्पादन होने पर इस क्षेत्र को डूबने से बचाने में मदद मिलेगी।'

कृषि विभाग की ओर से हाल में जारी 2019-20 की प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 2,919.5 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले साल हुए 2,852.1 लाख टन उत्पादन की तुलना में 67.4 लाख टन ज्यादा है।

कृषि जिंसों के रिकॉर्ड उत्पादन का लाभ सिर्फ उन ट्रांसपोर्टरों को मिलेगा, जिनके ट्रक खुदरा क्षेत्र की ढुलाई करते हैं और एक से ज्यादा मार्गों पर चलते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय परमिट की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, 'जब तक विनिर्माण व अन्य प्रमुख क्षेत्रों में तेजी नहीं आती है तब तक हमारे क्षेत्र को राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।'

पड़ेगी मार

- जनवरी की तुलना में फरवरी में प्रमुख ढुलाई मार्गों पर मालभाड़े में 2 से 3 प्रतिशत कमी
- आर्थिक मंदी और कोविड-19 का पड़ा है बुरा असर
- अब केंद्र सरकार ने तेल पर बढ़ा दिया बिक्री कर
- रबी की फसल का बंपर उत्पादन एकमात्र सहारा

घट रहा है पेट्रोलियम सब्सिडी का बोझ

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 15 मार्च

पेट्रोलियम के अंतरराष्ट्रीय दाम कम होने और केरोसिन व रसोई गैस (एलपीजी) के दाम में चरणबद्ध बढ़ोतरी से तेल सब्सिडी के मोर्चे पर भारत सरकार को कुछ राहत मिल सकती है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) हर महीने रसोई गैस के दाम 4 रुपये बढ़ा रही हैं। एक ओएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हर महीने सिलिंडर के दाम पर सब्सिडी मामूली कम की जा रही है और 4 रुपये प्रति महीने दाम बढ़ रहे हैं।'

विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक एलपीजी और केरोसिन दोनों पर सब्सिडी का बोझ 35,000 करोड़ रुपये हो सकता है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये केरोसिन की हिस्सेदारी होगी। सरकार के पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक इस साल 33,686 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई है, जिसके एक हिस्से का इस्तेमाल पिछले साल की सब्सिडी की भरपाई के लिए होगा।

2018-19 में पेट्रोलियम सब्सिडी 37,397 करोड़ रुपये थी। 2017-18 की 25,552 करोड़ रुपये सब्सिडी की तुलना में इसमें तेज बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड के दाम शुक्रवार को 34.48 डॉलर प्रति बैरल रहे।

सरकारी ओएमसी को बाजार भाव से कम पर उत्पाद बेचने के एवज में सरकार सब्सिडी के पैसे देती है। वैश्विक बाजार में रसोई गैस के दाम के आधार पर सब्सिडी की राशि कम या ज्यादा होती है। अधिकारी ने कहा कि अगर दाम अगले कुछ महीने कम रहते हैं, जिसकी संभावना है, तो सब्सिडी कम होगी।

मार्च में सब्सिडी रहित रसोई गैस की कीमत में 53 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलिंडर की कमी की गई। अंतरराष्ट्रीय दाम में कमी के कारण दिल्ली में इसकी कीमत 858.50 रुपये प्रति सिलिंडर से घटकर 805.5 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में सब्सिडी का बोझ बढ़कर 291.48 रुपये हो गया, जो जनवरी में 153.86 रुपये प्रति सिलिंडर था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ग्राहकों की सब्सिडी 174.86 रुपये से बढ़कर 312.49 रुपये हो गई। इसी के मुताबिक सब्सिडी वाले सिलिंडर के दाम 560.14 रुपये से बढ़कर फरवरी में 567.02 रुपये हो गए क्योंकि कुछ बोझ ग्राहकों पर भी डाला गया।

सरकार हर साल उन लोगों को 12 सिलिंडर पर सब्सिडी देती है, जिनकी सालाना कमाई 10 लाख रुपये से कम है। जो लोग ज्यादा कमाते हैं या 12 सिलिंडर से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बगैर सब्सिडी वाले दाम का भुगतान करना होता है। अधिकारी ने कहा कि फरवरी में अंतरराष्ट्रीय दाम के आधार पर गैर सब्सिडी वाले सिलिंडर के दाम में 144.5 रुपये प्रति सिलिंडर की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई थी, जो मार्च में कम होगी।

इसकी वजह यह है कि जनवरी महीने में एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय दाम 448 डॉलर से बढ़कर 567 डॉलर प्रति टन हो गए थे। मार्च महीने में सिलिंडर के खुदरा दाम घटकर 534.1 रुपये रह गए। रसोई गैस के दाम औसत वैश्विक मूल्य के आधार पर अगले महीने के लिए तय होता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक रसोई गैस की खपत में जनवरी में 6.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और वित्त वर्ष 2019-20 में संचयी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही है।

बैंकों ने सख्त किए श्रम आधारित क्षेत्रों को कर्ज देने के नियम

नम्रता आचार्य और ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 15 मार्च

बैंकों ने श्रम आधारित कुछ क्षेत्रों को कर्ज देने के मानक कड़े कर दिए हैं। खासकर उन क्षेत्रों के मामलों में कड़ाई बरती गई है, जहां निचले स्तर पर मशीनीकरण कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि चाय, कपड़ा, सीसा, रत्न एवं आभूषण क्षेत्रों में कर्ज की वृद्धि दर में तेज गिरावट आई है।

चाय क्षेत्र में सालाना आधार पर कर्ज की वृद्धि दर 2017 के 32 प्रतिशत से घटकर 2019 में 3 प्रतिशत रह गई है। कपड़ा क्षेत्र में वृद्धि 2017 के 7.6 प्रतिशत से घटकर 2019 में 5.4 प्रतिशत रह गई है। वहीं रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में कर्ज की वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत वृद्धि से 11.1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इन क्षेत्रों में से ज्यादातर का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, और ऐसे में यह दुष्चक्र जैसा है। एक चाय कंपनी के मालिक ने कहा, 'यह एक आपदा है, बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'कुछ को छोड़कर ज्यादातर कंपनियां दबाव में हैं क्योंकि कीमतें स्थिर हैं और लागत बढ़ रही है। असम और उत्तर बंगाल के बीच कई चाय बागान बिकने को हैं, लेकिन उनका कोई खरीदार नहीं है।'

जूट उद्योग के मामले में तमाम बैंक अब मालिक के नाम के जमीन के मूल कागजात की मांग कर रहे हैं। समस्या यह है कि मिलों ने कई बार मालिकाना में बदलाव किया है और उनमें से कुछ के पास ही मूल कागजात हैं। इंडियन जूट मिल एसोशिएशन के पूर्व चेयरमैन और मिल मालिक संजय कजारिया ने कहा, 'ज्यादातर जूट मिल की जमीन अभी भी कंपनियों के नाम से हैं, जिन्हें 1950 में स्थापित किया गया और उनके मालिका न कई बार बदल चुके हैं। बैंक रजिस्ट्री दस्तावेज मानने से इनकार कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो कंपनी मिल चला रही है, उसका साफ-साफ नाम हो।'

उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल सरकार को लैंड टाइटल के नियमन को हरी झंडी और मंजूरी देने की जरूरत है, जिससे जूट मिलें जमीन गिरवी रखकर काम करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से से धन हासिल कर सकें।'

आभूषण फर्म नेमिचंद बामलवा के पार्टनर बछराज बामलवा ने कहा कि बैंक इस क्षेत्र को कर्ज देने में कुछ समय से सुस्ती दिखा रहे हैं और उन्होंने नीरव मोदी ऋण घोटाले के बाद से इस क्षेत्र को ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र की श्रेणी में डाल रखा है।

चर्म प्रसंस्करण इकाई के एक मालिक का कहना है कि बैंक इस क्षेत्र को कुछ समय से कर्ज देने में बहुत सुस्ती दिखा रहे हैं।

बैंकरों की अपनी वजहें हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के प्रमुख ने कहा, 'यह श्रम आधारित कंपनियां हैं, जिनमें मशीनीकरण कम हुआ है और वित्तीय हिसाब से कमजोर हैं। वे हमारे कर्ज देने के मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं।' उन्होंने कहा, 'इन क्षेत्रों में ज्यादातर प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्में हैं। बैंकों को कॉर्पोरेट इकाइयों के साथ सौदे आसान होते हैं।'

एक और सरकारी बैंक के प्रमुख ने कहा, 'कुल मिलाकर उन क्षेत्रों में मंदी है। चाय, कपड़ा आदि क्षेत्रों में कोई नया प्रमोटर नहीं आ रहा है। उद्योग को श्रम कानूनों से जूझना पड़ रहा है और वृद्धि सकारात्मक नहीं है। ऐसे में हम कारोबार के मामले में बांग्लादेश जैसे देशों से टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में हिस्सेदारी गंवा रहे हैं। साथ ही चाय जैसे क्षेत्रों में अगर कोई बड़ी कंपनी संकट से जूझ रही है, यह इस बात का संकेत है कि पूरा उद्योग दबाव में है।'

एक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर ने कहा, 'इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मांग नहीं है, जिनके लिए पहले बड़े कर्ज की घोषणा की गई थी। बहरहाल बैंक इन क्षेत्रों को कर्ज देने से भाग नहीं रहे हैं।'

मंदी में कुछ क्षेत्रों पर दोहरी मार

- ज्यादातर कंपनियां दबाव में हैं क्योंकि कीमतें स्थिर हैं और लागत बढ़ रही है
- नीरव मोदी ऋण घोटाले के बाद रत्न एवं आभूषण उद्योग को कर्ज का संकट
- जूट उद्योग से तमाम बैंक मांग रहे हैं जमीन के मूल कागजात
- चमड़ा उद्योग को भी कर्ज देने में पहले की तुलना में सुस्ती दिखा रहे हैं बैंक

नकदी का संकट

दिसंबर तक कुल बैंक कर्ज आवंटन में उद्योगवार सालाना वृद्धि दर (% बदलाव)

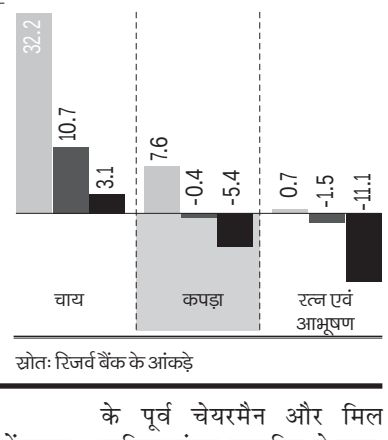

स्रोतः रिजर्व बैंक के आंकड़े

पेट्रोलियम सब्सिडी की स्थिति (करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	केरोसिन	रसोई गैस
2017-18	4,672	20,888
2018-19	5,950	31,447
2019-20*	4,058	29,628
2020-21**	3,176	35,605

*संशोधित अनुमान **बजट अनुमान

स्रोतः भारत सरकार

लक्ष्य की तुलना में रेलवे के विद्युतीकरण की रफ्तार सुस्त

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 15 मार्च

भारतीय रेलवे को दिसंबर 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 4 साल तक हर सालाना 9,700 किलोमीटर से ज्यादा विद्युतीकरण करना होगा। बहरहाल इस वित्त वर्ष में लक्ष्य हासिल होने की संभावना नहीं है। 2019-10 के लिए बजट में निर्धारित लक्ष्य का करीब 41 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल हुआ और इस दौरान महज 2,881 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण हो पाया है।

बहरहाल अब तक भारतीय रेल के महज 58 प्रतिशत ट्रैक का विद्युतीकरण हो सका है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी सिर्फ 6,000 किलोमीटर विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब यह है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले वर्षों का लक्ष्य बढ़ाना होगा।

जनवरी 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रेल के 93,902 किलोमीटर लंबे ट्रैक में से सिर्फ 58 प्रतिशत का विद्युतीकरण हो सका है। रेलवे की संसद की स्थायी समिति को जवाब देते हुए रेल मंत्रालय कहा है, '2018-19 और 2019-20 में हुए विद्युतीकरण की गति बरकरार रखी जाएगी और आने वाले वर्षों में शेष मार्गों का विद्युतीकरण कर दिसंबर 2023 तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।'

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रेलवे ने सबसे ज्यादा 5,276 किलोमीटर विद्युतीकरण किया था, जो इसके पहले के 4,087 किलोमीटर विद्युतीकरण की तुलना में 29 प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन चालू वित्त वर्ष में रफ्तार बहुत घट गई है। रेल बोर्ड ने संसद की समिति को आश्वस्त किया है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें कांट्रैक्ट प्रबंधन के लिए जोनल रेलवे को ज्यादा अधिकार दिया जाना शामिल है। इससे वे किसी भी मूल्य के ठेके के बारे में फैसला कर सकेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ठेकों के लिए ईपीसी मॉडल लाया गया है, जिससे तेजी से काम किया जा सके। विद्युतीकरण के क्षेत्र में भले ही प्रदर्शन खराब रहा है, ट्रैक के नवीकरण का काम अब तक के सबसे तेज रफ्तार से हो रहा है। जनवरी 2020 तक रेलवे ने 3,872 नवीकरण कर लिया है, जबकि पिछले साल 4,181 किलोमीटर पटरियों का नवीकरण किया गया था। समिति को दिए गए अपने जवाब में भारतीय रेल ने कहा है, '2018-19 के लिए 4,400 किलोमीटर ट्रैक नवीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 4,181 ट्रैक किलोमीटर का लक्ष्य हासिल किया गया, जो लक्ष्य से 4.98 किलोमीटर कम है। यह कमी मुख्य रूप से इसलिए आई कि सेल पटरियों की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई।' 2019-20 के दौरान 3,250 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर के नवीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जबकि जनवरी 2020 तक 3,872 किलोमीटर का नवीकरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य से 19 प्रतिशत ज्यादा है।

- 2023 तक संपूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य से सुस्त है काम
- 2019-20 में रखे गए बजट लक्ष्य का 41 प्रतिशत काम

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 24

कोविड-19 के बाद नीति

दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोविड-19 न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट है बल्कि इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसकी एक झलक हमें गत सप्ताह देखने को मिली जब वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी अस्थिरता उत्पन्न हो गई और लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित करने की कोशिश में लग गए। इसके चलते अमेरिकी सरकार का बॉन्ड प्रतिफल रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया। भारतीय बाजारों में भारी अस्थिरता आई। हालांकि फिलहाल पूरा ध्यान कोविड-19 के प्रसार को रोकने पर होना चाहिए लेकिन यह भी जरूरी है कि इस वायरस के आर्थिक असर को यथासंभव सीमित किया जाए। मौजूदा हालात की तुलना वर्ष 2008 के वित्तीय संकट से की जा रही है। यह बात पूरी तरह सही नहीं है। न केवल इस समस्या की प्रकृति पूरी तरह अलग है बल्कि मौजूदा दौर में वित्तीय और आर्थिक क्षेत्र में इससे निपटने की नीतिगत गुंजाइश भी बहुत सीमित है।

अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने भी नीतिगत दरों में कटौती की है। आगे और कटौती संभव है लेकिन यह जल्दी ही शून्य हो जाएगी जो एक अलग समस्या है। अन्य केंद्रीय बैंक मसलन यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की नीतिगत दरें पहले ही ऋणात्मक हैं। संकट की प्रकृति को देखते हुए फेडरल रिजर्व तथा अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा दी जा रही मौद्रिक शिथिलता ऋण की स्थिति सुधारने और नुकसान को सीमित करने में मदद करेगी।

फेडरल रिजर्व बाजार को अल्पावधि का मौद्रिक समर्थन भी दे रहा है। बहरहाल, यदि समस्या बरकरार रहती है और इसके चलते गहन वित्तीय संकट उत्पन्न होता है (यह संभव है) तब मौद्रिक नीति के प्रभाव की असल परीक्षा होगी। हो सकता है उस स्थिति में उच्च सार्वजनिक ऋण के बावजूद व्यापक राजकोषीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की 90 फीसदी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक ऋण का स्तर सन 2008 के स्तर से अधिक है। ऐसे हालात में आर्थिक नीति ऐसी हो सकती है जहां अप्रभावी मौद्रिक नीति, तेजी से बढ़ता सार्वजनिक ऋण और अनिश्चित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यह अहम है कि मौजूदा नीतिगत गुंजाइश का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाए। वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों का सहज कामकाज सुनिश्चित करना शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। जोखिम से बचाव ऋण की परिस्थितियों को कठिन बना सकती है। इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा राजकोषीय गुंजाइश का लक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।

भारत में जहां सरकार के पास अर्थव्यवस्था की सहायता करने की नीतिगत गुंजाइश नहीं है, वहीं केंद्रीय बैंक ने मुद्रा बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप करके अच्छा किया है। विदेशी विनिमय बाजार में नकदी सुनिश्चित करने के लिए खरीद बिक्री की घोषणा के अलावा उसने विदेशी बाजारों में भी हस्तक्षेप किया है। हालांकि मुद्रा अवमूल्यन कारोबारी क्षेत्रों में मददगार साबित होगा लेकिन अत्यधिक अस्थिरता से बचना ही बेहतर होगा। कई बाजार प्रतिभागियों को यह भी अपेक्षा है कि आरबीआई नीतिगत दरों में कटौती करेगा। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में उथलपुथल इस मोर्चे पर भी अनिश्चितता बढ़ा सकती है। इसके अलावा वित्तीय तंत्र की स्थिति भी लाभ को सीमित करेगा। दरें तय करने वाली समिति का निर्णय आज से लेकर 3 अप्रैल तक घटित होने वाली वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होगा। इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ाकर अच्छा किया है। इससे राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। वायरस की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतना समझदारी होगी। सरकार को संक्रमित लोगों के इलाज के लिए क्षमता विस्तार जारी रखना होगा। इससे आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी।

अजय मोहंती

भारतीय कुलीन वर्ग का समाजवाद

ज्योतिरादित्य सिंधिया का बिना एसी चलाए रेंज रोवर में चलने वाला बयान बताता है कि कैसे सामाजिक लोकलुभावनवाद का आत्मघाती पाखंड हमारी राष्ट्रीय विचारधारा बन गया है।

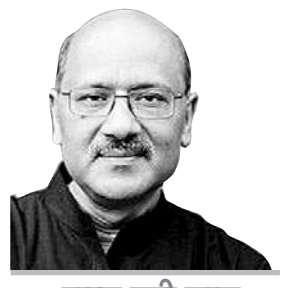

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में प्रवेश के बाद भोपाल में जोरदार स्वागत के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राज्य की राजनीति में वह और शिवराज सिंह चौहान ही ऐसे नेता हैं जो अपनी कारों में एयर कंडीशनर (एसी) नहीं चलाते। उनकी इस बात पर तंज कसे गए कि एक महाराजा ऐसा है जो रेंज रोवर से चलता है लेकिन वह एसी का प्रयोग नहीं करता। परंतु यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से वह भारतीय राजनीति की एक केंद्रीय हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं: राजनीति में सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध से लेकर शाही और ताकतवर उद्योगपति तक हर किसी को मितव्ययी और सादगीपसंद दिखना पड़ता है, भले ही वे किसी चायवाले जैसे नहीं दिखें।

बात करते हैं उस चाय वाले की जो भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित है। गीतकार प्रसून जोशी ने सन 2018 में लंदन में जब टेलीविजन पर प्रसारित एक बातचीत में उनसे यह कहा था कि इतनी फकीरी आप लाते कहां से हैं तो वह दरअसल भारतीय राजनीति की इसी हकीकत को रेखांकित कर रहे थे। वह कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री फकीर जैसी विनम्रता और सादगी कहां से लाते हैं? इसका सहज और तथ्यात्मक उत्तर होता- क्योंकि मैं फकीरी में पैदा हुआ, मैं इतना गरीब था कि मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचनी पड़ी। परंतु इससे मकसद पूरा नहीं होता। उद्देश्य था इस बात को सामने लाना कि इतना ताकतवर और लोकप्रिय व्यक्ति भी फकीर रह सकता है।

यहां तीन प्रासंगिक बातों का उल्लेख आवश्यक है। पहला, हम सत्ताधारी वर्ग से कुलीनता को चाहे जितना जोड़ें लेकिन सच यह है कि कोई सामंत या महाराजा अब तक शीर्ष पर नहीं पहुंचा। लेकिन कोई फकीर भी वहां तक नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। तीसरी बात, एक बार जब एक लोकप्रिय राजा (महाराजा नहीं) को चुना गया, उस वक्त उनका नारा था, 'राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है।' हम मांडा के राजा स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं।

क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति अमीरों या सामाजिक कुलीनों के लिए नहीं है? यह सच है कि बीते सात दशक में हमें ऐसे कुलीनों के तीन नाम तक नहीं मिलते जो इतने लोकप्रिय हों कि उन्हें किसी राज्य का नेतृत्व सौंपा जा सके। ऐसे दो नाम हैं पंजाब में अमरिंदर सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे (ज्योतिरादित्य की बुआ)। यह रिकॉर्ड खराब है लेकिन सामंती कुलीनों के लिए।

शेष के संदर्भ में एक सा सिलसिला नजर आता है जहां एक पीढ़ी धूल-मिट्टी से उभरती है और उसके वंशज नए सत्ताधारी कुलीन बन जाते हैं। नेहरू-गांधी परिवार कामगार वर्ग से नहीं था लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, बंसी लाल, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, करुणानिधि और ऐसे तमाम अन्य नेता थे। उनके वंशज सबसे बेहतर घड़िया और चश्मे पहनते हैं, सबसे अच्छी गाड़ियां चलाते हैं और बेहतरीन पेन रखते हैं। मोदी भी उनमें से एक हैं। हालांकि इन सभी को विनम्र दिखना होता है। जब वे यकीन से ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं कि वे अपनी कारों में एसी नहीं चलाते।

यह पाखंड हर दल में है। इसीलिए राहुल गांधी को दलित के घर खाते, मोटर साइकिल पर पीछे बैठे और ढाबे पर खाना खाते नजर आना चाहिए। उन्हें सवारी ट्रेन में सफर करते दिखना चाहिए। फिर क्या हुआ जो वे विदेशों में लंबी छुट्टियां बिताते हैं। कमल नाथ को चुनाव प्रचार के दौरान अपने हैरोड के बिस्किट सीट के बीच छिपा कर रखने चाहिए। ज्यादातर राजनीतिक राजकुमारों को दो तरह की जीवन शैली रखनी होती है। इसे दिन के राजनीतिक समय की पूर्वाह्न शैली और शाम को सामाजिक मेलमिलाप की अपराह्न शैली कह सकते हैं। ऐसे दोहरेपन से मेरा पहला साबका सन 1984 में ग्वालियर में स्वर्गीय माधव राव सिंधिया का चुनाव प्रचार कवर करते समय पड़ा। वह कांग्रेस का समाजवादी संदेश देते, हमें प्रोत्साहित करते कि हम उन्हें केवल भैया कहकर पुकारें लेकिन एक गांव से गुजरते समय उनकी आंख चमक उठी और उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने वहीं पहली बार बाघिन का शिकार किया था।

मतदाता इस सच्चाई से अवगत हैं लेकिन उन्हें दिखावा पसंद है। भारतीय राजनीति में नेता की विनम्रता कारगर हथियार है। इसलिए कह सकते हैं कि यहां डॉनल्ड ट्रंप जैसे नेता का चुना जाना मुश्किल है। हम बहुत अमीर लोगों पर ज्यादा यकीन नहीं करते।

हमारी राजनीति हमेशा से ऐसी ही थी। सरकारी स्कूलों की किताबों में जवाहरलाल नेहरू वाले अध्याय में पढ़ाया जाता है कि वह इतने अमीर परिवार से आते थे कि उनके कपड़े ड्राई क्लीन होने स्विट्जरलैंड जाते थे। परंतु असल जोर इस बात पर था कि उन्होंने यह आराम त्यागा और जेल गए।

इससे एक नया मॉडल सामने आया: भले ही आप साधारण परिवार से नहीं आते लेकिन यदि आपको राजनीति में करियर बनाना है तो आप अलग रूप अपना सकते हैं। यही कारण है कि आज भी नेहरू से नफरत करने वाले, खासकर हिंदू दक्षिणपंथी यूरोपियन कुलीनों के साथ पार्टी करते, धूम्रपान करते उनकी तस्वीरें प्रचारित करते हैं।

यकीनन शास्त्री असली जन नेता माने जाते थे। यह बात प्रसिद्ध है कि वह अपने पीछे परिवार के लिए एक पुरानी फिएट (बाद में प्रीमियर) कार और चुकाने के लिए सरकारी कर्ज छोड़ गए थे। कुलीनता के इसी आक्रामक विरोध के कारण बाद के दशकों के दौरान गरीबी को एक गुण के रूप में पेश किया गया। इससे आगे चलकर राष्ट्रीय विचारधारा प्रदूषित हुई।

मैंने संप्रग के शासन काल में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के निर्धनतावाद का मजाक उड़ाते हुए कहा था, 'गरीबी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप गरीब रहें।' शायद ऐसा करना मुझे रोमांचक लगा हो लेकिन इससे मेरा ही मजाक उड़ा। इसे चाहे जो नाम दिया जाए लेकिन एक खास किस्म का लोकलुभावनवाद आज हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है। मोदी से लेकर राहुल तक और मार्क्सवादियों से लेकर मोहन भागवत और ममता बनर्जी से लेकर दिलीप घोष तक सभी इस पर सहमत हैं। हर कोई चाहता है कि वह कम से कम अमीर नजर आए और अपनी राजनीति अमीरों को नुकसान पहुंचाने के भ्रम के इर्दगिर्द तैयार करें। इससे गरीबों को परपीड़ा का सुख मिलता है और यदाकदा कुछ हासिल हो जाता है। मोदी सरकार ने अत्यधिक अमीरों, पूंजीगत लाभ और लाभांश कर में इजाफे जैसे जो कदम उठाए हैं उससे बहुत कम राजस्व मिलेगा लेकिन जब अमीर रोते हैं और शिकायत करते हैं तो गरीबों को आनंद आता है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था में ऐसी एकरूपता देश को कहां ले जाएगी? ऐसे में आश्चर्य नहीं कि देश में दो ही धारणाएं बची हैं। सामाजिक विभाजन वाली या फिर व्यक्ति केंद्रित। नेहरू द्वारा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी के उदारवादियों की सफल विदाई को छह दशक बीत चुके हैं। ये लोग आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक थे और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के असल हिमायती। ऐसे में भारतीय राजनीति में जोर इस बात पर रहा है कि कौन अधिक समाजवादी दिख सकता है। आज मोदी इस मामले मे बाकियों से मीलों आगे हैं।

इसलिए आज भारत उस दशा में पहुंच गया है जिसका मखौल उड़ाते हुए अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर करार दिया था। सन 1970 की तरह यह दशक भी झूठी खुशहाली का है। नरसिंहराव-मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन सीमित समय के लिए हमने जो भी देखा वह एक भटकाव भर था।

मुझे सन 1990 की प्राग की एक घटना याद आती है। मेरे युवा टैक्सी चालक ने चेकोस्लोवाकिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की थी लेकिन उसके पास नौकरी नहीं थी। वह वामपंथ से अपनी घृणा के बारे में बहुत जुनून से बात कर रहा था। मैंने उसे याद दिलाया कि भारत में वामपंथ अच्छी स्थिति में है और उनके समर्थन वाली सरकार (वीपी सिंह की) सत्ता में है।

उसने मुझसे कहा, जब आपातकाल लगा और आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता छिनी तो आपने लड़कर उसे वापस लिया। परंतु आपने अपनी आर्थिक आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि आपने कभी इसका स्वाद नहीं चखा था। हम चेकवासी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की स्वतंत्रता के लिए लड़े।

चालक रहित वाहन तकनीक से बेहतर होगी यातायात प्रणाली

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

अल्फाबेट की सहायक कंपनी वायमो ने हाल में बाह्य स्रोतों से 2.25 अरब डॉलर जुटाए। कंपनी इस राशि का उपयोग चालक रहित कार बनाने वाली प्रणाली के लिए शोध कार्यों को बढ़ावा देने में करेगी।

वायमो का दावा है कि कंपनी द्वारा तैयार किए गए वाहनों ने सड़कों पर 3.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कंपनी कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में अपने कर्मचारियों के लिए और एरिजोना में सार्वजनिक सेवा के तौर पर रोबोट-टैक्सी हेलिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। एरिजोना प्रशासन ने एक गंभीर दुर्घटना होने के बाद उबर द्वारा चलाई जा रही चालक रहित कैब सेवा को बंद कर दिया था, हालांकि वायमो ने परिचालन जारी रखा।

वायमो ने जैगुआर लैंडरोवर के साथ भी साझेदारी की है जिसके तहत 20,000 इलेक्ट्रिक आई-पेस जैगुआर को स्वचालित कारों में बदला जाएगा कंपनी ने इन वाहनों पर अपने पांचवीं पीढ़ी के स्वचालित उपकरण 'वायमो ड्राइवर' का प्रदर्शन भी किया।

स्वचालित वाहन बनाना या किसी वाहन को स्वचालित प्रणाली में तब्दील करना शोध एवं विकास के स्तर पर काफी खर्चीला काम है। स्वचालित वाहन अपने आप में विशिष्ट होते हैं। उन्हें काफी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है जिससे उनके चारों ओर लगे उपकरण वाहन के लिए 'आंख तथा कान' का काम कर सकें। उन्हें हार्डवेयर तथा एआई तकनीक आधारित सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है जिससे आंकड़ों का रियल टाइम में प्रसंस्करण करके वाहन चलाने संबंधी निर्देश दिए जा सकें।

स्वचालित कार को विभिन्न तरह के संकेतों जैसे गाड़ी रोकना, दिशा विशेष में मुड़ना, गति सीमा आदि को पढ़ना होता है और लेन बदलने वाले जोन की पहचान करनी होती है। यह सब खराब मौसम परिस्थितियों या रात्रि के समय भी करना होगा। कार को अपने आस-पास तथा दूर चल रहे वाहनों की पहचान करके उनके प्रकार (कार, ट्रक आदि) की जांच करना, उसकी सापेक्ष गति मापना और अपनी गति तथा दिशा का चयन करना होगा।

इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को अपने उपकरणों की डिजाइनिंग तथा निर्माण स्वयं ही करना होता है। लाइट डिटेक्शन ऐंड रेंजिंग रडार (लीडार) इसी तरह का एक प्रमुख उपकरण है। यह लंबी दूरी के साथ ही कम दूरी की वस्तुओं का भी आसानी से पता लगा लेता है जिससे दूसरे वाहनों से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। कैमरा तथा रडार के साथ लीडार का उपयोग करने से स्वचालित कारों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए जरूरी लगभग सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

वायमो द्वारा लाई गई प्रणाली, 'द वायमो ड्राइवर' में लीडार के साथ ही कई कैमरे लगे हैं जिससे यह सभी दिशाओं में लंबी दूरी तक वस्तुओं तथा वाहनों का पता लगा सकता है। लंबी दूरी पर वस्तुओं की पहचान के लिए वाहन की छत पर लगे उपकरण 500 मीटर की दूरी से पैदल चलने तथा रुकने वाले चिह्न की पहचान कर सकते हैं। छोटी दूरी वाले उपकरण शहरों की भीड़भाड़ से बचने और पहाड़ी इलाकों में संभावित ब्लाइंड स्पॉट के लिए अधिक सटीकता उपलब्ध कराते हैं।

इस सभी उपकरणों से आने वाली जानकारियों का एक दूसरे से अधिव्यापन होता है। पहले प्रयोगशाला में सिमुलेटर पर मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म का परीक्षण किया जाता है और फिर सार्वजनिक सड़कों पर, जिससे वायमो ड्राइवर शहरों की जटिल सड़कों पर आसानी से चल सके।

शहरों में वाहन चलाते समय छोटी दूरी के आंकड़े काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। राजमार्गों पर लंबी दूरी की दृश्यता भी अहम भूमिका निभाती है। बड़े वाहनों या खड़ी की गई कार के लिए परिधीय दृष्टि भी जरूरी होती है। परिधीय कैमरे किसी कार के आगे चल रहे ट्रक को देख सकते हैं और वायमो ड्राइवर को बता सकते हैं कि क्या कार से आगे निकलना सुरक्षित होगा।

वायमो का दावा है कि उसके द्वारा विकसित लीडार उपकरण बिल्कुल पास की वस्तुओं के साथ ही 300 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। फिलहाल बेहतरीन लीडार उपकरणों की क्षमता 250 मीटर तक की ही है। साथ ही, वायमो द्वारा विकसित प्रणाली खराब मौसम, बारिश, बर्फ, चक्रवात और खराब सड़कों जैसी स्थितियों में भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है।

जब तक अधिकांश देश पूर्णतया स्वचालित कारों को, विशेषकर भीड़भाड़ वाले शहरी माहौल में परिचालन की अनुमति दें, इससे पहले इन्हें अभी लंबी दूरी तय करनी है। हालांकि, अभी भी चालक रहित बड़े ट्रकों को यूरोपीय संघ तथा अमेरिका में परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि आम कार चालक के मुकाबले स्वचालित कारें अधिक सुरक्षित होंगी। एआई प्रणाली लाल बत्ती को पार नहीं करेगी या दूसरे जोखिम भरे ऐसे कार्यों को अंजाम नहीं देगी जिससे दुर्घटना की आशंका बनती है। अगर सड़क पर चलने वाली प्रत्येक कार चालक रहित कार होगी और वे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगी तो दुर्घटनाओं में भारी कमी देखी जा सकती है।

लेकिन चालक रहित कारें गलतियां भी करती हैं। इनके चलते कई अहम दुर्घटनाएं हुई हैं और यहां जवाबदेही का भी सवाल उठता है। अगर स्वचालित कार से कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बीमाकर्ताओं को इस सवाल का जवाब खोजना होगा।

एक सवाल और भी है, लोकप्रिय 'ट्रॉली समस्या'। अर्थात, अगर कार किसी पहाड़ी इलाके में चल रही है और सामने बच्चों से भरी मिनी वैन से टक्कर होने वाली हो तो ऐसी स्थिति के लिए कार को किस तरह से तैयार किया जाएगा? क्या कार उन बच्चों को बचाने के लिए कार में सवार व्यक्ति को मारने का विकल्प चुनेगी?

आम वाहनों में भी नई प्रणालियों का उपयोग बढ़ रहा है जो अंतत: स्वचालित व्यवस्था की ओर ही लेकर जा रही हैं।

कानाफूसी

पुराने की कीमत

यह कतई जरूरी नहीं है कि कोई सत्ताधारी दल अपने पूर्ववर्ती द्वारा निर्मित हर चीज को खत्म ही कर दे। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस इसका उदाहरण है। बीकानेर के महाराज का यह निवास स्थान अब दिल्ली में राजस्थान सरकार की संपत्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र है। इस खूबसूरत इमारत का इस्तेमाल अब मुक्ताकाशी संगीत प्रस्तुतियों, कला और मूर्ति शिल्प की प्रदर्शनी लगाने जैसे कामों में होता है। परंतु हमेशा ऐसा नहीं था। वर्षों तक यहां सरकारी कार्यालय लगते थे बल्कि एक समय तो यहां राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का बस अड्डा भी बना दिया गया था। परंतु राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार आने के बाद यह बदल गया। इस इमारत का भव्य अतीत पुनर्जीवित किया गया। हर रविवार को यहां जैविक बाजार लगने लगा और यह इमारत राज्य सरकार के लिए राजस्व जुटाने का जरिया बन गई। दिसंबर 2018 में राजस्थान में सरकार बदलने के बाद शुरुआती रिपोर्ट ऐसी आईं जिनमें कहा गया कि इसे दोबारा बस अड्डे में बदला जा सकता है। परंतु कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दखल के बाद अब यह इमारत दोबारा अपने पुराने गौरव को हासिल कर रही है और यहां नए सिरे से आयोजन किए जा रहे हैं। भाजपा को इससे सबक लेने की जरूरत है। प्रगति मैदान के बीचोबीच बने खूबसूरत ढांचे को सेंट्रल विस्टा के विकास के लिए मोदी सरकार ने ढहा दिया।

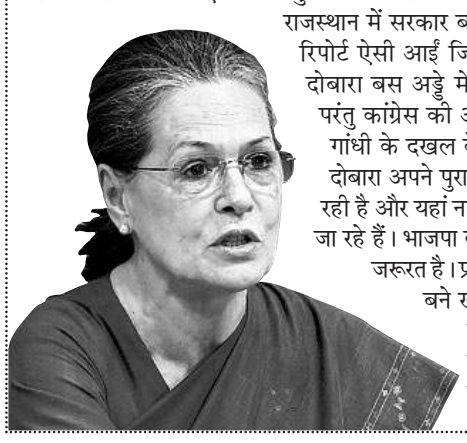

आपका पक्ष

अंधविश्वास का महिमामंडन बंद हो

बड़े राजनेता या सेलेब्रिटी सार्वजनिक मंचों पर ऐसे दावे करते या अनुभव साझा करते देखे जाते हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। कुछ समय पहले एक राज्य के गृहमंत्री को एक तांत्रिक से मधुमेह का इलाज कराते देखा जा चुका है। ऐसे मामलों में स्थानीय मीडिया का रवैया भी चौंकाने वाला रहता है। एक ओर जहां हम अंधविश्वास को खत्म करने के लिए अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर जनता की नजर में आदर्श स्थान रखने वाले लोगों का ऐसा सार्वजनिक व्यवहार सारे अभियान को खत्म करता दिखता है। अंधविश्वास आधारित अफवाहों की वजह से आए दिन हिंसा तथा हत्या की खबरें आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास संबंधित गतिविधियों में केवल अशिक्षित या कम शिक्षित लोग ही शामिल होते हैं। जिम्मेदार पदों पर आसीन लोग अक्सर अंधविश्वास पर वक्तव्य देते नजर आ जाते हैं। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रियलिटी कार्यक्रमों, विभिन्न सरकारी एवं निजी विज्ञापनों में

अंधविश्वास आधारित अफवाहों की वजह से आए दिन हिंसा तथा हत्या की खबरें आती रहती हैं

अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। भ्रामक टीवी कार्यक्रमों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। देश का संविधान भी नागरिकों को वैज्ञानिक सोच अपनाने को कहता है। आज विज्ञान का दौर है और लोगों को अंधविश्वासपूर्ण कृत्यों को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तभी हमारा देश विकास के पथ पर तेज गति से दौड़ पाएगा।

ऋषभ देव पांडेय, जशपुर

वायरस से मंदी की ओर बढ़ता भारत

चीन के वुहान शहर से फैले कोरोनावायरस के कारण वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे रही है। कई देशों में सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। भारत में भी कई शहरों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दे रही हैं। कई वस्तुओं की खरीद पर असर पड़ा है। देश के आयात-निर्यात पर भी व्यापक असर पड़ा है। पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह ठप होने के कगार पर पहुंच चुका है। भारत से कई देशों में हवाई यात्रा रद्द कर दी गई है। वीजा रद्द किए जा रहे हैं। इस वायरस के कारण पूरे विश्व में जहां डर का माहौल बन रहा है, वहीं कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। शेयर बाजार लगातार गिर रहे हैं। इससे दुनिया वैश्विक मंदी की ओर बढ़ रही है। सार्वजनिक जगहों के बंद होने से वहां काम कर रहे कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों की आय पर असर पड़ेगा। उत्पादों की बिक्री कम होने पर कंपनियों को घाटा पहुंचेगा जिसका सीधा असर उस कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ेगा। भारत के कई राज्यों में कुछ लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इससे उन राज्यों में सतर्कता तो बरती जा रही है लेकिन लोगों में भय का माहौल भी है। सरकार को इस वायरस से बचाव के सभी उपाय करने चाहिए तथा लोगों को नुकसान नहीं हो ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगर कोई कंपनी बंद होती है तो उस कंपनी में काम करने वाले कर्मियों के वेतन पर असर पड़ेगा। इससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। जब तक कोरोना का प्रकोप जारी है असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अत: सरकार को इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

आभा कुमारी, गाजियाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कायम करें जनता का भरोसा, सभी हितधारक उठाएं कदम

दीपक शर्मा

सरकारी नीतियां हों स्पष्ट

पहले औद्योगिक घरानों के स्वामित्व वाले निजी बैंक मुनाफा और सेवा दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते थे। लेकिन आम जनता की इन बैंकों तक पहुंच नहीं थी। निस्संदेह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आम जनता की पहुंच इन बैंकों तक हुई। लेकिन शहरों से लेकर गांव, कस्बों तक शाखा स्थापना व्यय और नई भर्तियों के कारण खर्चे बढ़ने से बैंकों का लाभ कम होने लगा। साथ ही लाखों की वसूली न होने के कारण लोगों का बैंकों से विश्वास भी उठने लगा। बैंकों पर आम जनता का भरोसा कायम करने के लिए सरकारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए।

अनिल कोथुलकर

इंदौर, मध्य प्रदेश

दुविधाग्रस्त हुए जमाकर्ता

अब लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि बैंकों में जमा उनका पैसा कितना सुरक्षित है। घोटालों में घिरी बैंकों के ग्राहक तो परेशान हैं ही साथ में दूसरे बैंक के खाताधारक भी सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारा पैसा कितना सुरक्षित है यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों में बैंकों के डूबने की वजह से ग्राहक खुद को लाचार और बेबस पा रहे हैं। हालांकि भारत में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बैंक डूबा हो। अब सरकार को जनता को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है।

साक्षी पांडेय

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

सकारात्मक कदमों और ईमानदार प्रयासों से बहाल हो भरोसा

देश के बैंकिंग क्षेत्र की बुनियाद भरोसा है। येस बैंक मामले में सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इससे ग्राहकों में बैंकों के प्रति विश्वास घट गया। अगर इसे लेकर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर दूसरे निजी बैंकों पर भी पड़ेगा। इसका संकेत कुछ छोटे बैंकों में भी दिखता है जो लोगों के बीच अपनी वित्तीय सेहत तथा स्थिरता को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को भी आगे आकर आम जनता को यह कहना पड़ा कि बैंकों में धन सुरक्षित है और राज्य सरकारों से भी जल्दबाजी में राशि नहीं निकालने की बात कही। किसी दूसरी गतिविधियों से इतर, बैंकिंग बहुत हद तक ग्राहकों पर निर्भर है और उनके भरोसे तथा ईमानदारी पर ही चलती है। बेसल 2 टीयर 1 बॉन्ड पर ब्याज देने में विफल होने तथा निकासी पर 50,000 रुपये प्रतिमाह की सीमा लगने से निवेशक तथा जमाकर्ता, दोनों के भरोसे को ठेस पहुंची है। उधारी तथा जमाएं बैंक के वित्त का अहम जरिया है। इस संबंध में कमजोर फ्रैंचाइजी बिगड़ती तरलता के जोखिम का वहन करती है जिसके चलते एसेट-देयता में अंतर से विफलता की संभावना बढ़ जाती है। ग्राहकों में भरोसा बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घ अवधि की योजनाएं तैयार करनी होंगी। अपने धन की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता को जल्द से जल्द दूर करना होगा। एसबीआई द्वारा तत्काल कदम बढ़ाने की घोषणा करना अच्छा कदम था। हालांकि लोग अब प्रदर्शन पर भरोसा करते हैं। इसके लिए भरोसेमंद अधिकारियों तथा बोर्ड सदस्यों द्वारा सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। बैंकिंग प्रणाली के कामकाज तथा बड़े पैमाने पर समाज के लिए बैंकों एवं दूसरे वित्तीय संस्थानों में विश्वास अहम है। विश्वास बहाल करने के लिए बैंक-ग्राहक संबंधों में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह केवल ग्राहक हित में सकारात्मक कार्यों तथा ईमानदार व्यवहार द्वारा सभी हितधारकों तक पहुंच बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

बातचीत: वीरेश्वर तोमर

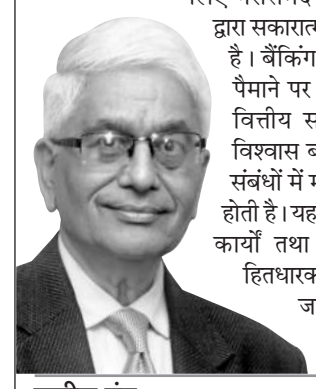

सुनील पंत

मुख्य महाप्रबंधक (सेवानिवृत) भारतीय स्टेट बैंक

निष्पक्ष रेटिंग एजेंसी, बीमा सुविधाओं से बढ़ेगा भरोसा

किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम उसकी अर्थव्यवस्था की नींव होता है। बैंकों को ज्यादा नुकसान होने से देश के प्रत्येक नागरिक पर असर होता है, क्योंकि बैंकों में जमा राशि देश के उन्हीं नागरिकों की होती है। लोग बचत करके बैंकों में छोटा-बड़ा निवेश करते हैं। लेकिन पीएमसी बैंक के घोटाले के बाद निजी क्षेत्र के एक बड़े बैंक येस बैंक के घोटाले ने ग्राहकों में बैंकों को लेकर अविश्वास की भावना पैदा कर दी है। ग्राहकों का ये अविश्वास बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं हैं क्योंकि यदि ग्राहक बैंकों में अपना पैसा नहीं रखेंगे तो बैंक ऋण देने के लिय धन की व्यवस्था कहां से करेंगे। येस बैंक का ये घोटाला सीधे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी कार्य तथा येस बैंक बोर्ड के गवर्नन्स की विफलता है। हालांकि आरबीआई तथा वित्त मंत्रालय द्वारा तत्काल कार्यवाही करके बैंक के ग्राहकों को भरोसा देने की कोशिश की गई कि उनका जमा धन बैंक में सुरक्षित है और सरकार बैंक को डूबने नहीं देगी। कुछ समय बाद ही भारतीय स्टेट बैंक द्वारा येस बैंक में निवेश करने की घोषणा से भी ग्राहकों को मामूली राहत जरूर मिली होगी। हालांकि प्रभावी कदम उठाने के साथ ही ऐसे सभी लोगों पर सख्त कार्यवाही की जरूरत है जिनके कारण बैंक की ये हालत हुई है, जिसमें आरबीआई, प्रवर्तक, बोर्ड सदस्य, लेखाकार या बैंक के अधिकारी ही क्यों न हों जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो सके। सरकार द्वारा बैंक के ग्राहकों के लिए पहले 1 लाख रुपये तक की जमा राशि की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई थी जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे भी बैंकों में ग्राहकों के विश्वास में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार को एक नई बीमा योजना भी शुरू करनी चाहिए जिसमें 5 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि वाले ग्राहकों के पास अपनी राशि का बीमा कराने का विकल्प मौजूद हो। वहीं, सरकार को आरबीआई की मदद से एक रेटिंग एजेंसी बनानी चाहिए जो समय समय पर बैंकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंकों की रेटिंग जारी करे जिससे ग्राहकों को पता चलता रहे कि जिस बैंक में उनकी धनराशि रखी हुई है वह बैंक और उनकी जमा धनराशि कितनी सुरक्षित है।

बातचीत: वीरेश्वर तोमर

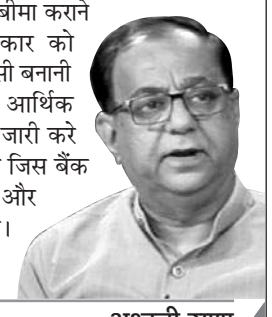

अश्वनी राणा

पूर्व महासचिव, नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स

नियामक तंत्र को मजबूत बनाएं

बड़े बड़े कर्जदारों द्वारा देश के बैंको के हजारों रुपये बिना चुकाए विदेश भाग जाने, कर्जदारों के दिवालिया हो जाने की पृष्ठभूमि में जनता में बैंकों के प्रति विश्वास में भारी कमी आई है। यही कारण है कि बहुत से लोग बैंकों में जमा अपनी पूंजी निकाल कर घर पर ही रखना चाह रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग में लोगों के विश्वास को पुन: स्थापित करने के लिए सरकारी व निजी बैंकों के लिए मौजूदा नियामक तंत्र को मजबूत बनाना होगा। बैंक गैर जिम्मेदाराना तरीके से जानबूझकर चूककर्ता को भारी मात्र में कर्ज देने से परहेज करें। इसके लिए सुस्पष्ट दिशानिर्देश जारी करते हुए बैंककर्मियों की जवाबदेही तय करनी होगी ताकि बैंक अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद ही ऋण जारी करने की कार्यवाही करें।

ऋषभ देव पाण्डेय

पामगढ़, छत्तीसगढ़

बैंकों की देख रेख का दायरा बढ़े

बीते समय में बैंक घोटालों, कर्ज लेकर उद्योगपतियों के विदेश भागने से बैंकों की हालत पस्त है और ग्राहकों का बैंक पर से भरोसा टूट रहा है। हालांकि आरबीआई ने हस्तक्षेप कर ग्राहकों को पैसा वापसी का भरोसा दिलाया है और कारोबार में फेरबदल की पहल कर बैंकों की स्थिति में सुधार और समाधान के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन इनकी गति काफी धीमी है। राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में ग्राहकों का बैंकिंग पर भरोसा कायम करने के लिए आरबीआई और वित्त मंत्रालय को अपनी देखरेख का दायरा बढ़ाकर कार्य करने की गति में आने वाले रोड़ों को हटाना होगा। इससे जमाकर्ताओं बैंक पर विश्वास बढ़ेगा।

प्रदीप माथुर

अलवर,राजस्थान

जिम्मेदारी के निर्धारण से मिलेगा हल

लोगों की जमा राशि की सुरक्षा और उचित समय पर उसकी उपलब्धता बैंकों की प्रमुख जिम्मेदारी है। अचानक से बैंकों के बंद या एक बैंक का दूसरे में विलय हो जाने से जमाकर्ताओं पर चिंता के बादल छा जाते हैं, इसलिए सरकार और रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी हैं कि इनकी उचित निगरानी हो तथा समय-समय पर नए कानून आवश्यकतानुसार बनाए जाएं। बैंक क्यों बंद हो रहे हैं? एनपीए क्यों बढ़ रहा हैं? इन सभी प्रश्नों की जांच हो तथा निष्कर्षों पर कार्रवाई की जाए। डिजिटल युग में वित्तीय संस्थाओं का सुचारू रूप से कार्य करना अपरिहार्य है। बैंक की निगरानी में ढिलाई से आम जनता का विश्वास टूटेगा। इसलिए सरकार को जिम्मेदारी का निर्धारण करना होगा।

पंकज चौहान

बैतूल, मध्यप्रदेश

न उठने पाए लोगों का भरोसा

महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक और उसके बाद येस बैंक में आए संकट के बाद ग्राहकों में बैंक में रुपया रखने को लेकर बड़ी घबराहट है। बैंक के विफल होने की स्थिति में ग्राहक को बड़ी राशि होने पर एक लाख की गारंटी थी। हालांकि, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम से बैंकों को निकलने वाली राशि पर विराम लगा है। अब बैंकों की सेहत में भी सुधार होगा। अब लोगों का निजी की अपेक्षा सरकारी बैंकों पर ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। बैंकों से बड़े उद्योगपति को दिए जाने वाले बड़े कर्ज की वापसी की शर्तें ऐसी बनाई जाए जिससे कि बैंकों का भी पैसा न मरे।

दिनेश गुप्ता

पिलखुवा, उत्तर प्रदेश

रिजर्व बैंक की नीति भी जिम्मेदार

निजी बैंकों के डूबते ऋणों के पीछे रिजर्व बैंक भी कम जिम्मेदार नहीं है। जब सरकारी बैंक एनपीए से जूझ रहे थे, तब रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने कहा था कि सरकारी बैंकों के प्रबंधन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण सीमित है, जबकि निजी बैंकों पर रिजर्व बैंक बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकता है। लेकिन आज येस बैंक के प्रबंधन को ही उसके संकट का दोषी कह रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक की वह नीति जिम्मेदार है, जिसके अनुसार निजी बैंकों के प्रमोटरों पर यह शर्त लगाई गई कि वे एक निश्चित समय सीमा में बैंकों में अपनी अंशधारिता यानी मालकियत को शून्य करें। येस बैंक के मालिक राणा कपूर की अंशधारिता को घटाने के लिए मजबूर किया गया। यदि प्रमोटरों की अंशधारिता को शून्य नहीं किया गया होता, तो बैंक के स्वास्थ्य में उनकी रुचि बनी रहती और बैंक इस हालत में नहीं पहुंचता।

रितेश कुमार उपाध्याय

संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश

भ्रष्ट लोगों में हो कानून का डर

बैंकिंग के प्रति लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए प्रावधानों की कमी नहीं है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, जमाकर्ताओं की जमा का बीमा जैसे कई प्रावधान विद्यमान हैं लेकिन उन प्रावधानों के क्रियान्वयन में लापरवाही जैसे वाकयों का आना निश्चित रूप से जमाकर्ताओं के भरोसे पर कुठाराघात करता है। हालिया येस बैंक, पीएमसी बैंक जैसे घटनाओं में नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से ज्यादा ऋण का वितरण, शीर्ष अधिकारियों की अनियमितता ही बैंकिंग में दाग लगाने वाले कारकों में रहे हैं। जरुरत जिम्मेवार लोगों को सख्त सजा देकर, नियमन को अधिक दुरुस्त कर आम जनमानस में बैंकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बनाया जाए।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी

उज्जैन, मध्य प्रदेश

विश्वास बहाली को उठाएं कदम

बैंकों के घोटाले सामने आने के बाद लोगों का बैंकिंग प्रणाली से भरोसा उठता जा रहा है। अत: सर्वप्रथम, बैंक में जमा राशि की गारंटी या बीमा बढ़ाने पर सरकार को गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेने होंगे। गत वर्ष सितंबर में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने 'भरोसा बचत खाता' शुरू करने की घोषणा की थी, जो बैंकिंग सेवाओं से दूर रहे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सरकार के वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में योगदान देगा। यदि ग्राहक सरकारी सब्सिडी अपने भरोसा खाता में प्राप्त करेंगे या इसमें नगद पैसे जमा करेंगे, तो उन्हें कैशबैक का लाभ भी मिलेगा और 5 लाख रुपये का नि:शुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त होगा। बाजार के शोध के बाद डिजाइन किए गए इस प्रकार के अभिनव खातों को प्रोत्साहन देने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ाया जा सकता है।

सुधीर कुमार सोमानी

देवास, मध्य प्रदेश

कड़े कानून से ही बढ़ेगा भरोसा

ग्राहकों एवं बैंकों में अन्योनाश्रय संबंध है। दोनों ही एक दुसरे पर निर्भर हैं। बैंक जमा राशि को कर्ज के रूप में व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपना धंधा चालाने के लिए देते हैं और उनसे प्राप्त ब्याज को अपने जमाकर्ताओं में वितरित करते हैं। बैंक सेवाएं सब जगह स्थापित है किंतु राजनैतिक दबाव और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक अपनी जमा राशियों को ऐसे ऐसे लोगों और उद्योगों को आंख बंद कर बांट रहे हैं, जो अपना कर्ज चुकाने में आनाकानी करते हैं और इस कारण बैंकों की पूंजी हड़पी जा रही है। लिहाजा जमाकर्ताओं का विश्वास बैंकों से उठ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे कड़े कानून बनाये जिससे बैंक की जमा राशियां सुरक्षित हाथों में पहुंचे और आमजन का विश्वास बैंकों पर स्थापित हो।

हरमोहन नीमा

इंदौर, मध्य प्रदेश

जिम्मेदारी से मिलेगा समाधान

बैंकिंग सेक्टर में हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, उसने जमाकर्ताओं की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। पीएमसी बैंक के बाद येस बैंक का लड़खड़ा कर गिर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई वर्षों से इन बैंकों ने आरबीआई से कई सारी जानकारियां छिपाई है जिसका नुकसान इन बैंकों के ग्राहक भुगत रहे हैं। साल 2017 में ही आरबीआई के पास जानकारी थी कि इन बैंकों ने कई हजार करोड़ के खराब कर्ज दे रखें हैं। अगर समय रहते इन बैंकों के आला प्रबंध अधिकारियों के पास मौजूद सारे रिकॉर्ड खंगाल कर कार्रवाई की जाती तो आज अन्य बैंको द्वारा शेयर खरीद कर जमाकर्ताओं का विश्वास दोबारा बहाल करने की नौबत नहीं आती। वित्त मंत्रालय ने भी अगर पिछली सरकार की खामियां गिनाने के बजाय समय रहते मोर्चा संभाला होता तो निजी बैंकों की खस्ता हालत नहीं होती।

उद्देश कुमार

मणिपाल

जनता का भरोसा करें कायम

इन दिनों बैंक अपनी साख खोते जा रहे हैं जिसका कारण आज के कुछेक बैंक प्रणाली को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से फर्जीवाड़े पर ही इसका ताना बाना बुना हुआ है। छोटे कर्ज के लिए ढेरों औपचारिकताएं हैं पर नीरव मोदी, विजय माल्या या राणा कपूर जैसे तथाकथित सक्षम लोगों के लिए कोई औपचारिकता ही नहीं हैं। हाल फिलहाल स्थिति को देखते हुए सिर्फ विपक्ष पर सारे दोष मढ़कर वर्तमान सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। येस बैंक के मामले ने एक सामान्य जमाकर्ता को भी सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या वह बैंकों पर भरोसा कर सकता है। अगर जनता के भरोसे को जल्द ही सुनिश्चित नहीं किया गया तो बैंकिंग से ही लोगों का भरोसा उठ जाएगा।

डॉ रसिकेश 'नवजात'

जौनपुर,उत्तर प्रदेश

एनपीए पर लगाम जरूरी

यदि हमारी बैंकिंग प्रणाली संकट ग्रस्त हो जाए तो पूंजी के प्रवाह को बनाए रखना कठिन होगा और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गत दिनों येस बैंक के संकट ने बैंक ग्राहकों को परेशान कर दिया। उनका अपनी जमा हेतु चिंतित होना स्वाभाविक था। इस वर्ष आम बजट में जमा की सुरक्षा के लिए बीमा सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह स्वागतयोग्य निर्णय है। इससे जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ेगा। एनपीए पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इससे बैंक की साख बनेगी और जमाकर्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा।

डॉ एम एस सिद्दीकी

फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

अनुपात पैमाना होना चाहिए

जिस प्रकार येस बैंक के हालात हुए हैं उसे देखकर आम आदमी का धीरे-धीरे बैंकिंग प्रणाली पर से विश्वास उठता नजर आ रहा है जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा होने पर पूंजी का प्रवाह या इसकी पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आम जनता का बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास जमा रहे इसके लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ ऐसी नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है जो जमाकर्ताओं की जमा पूंजी की गारंटी प्रदान कर सके। न्यूनतम 5 लाख की जगह अगर बैंक जमा राशि का अनुपात निर्धारित कर इस बात की गारंटी प्रदान कर सकें कि एक निर्धारित अनुपात तक आपका पैसा सुरक्षित रहेगा।

डॉ. महेश बंसिया

उज्जैन, मध्य प्रदेश

पुरस्कृत पत्र

अटके कर्ज की वापसी का उपाय करें

बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के विश्वास को बहाल करने के लिए दिए गए कर्ज की वापसी के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण बैंकों के एनपीए लगातार बढ़ते चले जाते हैं जो कालांतर में बैंकों के डूबने के कारण बनते हैं। ऐसे एनपीए बनाने वाले जानबूझकर चूककर्ता को समय रहते चिह्नित कर अब तक दिए गए कर्ज को वसूलने की वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। कर्ज वसूलने के लिए स्थापित निकाय को और अधिक अधिकार देने की जरूरत है ताकि वह समयबद्ध तरीके से उत्पादक कार्य कर सके। कर्ज वसूलने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का आम जनता में पर्याप्त प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत है ताकि आम जन तक यह संदेश पहुंचे कि उनके पैसे का दुरुपयोग को रोकने में सरकार पूरी तरह सक्षम हैं। भ्रष्ट बैंक अधिकारियों को दंडित करने के साथ ही कर्मठ अधिकारियों को संरक्षण मिले।

1

अशोक सिंह यादव
जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

व्यापक सुधार की जरूरत

हाल फिलहाल बैंकिंग क्षेत्र में कई घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए जिससे बैंको की साख गिरी है और जमाकर्ताओं का भरोसा उठा है। चूंकि इसका फिलहाल कोई विकल्प नहीं है लिहाजा जमाकर्ता भी पशोपेश में हैं। वैसे बैंकों को सिर्फ भरोसा ही नहीं अपने व्यवहार को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बैंकों के काम पहले की अपेक्षा बढ़े हैं और कोर बैंकिंग ने बैंक को व्यापक बना दिया है पर बैंक में कार्यरत कर्मचारियों और अफसरों पर इसका तनाव और दबाव साफ देखा जा सकता है। जमाकर्ताओं का भरोसा फिर से बैंकिंग की तरफ बढ़े। इसके लिए बैंकों को नए प्रबंध विधियों को अपनाने की जरूरत है। मानवीय संवेदनाओं को तरजीह देना होगा।

डॉ. दीप्ति विश्वास
भोपाल, मध्य प्रदेश

बैंकिंग कार्यप्रणाली में हो पूर्ण सुधार

पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते एनपीए, पीएमसी, येस बैंक तथा अन्य बैंकों के आर्थिक संकट ने ग्राहकों के मन में भय के साथ ही आक्रोश भी उत्पन्न किया है कि उसकी बचत बैंकों में सुरक्षित है भी या नहीं। बैंकिंग प्रणाली की मजबूती सरकार एवं स्वयं केंद्रीय बैंक पर भी निर्भर करती है। सर्वप्रथम रिजर्व बैंक में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, उसे स्वायत्तशासी संस्था के रूप में निष्पक्ष रूप से देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने दिया जाए। राष्ट्रीयकृत, निजी, सहकारी सभी बैंकों का वार्षिक लेखा परीक्षण यदि कैग से करवाई जाए तो बैंकों के आर्थिक संकट की संभावना कम होगी। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति मसलन किसान कर्जमाफी, मुद्रा योजना आदि के लिये बैंकिंग क्षेत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

डॉ आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

निगरानी के जरिये रोकें फर्जीवाड़ा

आए दिन बैंक की गिरती साख ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि कैसे लोगों को बैंकिंग पर भरोसा बना रहे। पहली बात सरकार को कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि आम जन पर उसका क्या प्रभाव होगा। नोटबंदी एक फ्लॉप शो था जो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। पर इसने आम लोगों में उहापोह की स्थिति जरूर पैदा कर दी। पहले के मुकाबले ढेर सारे बैंक हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा के कारण ये गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए बैंकों की संख्या घटाई जाए और जितने भी बैंक हों उनकी पूरी निगरानी हो जिससे कोई भी फर्जीवाड़ा न होने पाए। यदि बैंकों पर जमाकर्ताओं का भरोसा डगमगाया तो यह अर्थव्यवस्था के लिए मुफीद नहीं होगा।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

व्यवस्था को बनाएं दुरुस्त

बैंक घोटालों के सामने आने के बाद अब लोग सरकार और रिर्जव बैंक को भी बैंकों की कार्यप्रणाली के लिए दोषी मानने और शक की नजर से देखने पर मजबूर हैं। बैंक घोटाले ने तो देश की सारी बैंकिग व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। बेशक बैंकों की गड़बड़ी-घोटाले की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन यहां सवाल तो यह खड़ा होता है कि जब सभी बैंक रिजर्व बैंक के अधीन हैं तो फिर ये घोटाले आखिर हो कैसे गए? क्या बैंकों की कार्यप्रणाली की समय-समय पर जांच नहीं की जाती? अब यह देखना होगा कि रिजर्व बैंक, बैंकों की कार्यप्रणाली के लिए कितना गंभीर होता है, जिससे भविष्य यह नौबत नहीं आए।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -
महामारी से निपटने को कितने तैयार हम?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

सुरक्षित लेनदार का दावा कर विभाग से ऊपर

एमजे एंटनी

अदालत से

उच्चतम न्यायालय का कहना है कि अगर कोई संपत्ति ऋण वसूली पंचाट के निर्देश पर पहले ही बिक चुकी है तो कर विभाग के अधिकारी उस पर प्राथमिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कनेक्टवेल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ वाद में यह व्यवस्था दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी कानून के द्वारा क्राउन ऋण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तब तक किसी सुरक्षित लेनदार के बकाये को क्राउन ऋण पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्राउन ऋण का मतलब सरकार का बकाया होता है जो सरकार को दूसरे लेनदारों पर प्राथमिकता का अधिकार देता है। इस मामले में एक कंपन ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) से एक भूखंड खरीदने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया था। इस ऋण का भुगतान नहीं किया गया। बैंक ने पंचाट का रुख किया जिसने वसूली अधिकारी को गिरवी रखी संपत्ति को कुर्क करने और बेचने का आदेश दिया। नीलामी में इसकी बिक्री हो गई। इसके बाद एमआईडीसी ने एक नोट भेजा कि आय कर अधिकारी पहले ही इस संपत्ति के लिए कुर्की नोटिस भेज चुके थे। जब यह विवाद बंबई उच्च न्यायालय में पहुंचा तो उसने राजस्व अधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया। संपत्ति के खरीदार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और कर अधिकारियों की कुर्की को हटा दिया। उसने साथ ही एमआईडीसी को खरीदार को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का भी आदेश दिया।

ड्यूटी के दौरान मौत पर मुआवजा

उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी मुआवजा कानून के तहत मुआवजे का दावा करने वाले कर्मचारियों के फायदे के लिए 'रोजगार से उत्पन्न' उक्ति की परिभाषा को व्यापक बना दिया है। इस कानून में रोजगार के दौरान मौत या घायल होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान है। इस कानून के तहत कर्मचारियों को बीमा कवर हासिल होता है। पूनम देवी बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी वाद में भी ऐसा ही था। इस मामले में यमुना नदी से पानी लेने गए एक ट्रक चालक की मौत हो गई थी। वह 42 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में ट्रक चलाकर अंबाला से मेरठ ले गया था। वह नदी में गिर गया और डूब गया। कानून के तहत आयुक्त ने उसके वारिसों को 4.45 लाख रुपये का मुआवजा दिया। बीमा कंपनी ने इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने वारिसों के खिलाफ फैसला दिया। उसका कहना था कि ट्रक चालक की मौत ड्यूटी के दौरान हुई थी लेकिन यह ड्यूटी के कारण नहीं हुई थी। कानून के मुताबिक अगर कर्मचारी की मौत ड्यूटी के कारण और ड्यूटी के दौरान हुई है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। ट्रक चालक के वारिसों ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की और जीत गए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी भीषण गर्मी में अगर ट्रक चालक वाहन चलाने के लिए खुद को तरोताजा नहीं रखेगा तो गर्मी के कारण वह सड़क पर कोई गलती कर सकता है जिससे उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ट्रक चालक की मौत ड्यूटी के दौरान हुई थी।

प्रतिबंधित मिलरों के लिए पिछला दरवाजा बंद

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में 180 से अधिक प्रतिबंधित चावल मिलों की भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को आपूर्ति के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। राज्य की संस्थाओं ने चावल की खरीद की थी और इसे प्रसंस्करण तथा एफसीआई को आपूर्ति के लिए विभिन्न मिलरों को आवंटित किया था। पता चला कि कई मिलरों द्वारा एफसीआई को जिस चावल की आपूर्ति की गई थी, उसमें मिलावट थी और वह खाने लायक नहीं था। सीबीआई जांच के बाद इनमें से कई मिलरों को सात साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे एफसीआई को भारी नुकसान हुआ और उसने जुर्माने और ब्याज के साथ बकाये की मांग की। इन मिलरों ने इस प्रतिबंध को चकमा देने के लिए अपनी इकाइयों को नई कंपनियों को पट्टे पर दे दिया। एफसीआई ने इसका विरोध किया। नए मिलरों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी कि वे बेगुनाह हैं। न्यायालय ने इसे मान लिया। एफसीआई ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उसने एफसीआई बनाम वी के ट्रेडर्स वाद में अपील को सही ठहराया और कहा कि प्रतिबंधित मिलरों ने नया चोला पहन लिया है। इतना ही नहीं उनके पट्टे भी पंजीकृत नहीं थे।

बीमा कंपनी की देनदारी बढ़ी

अगर कोई इमारत बगल के भूखंड में खनन के कारण ढहती है तो यह साधारण बीमा के दायरे में आएगी, भले ही पॉलिसी दस्तावेज में इसे स्पष्ट तौर पर बाहर नहीं रखा गया हो। अगर पॉलिसी की शर्तों में अस्पष्टता है तो इसकी व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि इससे बीमित व्यक्ति को फायदा हो। उच्चतम न्यायालय ने संगरूर सेल्स कॉरपोरेशन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में यह व्यवस्था दी। इस मामले में एक सैनिटरीवेयर शोरूम बगल के भूखंड में चल रहे खनन के कारण ढह गया। शोरूम के मालिक ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी और फिर बीमा कंपनी के पास दावा किया। बीमा कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया। शोरूम के मालिक ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली जिसने कंपनी को ब्याज सहित 18 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा। पंजाब उपभोक्ता आयोग ने भी इस आदेश को सही ठहराया। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा कि पॉलिसी में पड़ोस में हो रही गतिविधियों के कारण हुए नुकसान को कवर नहीं किया गया था। शोरूम की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि तीसरे पक्ष के कारण हुआ नुकसान भी मानक नीति के तहत आता है। न्यायालय ने 2004 के अपने फैसले को उद्धृत किया जिसमें इसी बीमा कंपनी ने इसी तरह के मामले में यही दलील दी थी और उसे मुकदमा हार गई थी।

उपभोक्ता फोरम जा सकता है किसान

अगर कोई कंपनी किसी किसान को बीज देकर यह वादा करती है कि वह उसकी फसल को ज्यादा कीमत पर खरीद लेगी तो उपभोक्ता संरक्षण कानून के मुताबिक किसान उपभोक्ता है। उच्चतम न्यायालय ने नंदन बायोमेट्रिक्स बनाम अंबिका देवी वाद में यह बात कही। जो लोग सामान को खरीदकर फिर बेचते हैं या व्यावसायिक गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें उपभोक्ता अदालतों का रुख करने की अनुमति नहीं है। इस मामले में कंपनी ने महिला को बीजों की आपूर्ति की और उसे तकनीकी सहयोग, मार्गदर्शन और बीमा देने पर सहमति जताई। केरल में उपभोक्ता जिला फोरम में महिला की शिकायत थी कि कंपनी ने उसकी फसल लेने से इंकार करके अनुबंध का उल्लंघन किया। कंपनी ने अपनी दलील में कहा कि यह पुनर्बिकी है और महिला उपभोक्ता नहीं है क्योंकि उसने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बीजों का इस्तेमाल किया। जिला फोरम ने कंपनी की दलील मान ली। लेकिन महिला की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और फिर उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और जिला फोरम को शिकायत पर पुनर्विचार करने को कहा।

अधिकारियों ने खुद की अपने मामले की सुनवाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलवे के एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इस मामले में मध्यस्थ पंचाट के अध्यक्ष और उसके दो सहयोगी पूर्वी रेलवे के अधिकारी थे। न्यायालय ने कहा कि पंचाट ने एकतरफा अंदाज में फैसला दिया, अपने कुछ फैसलों के लिए कुछ कारण नहीं दिया और जन नीति का उल्लंघन किया। न्यायालय ने कहा कि चर्चा में इस बात का लेशमात्र भी प्रमाण नहीं है कि पंचाट ने संबंधित पक्षों के अधिकारों पर न्याय करने की जरा सी भी कोशिश की हो। बीबीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम भारत सरकार वाद में झारखंड के कुछ कस्बों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने की परियोजना का काम ठेकेदार कंपनी को दिया गया। देरी के कारण कंपनी का अनुबंध खत्म कर दिया गया जिससे मामला मध्यस्थता में पहुंच गया। न्यायालय ने पाया कि देनदारी और अनुचित कटौती तय करने में साफ-साफ अनियमितता बरती गई थीं।

वैश्विक महामारी के समय कारोबारी सौदे

विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदारों और विक्रेताओं को कारोबार, परिसंपत्तियों, मूल्यांकन और भविष्य में नकदी की आवक पर कोविड-19 के असर के फिर से आकलन की पड़ सकती है जरूरत

सुदीप्त दे

हाल में सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली की अंतिम तिथि 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी। यह कोरोनावायरस की वजह से अटके कारोबारी सौदों की दुनिया में भविष्य की स्थिति का संकेत हो सकता है। इसकी तपिश कंपनी दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही विलय एवं अधिग्रहण गतिविधियों को भी झेलनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रा प्रतिबंधों और अन्य बंदिशों से निश्चित समयावधि वाले सौदे एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिससे कानूनी और नियामकीय जटिलताएं पैदा हो रही हैं।

ट्राईलीगल में पार्टनर योगेश सिंह ने कहा, 'सीआईआरपी से गुजर रही बहुत सी कंपनियों की ऋणदाताओं की समितियां समय सीमा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क करने के बारे में विचार कर रही हैं क्योंकि बोलीदाता प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।' ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में सीआईआरपी के पूरा होने के लिए अधिकतम समयसीमा 330 दिन तय की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अदालतें केवल अत्यधिक जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रही हैं, जिससे समाधान योजनाओं की मंजूरी पर असर पड़ सकता है। विलय एवं अधिग्रहण विशेषज्ञों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी के आपूर्ति श्रृंखला पर असर का उन परिसंपत्तियों के मूल्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिनके स्वामित्व में बदलाव हो रहा है या बदलाव होने जा रहा है। खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर रवींद्र झुंनझुनवाला ने कहा, 'इस समय जिन सौदों की प्रक्रिया चल रही है, उनके मूल्यांकन के फिर से आकलन करने की जरूरत पड़ सकती है।'

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वक्त में खरीदारों को विलय एवं अधिग्रहण के सौदों में कोरोनावायरस के असर की वजह से लक्षित कंपनी के वित्तीय आकलन मॉडल का फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को अपने कारोबार की संभावनाओं का आकलन करना चाहिए और कारोबार पर किसी संभावित असर का सही खुलासा करना चाहिए।

सिंह ने कहा, 'विवाद की स्थिति से बचने के लिए दोनों पक्षों को संबंधित कारोबारों पर असर के आकलन के लिए समय और ध्यान देना चाहिए और उचित जोखिम आकलन, मूल्यांकन और सौदे की निश्चितता के पहलू पर सहमत होना चाहिए।'

खरीदारों को विलय के बाद एकीकरण से संबंधित मुद्दों पर यात्रा प्रतिबंध के असर को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अद्वैत लीगल में प्रिंसिपल (इन्फ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेट प्रैक्टिस) मोनाली दत्ता का सुझाव है कि सौदा करने वाले पक्षों को अग्रिम चर्चा करनी चाहिए। उन्हें लंबी अवधि के संबंधों और मौजूदा माहौल में विभिन्न उद्योगों के समक्ष मौजूद चुनौतियों की हकीकत को पहचानना चाहिए। हालांकि कंपनियों की लीगल टीम को भी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सौदा सफल न होने पर मामूली नुकसान हो। झुनझुनवाला ने कहा, 'इससे कोई मुकदमेबाजी से निपटने के लिए रणनीति बनाने में अड़चन नहीं आएगी, जो अन्यथा उनके रास्ते में अड़चन बनती हैं।'

खरीदारों और विक्रेताओं को क्या करना चाहिए

- दोनों पक्षों को सबसे पहले यह आकलन करना चाहिए कि क्या इस वैश्विक महामारी का कारोबार, परिसंपत्तियों, मूल्यांकन और भविष्य में नकदी की आवक पर कोई असर पड़ेगा
- सौदे पर हस्ताक्षर होने और पूरा होने के बीच कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की स्थिति में खरीदार सौदे से बाहर निकलने के अधिकारों की कर सकते हैं मांग
- पहले से चल रहे सौदे में दोनों पक्षों को महामारी के संबंध में विशेष वारंटी, मुआवजे और खुलासे के बारे में विचार करना चाहिए ताकि सौदे की निश्चितता और उचित सौदा आवंटन सुनिश्चित किया जा सके
- सीआईआरपी से गुजर रही कंपनियों की ऋणदाताओं की समिति बोलीदाता की कामकाजी प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए समयसीमा को बढ़ाने के लिए एनसीएलटी से संपर्क कर सकती है
- अदालत केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रही हैं, इसलिए ऋणदाताओं की समिति और विजेता बोलीदाताओं के लिए समाधान योजना की मंजूरी में देरी होने की संभावना है
- खरीदारों को विलय के बाद एकीकरण के संबंधित मुद्दों पर यात्रा प्रतिबंधों के असर को लेकर सजग रहने की जरूरत है

कारोबार में नुकसान पर 'फोर्स मैजर' के सहारे न बांधे उम्मीद

सुदीप्त दे

देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस के असर के चलते कारोबारी गतिविधियों के ठहरने की स्थिति में भारतीय कारोबारी समुदाय 'फोर्स मैजर' (अप्रत्याशित घटना) प्रावधान पर उम्मीद लगा रहा है लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सभी मामलों में यह प्रावधान कारगर नहीं होगा। इंडिया इंक पर इस संकट के कानूनी प्रभाव का आकलन करते हुए कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास द्वारा अपने ग्राहकों के लिए तैयार नोट में कहा, 'सभी अनुबंधों तथा प्रत्येक परिस्थिति में कोविड-19 के चलते पैदा स्थिति में फोर्स मैजर के सुरक्षात्मक उपाय प्रभावी नहीं हो सकेंगे क्योंकि विभिन्न अनुबंध तथा अलग-अलग कानूनी स्थितियां विभिन्न आवश्यकताओं को निर्धारित करती हैं।'

इस नोट में कंपनियों के लिए संबंधित कानूनी जोखिम को नियमित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है और सावधानीपूर्वक बताया गया है कि ब्रेकडाउन के चलते किस पक्ष को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरे देशों से अलग, भारत में 'फोर्स मैजर' कानून के तहत प्रदत्त अधिकार के बजाय एक संविदात्मक अधिकार है। डीएसके लीगल में पार्टनर ऋषि आनंद कहते हैं, 'अनुबंध में शामिल होने के कारण इसमें अंतर्निहित सीमाओं को देखते हुए इस अवधारणा की व्याख्या तथा गुंजाइश संबंधित अनुबंध एवं न्यायिक क्षेत्र में इसकी सटीक शब्दावलियों के अधीन है।' भारत में अलग से किसी तरह के फोर्स मैजर कानून के अभाव में विशेषज्ञों को भय है कि कोविड-19 के कारण भारतीय न्यायालयों पर अनुबंध संबंधी विवादों का बोझ बढ़ सकता है। आनंद कहते हैं, 'यह संभवतया भारतीय नीति निर्माताओं के लिए अनुबंध संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार का समय है जिसमें फोर्स मैजर संबंधी घटनाएं होने पर संबंधित पक्षों के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए।' विशेषज्ञों का कहना है कि संबंधित प्रावधान के तहत सुरक्षा के बारे में विचार कर रहे कारोबारियों को अपने अनुबंध में लिखित प्रावधान को बारीकी से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि क्या फोर्स मेजर एक अनुबंधात्मक अधिकार है या कानूनी अधिकार। विशेषज्ञों ने कहा कि कारोबारियों को इस बात पर भी गौर करना होगा कि क्या फोर्स मैजर प्रावधान का दावा करने से अनुबंध समाप्त तो नहीं हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध में फोर्स मैजर प्रावधान शामिल नहीं है फिर भी प्रभावित कंपनी या पक्ष भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सहारा ले सकते हैं। सिरिल अमरचंद मंगलदास ने कहा, 'हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के तहत दावा करते समय यह दिखाया जाए कि अनुबंध के तहत कार्य पूरी तरह असंभव है और अनुबंध को लागू करने के समय तथा परिस्थिति से अलग हो चुका है।'

विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया विलय तथा अधिग्रहणों पर कोरोनावायरस का गंभीर असर होगा। सिरिल के नोट में कहा गया, 'विलय तथा अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को अपने दस्तावेजों की गहन समीक्षा करनी चाहिए और कोविड-19 के कारण पड़ने वाले प्रभाव के लिए अपने साझेदारों से राय लेनी चाहिए।'

आनंद कहते हैं, 'अंत में, दोनों पक्षों के बीच साझा कारोबारी विचारों को सबसे आगे रखा जाना चाहिए, जिसे विवादों के बजाय संवाद द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।'

क्या है 'फोर्स मैजर'?

यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है 'महाशक्ति।' यह कानून भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 32 तथा 56 के तहत सन्निहित है। यह एक संविदात्मक प्रावधान है जो दो पार्टियों के बीच सहमति पर आधारित है। अगर कोई पार्टी अनुबंध के तहत निर्धारित जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असमर्थ रहती है तो यह नियम उस पार्टी का बचाव करती है। आमतौर पर फोर्स मैजर के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, श्रमिक आंदोलन, हड़ताल या महामारी आदि स्थिति शामिल होती है।

कंपनियों को क्या करना होगा?

अनुबंध को ध्यान से पढ़ें: कई बार अधिकांश अनुबंधों में लिखी गई भाषा में काफी अंतर देखा गया है। इन प्रावधानों की समीक्षा काफी जरूरी है।

प्रावधान लागू करने का नोटिस जारी करें: अधिकांश अनुबंधों में दूसरे पक्ष को नोटिस भेजने की आवश्यकता होती है, जिससे संबंधित प्रावधान को लागू किया जा सके। कुछ कंपनियां दावे या प्रावधान को प्रभावी करने के लिए नोटिस में समय सीमा का भी वर्णन करते हैं।

आंकड़ें उपलब्ध कराएं: फोर्स मैजर पर निर्भर कंपनी के पास जरूरी तथ्य होने चाहिए और दूसरे पक्ष को वह उपलब्ध कराए जाएं।

तथ्य सहेजें: गंभीर वाद-संवाद तथा दूसरे कार्यों से जुड़े तथ्यों की प्रतियां सहेजी जाएं जिससे बाद में विवाद की स्थिति में इनका प्रयोग किया जा सके। यह जरूरी है कि कंपनी नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी कदम उठाए।

अगर अनुबंध में न हो ऐसा प्रावधान?

अगर अनुबंध में फोर्स मैजर का प्रावधान नहीं है तो प्रभावित कंपनी या पक्ष भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सहारा ले सकती है।

कोरोना से कार्यालय परिसरों में घटी चहल-पहल

पृष्ठ 1 का शेष

बेंगलूरु में हर जगह मास्कगुरुग्राम से करीब 2,000 किमी दूर भारत की सिलिकॉन सिटी यानी बेंगलूरु में भी यही हाल है। एमेजॉन इंडिया के 32 मंजिला मुख्यालय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कंपनी के अधिकांश कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। इमारत के प्रवेश द्वार पर मास्क पहने चार लोग हर आगंतुक के तापमान की जांच कर रहे हैं। कंपनी के एक कर्मचारी ने कहा, 'अगर किसी व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री से अधिक है तो उसे तुरंत जांच के लिए पास के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है।' ऑफिस की लॉबी में अक्सर कर्मचारियों की चहल-पहल रहती है लेकिन आजकल यह सुनसान पड़ी है। किसी को भी वहां जमा होने की अनुमति नहीं है। वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने सभी 10 हजार कर्मचारियों को 20 मार्च तक घर से काम करने की सुविधा दे रखी है। कंपनी के बेलनदूर कार्यालय में गुरुवार और शुक्रवार को दवा का छिड़काव किया गया। घर से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित तौर पर मेल भेजा जा रहा है। बी2बी यूनिकॉर्न उड़ान के सभी कमर्चारियों को 20 मार्च तक घर से काम करने को कहा गया है। मीटिंग गूगल हैंगआउट के जरिये हो रही है। जिन कर्मचारियों का कार्यालय जाना जरूरी है, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें यह शपथपत्र भी देना पड़ रहा है कि

उनमें फ्लू के कोई लक्षण नहीं हैं। उबर इंडिया ने भी अपने कर्मचारियों को 6 अप्रैल तक घर से काम करने को कहा है और ऑफिस की कैंटीन भी बंद कर दी है।

यात्रा विवरण की पड़ताल

वित्तीय राजधानी मुंबई में उपनगरीय रेल में यात्रियों की कमी हालात बिगड़ने का एक बड़ा संकेत है। मुंबई के विखरोली में ऐंबसी ऑफिस पार्क्स में रिसेप्शन पर तैनात कर्मी लोगों के शरीर का तापमान माप रहे हैं। इसके बाद उनसे यह पूछा जाता है कि क्या हाल में उन लोगों ने चीन, इटली या कोरिया आदि की यात्राएं की है। ऐंबसी ऑफिस पार्क्स के बेंगलूरु, मुंबई और पुणे में परिसर हैं। कंपनी कोरोनावायरस से निपटने के लिए कई दूसरे उपाय कर रहे हैं।

चेन्नई में कारोबार सामान्य

चेन्नई के आईटी क्षेत्र ओल्ड महाबलीपुरम रोड (ओएमआर) में कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है। चेन्नई की ज्यादातर कंपनियां वायरस के संक्रमण पर पैनी निगाहें रख रही हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह नहीं दी है। सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो एक अपवाद है। कंपनी ने अपने चेन्नई कार्यालय के 8,500 कर्मचारियों को घर से ही काम करने की हिदायत दी है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि नितांत आवश्यक होने पर ही उन्हें कार्यालय आना चाहिए।

जोहो ने एहतिआत के तौर पर दुनिया में अपने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी है। कंपनी के तकनीकी निदेशक राजेंद्रन दंडपानी ने कहा कि वायरस का खतरा टलने तक कंपनी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए ही कहेगी। एक दूसरी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने अपने प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की सभी गैर-जरूरी यात्राएं टाल दी हैं। कंपनी ने सर्दी-जुकाम के लक्षण होने पर कर्मचारियों को तत्काल इस ओर ध्यान देने के लिए कहा है। कॉग्निजेंट के प्रवक्ता ने कहा, 'भारत और अन्य देशों में कॉग्निजेंट के कार्यालयों में सामान्य रूप से काम हो रहा है। कंपनी ने दुनियाभर में अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं देने के लिए एक टीम गठित की है। यह टीम संबंधित पक्षों के साथ रोज आपात योजनाओं पर काम करती है। आपात योजनाओं में ऐसी तैयारियां भी शामिल हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारी सुदूर क्षेत्रों से काम कर सके। कंपनी भारत सहित दुनिया भर में अपने कार्यालयों में स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। कंपनी ने कार्यालयों में हैंड सैनिटाइजर भी बड़ी संख्या में रखे हैं।

साथ में नई दिल्ली से युवराज मलिक और नेहा अलावधी

यूरोपीय मंदी से वाहन क्षेत्र होगा प्रभावित

मदरसन सूमी, अपोलो टायर्स और टाटा मोटर्स के ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियों में शुमार होने की आशंका

राम प्रसाद साहू

घरेलू स्तर पर आर्थिक मंदी से प्रभावित हुए वाहन क्षेत्र को अब यूरोप जैसे प्रमुख भूभागों में मांग से संबंधित चिंताओं को देखते हुए दोहरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय बाजार में गहरी पहुंच वाली कंपनियों ने अपने उन प्रतिस्पर्धियों (खासकर घरेलू बाजार तक केंद्रित) की तुलना में अपने शेयर कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की है।

जहां निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले तीन सप्ताहों के दौरान 20 प्रतिशत तक गिरा है, वहीं मदरसन सूमी, टाटा मोटर्स, वेरॉक इंजीनियरिंग, और अपोलो टायर्स में इस अवधि के दौरान 34 प्रतिशत और 48 प्रतिशत के बीच गिरावट आई है। इन कंपनियों में तेज गिरावट काफी हद तक कोरोनावायरस के प्रसार के बाद मांग से जुड़ी चिंताओं की वजह से आई है। एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने कहा कि इस महामारी की वजह से पैदा हुए डर से मांग पर दबाव पड़ेगा जिससे बिक्री और संयंत्रों के इस्तेमाल में कमी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल स्पेन, इटली, हंगरी और फ्रांस द्वारा उठाए जा रहे आपात उपायों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला और बिक्री पर दबाव पड़ रहा है जिससे निवेशकों के लिए धारणा नकारात्मक हो गई है।

कुछ यूरोपीय वाहन निर्माताओं के लिए भी अल्पावधि परिदृश्य कमजोर पड़ा है। उदाहरण के लिए डेमलर पर आपूर्ति श्रृंखला और मांग संबंधित दबाव पड़ सकता है। कंपनी का मानना है कि 2020 में मर्सिडीज बेंज कारों के लिए बिक्री 2019 के स्तर से नीचे रह सकती है। रेनो को आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि उसके ज्यादातर कलपुर्जे चीन के हुबेई प्रांत से आते हैं। निसान मोटर अपनी रिकवरी योजना में लागत कटौती पर जोर दे रही है। कंपनी के दूसरे सबसे बड़े बाजार चीन में वाहन बिक्री फरवरी में 80 प्रतिशत घटी है, क्योंकि यात्रा पर प्रतिबंध और कुछ मार्गों को बंद किया गया है।

ये कंपनियां भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए सबसे बड़े ग्राहकों में शुमार हैं और यूरोप एक प्रमुख बाजार है। मदरसन सूमी का लगभग 37 प्रतिशत राजस्व यूरोप (स्पेन और जर्मनी) से आता है और रेनो निसान, ऑडी, फोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू और डेमलर जैसी यूरोपीय वाहन निर्माताओं के वैश्विक परिचालन का इसमें लगभग 50 प्रतिशत योगदान है। वैरॉक इंजीनियरिंग का लगभग 46 प्रतिशत राजस्व यूरोपीय बाजार से आता है और फिएट क्राइसलर, प्यूजो, जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) और फॉक्सवेगन उसके प्रमुख ग्राहकों में शामिल हैं।

अपोलो टायर्स के लिए कमजोर धारणा खासकर हंगरी के प्रधानमंत्री द्वारा कोरोनावायरस की महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने की चेतावनी दिए जाने के बाद देखी गई है। हंगरी में अपोलो का नया संयंत्र मजबूती से परिचालन कर रहा था और विश्लेषकों को कंपनी के यरोपीय परिचालन के लिए भविष्य में एक अंक की वृद्धि का योगदान होने का अनुमान था। लेकिन कंपनी के लिए हालात में सुधार के बजाय वृद्धि की रफ्तार नीचे आ सकती है। अन्य टायर निर्माता बालकृष्ण टायर्स भी प्रभावित होगी, क्योंकि उसका लगभग 50 प्रतिशत टायर निर्यात यूरोपीय बाजार से जुड़ा हुआ है। महिंद्रा सीआईई (जिसमें स्पेन की सीआईई ऑटोमोटिव की 56 प्रतिशत हिस्सेदारी है) अपना आधे से ज्यादा राजस्व यूरोपीय बाजार से हासिल करती है और अब इस पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उत्पादन में कमी आई है।

टाटा मोटर्स के लिए, यह प्रभाव कई गुना होगा, क्योंकि जेएलआर के राजस्व में यूरोप का लगभग 40 प्रतिशत योगदान है। चीन में फरवरी में कार की खुदरा बिक्री 85 प्रतिशत घटने, आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव, और अन्य बाजारों में मांग में कमी को देखते हुए कंपनी ने अपने वित्त वर्ष 2020 के एबिटा में एक प्रतिशत तक की कमी की है। अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज और जेएलआर में निवेश को देखते हुए मांग पर दबाव की स्थिति में नकदी प्रवाह बनाए रखना मुश्किल होगा। टाटा मोटर्स के अलावा, यूरोप में संयंत्र चलाने वाली कई वाहन कलपुर्जा निर्माता कंपनियां कर्ज से जुड़ी हुई हैं। एक विश्लेषक का कहना है कि ये संयंत्र नियोजित पूंजी पर एक अंक का प्रतिफल कमाते हैं। नए अनुबंधों के बगैर और मौजूदा ऑर्डरों का दायरा बढ़ाए बिना ऊंची लागत से नए संयंत्र गैर-उपयोगी साबित हो सकते हैं।

उनका कहना है कि परिचालन से जुड़ी चिंताओं के अलावा, इन कंपनियों के लिए मूल्यांकन दीर्घावधि औसत की तुलना में ज्यादा रहा है। यह बाजार के कम्फर्ट जोन से ऊपर था और इस वजह से रेटिंग में गिरावट की आशंका बनी हुई थी।

मांग पर दबाव को देखते हुए ब्रोकरों का मानना है कि खासकर बड़े वैश्विक जोखिम वाली कंपनियों के लिए निवेशक ग्रामीण बिक्री में तेजी, लाभांश और मजबूत पूंजी आवंटन को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प जैसी भारत-केंद्रित कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं।

बाजार हलचल

बाजारों के लिए नकदी की खुराक

बाजार कारोबारियों का कहना है कि व्यवस्था में 2 लाख करोड़ डॉलर की पूंजी डाले जाने से बाजार में तेजी आ सकती है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को शेयर नहीं मिलने की स्थिति में रिफंड का भुगतान किया जा चुका है। एसबीआई कार्ड्स के 10,300 करोड़ रुपये के आईपीओ को 27 गुना का अभिदान मिला। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ 5 मार्च को बंद हुआ, और जब से बाजार में 11 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये की संस्थागत रकम और अन्य 90,000 करोड़ रुपये का एचएनआई निवेश इस आईपीओ पर लगा था। एक विश्लेषक ने कहा, 'एसबीआई कार्ड्स निर्गम के लिए रिफंड शुक्रवार को किया गया। यानी इस निर्गम के लिए ब्लॉक कर रखी गई पूंजी उन्हें शुक्रवार को लौटा दी। यदि बाजार मजबूत होता है, तो इसमें से कुछ पूंजी बाजार में लौट सकती है।' *– समी मोडक*

डीमार्ट के लिए कारोबारी बदलाव

एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर को इस महीने के शुरू में ट्रेड-टु-ट्रेड (टी2टी) श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने की स्टॉक एक्सचेंजों की पहल से बाजार को आश्चर्य हुआ है। हालांकि यह कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ। यह कंपनी डीमार्ट रिटेल चेन का परिचालन करती है। 2 मार्च से एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर महज 6 प्रतिशत गिरा है, जबकि निफ्टी में इस अवधि में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। टी2टी सेगमेंट के तहत, किसी शेयर को डिलिवरी के लिए अनिवार्य तौर पर चिह्नित किया जाता है। अक्सर, अत्यधिक सट्टा गतिविधि वाले शेयर इस सेगमेंट में आते हैं। हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने इस महीने बाजार को मात दी है। यह अपने ऊंचे स्तर से 17 प्रतिशत नीचे आया है। *– सुंदर सेतुरामन*

एमएनसी शेयर दिख रहे सुरक्षित दांव

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के शेयर मौजूदा बाजार बिकवाली में सुरक्षित दांव के तौर पर उभरे हैं। 20 फरवरी से निफ्टी 17 प्रतिशत गिरा है, जबकि एमएनसी कंपनियों के सूचकांक में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक कम कर्ज वाली और पिछले तीन वर्षों में अच्छी आय वृद्धि वाली एमएनसी पर ध्यान दे सकते हैं। एक विश्लेषक ने कहा, 'एमएनसी शेयरों ने चुनौतीपूर्ण परिवेश में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, शेयर कीमतों में गिरावट से विदेशी पैतृक कंपनियों को अपनी इन घरेलू कंपनियों हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल सकता है। वैश्विक रूप से कम ब्याज दरों ने पुनर्खरीद या ओपन ऑफरों को एमएनसी प्रवर्तकों के लिए बेहद आकर्षक पेशकश बना दिया है।' *– अशोक दिवासे*

उथल-पुथल भरे बाजार में फंडों की लिवाली बरकरार

जश कृपलानी

बाजार में भारी बिकवाली के बाद भी घरेलू म्युचुअल फंड (एमएफ) लगातार शेयर खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) हाल में बाजार में आई गिरावट के दौरान बड़े पैमाने पर शेयरों से निवेश निकाल चुके हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एमएफ कंपनियों ने चालू कैलेंडर वर्ष में शेयरों में 18,871 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किए हैं। इस दौरान एफआईआई ने कुल 14,889 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की है। इनमें अस्थायी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को एफआईआई द्वारा की गई 6,027 करोड़ रुपये की बिकवाली भी शामिल है।

■ चालू कैलेंडर वर्ष में म्युचुअल फंडों ने शेयर बाजार में 18,871 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया

घरेलू एमएफ कंपनियों का कहना है कि बाजार में बिकवाली से शेयर खरीदारी के लिहाज से काफी आकर्षक हो गए हैं और नए निवेश के लिए माकूल हो गए हैं। टाटा म्युचुअल फंड में वरिष्ठ फंड प्रबंधक चंद्र प्रकाश पदियार ने कहा,'पूरे बाजार में शेयर खरीदारी के लिहाज से काफी आकर्षक हो गए हैं। भुगतान संतुलन सुधरने और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद भारत के वृहद आर्थिक हालात फिलहाल मजबूत दिख रहे हैं।'

पदियार ने कहा,'हमारे जैसे निवेशक, जो बाजार में निवेश के लिए नकदी जमा कर रखते हैं, उनके लिए यह निवेश का बेहतरीन मौका है। इस समय बाजार में गिरावट सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और शेयर इससे अधिक नीचे जाएंगे शायद ऐसा नहीं लगता है। अगले 12 से 18 महीने के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं।' कोरोनावायरस के कहर से आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित होने की आशंका के बीच कच्चे तेल में गिरावट एक सकारात्मक के चालू खाता घाटे पर सकारात्मक असर होगा।'

इस बीच, फंड कंपनियां किसी तरह के नए जोखिम कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव भी कर रहे हैं। क्वांटम एडवाइजर्स में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य निवेश अधिकारी आई वी सुब्रमण्यन ने कहा,'हम मौजूदा हालात के मद्देनजर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं। हम वैसी कंपनियों को तवज्जो दे रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में मंदी झेलने में सक्षम हैं। सतर्क बाजार में हमें संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए नकदी झोंक रहे हैं।' फंड प्रबंधकों के सतर्क लेकिन सकारात्मक रुख से भी शुक्रवार को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। एक्सचेंजों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को एफआईआई ने 6,000 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक शेयरों की बिकवाली की। इसके उलट घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,867 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की लिवाली की। चालू कैलेंडर वर्ष में भारतीय बाजारों को लेकर एफआईआई की धारणा में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

सौदेबाजों के लिए है अच्छा समय

वर्ष 2008 या 2012 में मजबूत बिजनेस फ्रैंचाइजी वाली कंपनियों का चयन करने वाले निवेशकों ने अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू में कई गुना इजाफा दर्ज किया

कृष्ण कांत

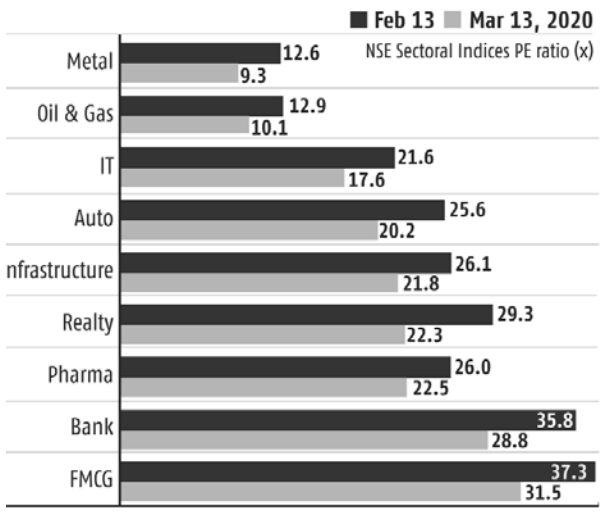

बाजार में बड़ी गिरावट ने लगभग एक दशक में पहली बार अच्छे शेयर ऐतिहासिक रूप से निचले मूल्यांकन पर खरीदने का अवसर दिया है। इससे निवेशकों को प्रतिफल सामान्य होने और आर्थिक वृद्धि तथा कॉरपोरेट आय के फिर से दीर्घावधि विकास की पटरी पर लौटने की स्थिति में शानदार प्रतिफल कमाने में मदद मिलेगी। इसी तरह की स्थिति बाजार में वर्ष 2008 और 2012 की पिछली बड़ी गिरावट के दौरान देखने को मिली थी। 2008 या 2012 में मजबूत बिजनेस फ्रैंचाइजी का चयन करने वाले निवेशकों ने बाजार में अस्थिरता के बावजूद अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में कई गुना की तेजी दर्ज की।

उदाहरण के लिए, बीएसई के सेंसेक्स ने फरवरी 2009 में अपने निचले स्तर से 18 महीनों के दौरान ढाई गुना की तेजी दर्ज की। सेंसेक्स को लगभग 74 प्रतिशत का सालाना प्रतिफल हासिल करने में मदद मिली। इसी तरह, कैलेंडर वर्ष 2012 की पहली छमाही (जिसमें भारी बिकवाली देखी गई थी) के बाद सूचकांक अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग दोगुना हो गया जिससे बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी करने वाले निवेशकों को लगभग 20 प्रतिशत का सालाना प्रतिफल हासिल हुआ।

ताजा गिरावट के बावजूद रिटेल उधारी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कई प्रमुख शेयर अपने 2012 के निचले स्तरों से अभी भी लगभग 10 गुना पर हैं। यही वजह है कि विश्लेषक निवेशकों को मौजूदा गिरावट का इस्तेमाल दीर्घावधि खरीदारी अवसर के तौर पर करने की सलाह दे रहे हैं। सिस्टेमेटिक्स ग्रुप के शोध प्रमुख धनंजय सिन्हा कहते हैं, 'हम अपने ग्राहकों से कंज्यूमर उत्पादों, सीमेंट एवं रिटेल उधारी में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने को कह रहे हैं।' उनके अनुसार, तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट से पेंट, सीमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में मार्जिन को मजबूती मिलेगी। अन्य विश्लेषक हालात सामान्य होने पर अच्छी गुणवत्ता वाले मिडकैप में तेजी आने की उम्मीद जता रहे हैं। इक्विनोमिक्स रिसर्च ऐंड एडवायजरी सर्विसेज के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम कहते हैं, 'कई गुणवत्ता वाले मिडकैप शेयर अब एक अंक के पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहे हैं जिससे दीर्घावधि निवेशकों को अच्छी वैल्यू दिख रही है।'

विश्लेषक भारत समेत वैश्विक तौर पर सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट का लाभ मिलने की भी संभावना देख रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि निवेशक सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल में ब्याज दरों में कटौती की है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसमें कई शेयरों पर लाभांश प्रतिफल बॉन्ड प्रतिफल के मुकाबले कम है जिससे शेयर आकर्षक हो गए हैं। सेंसेक्स कंपनियों के लिए आय प्रतिफल अब 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल के मुकाबले 390 आधार अंक तक आगे निकल गया है। इस तरह का बड़ा अंतर 2012 की बाजार गिरावट के दौरान देखा गया था। हमने उन सभी क्षेत्रों के शेयरों की सूची तैयार की है जिनमें वृहद आर्थिक अनिश्चितता दूर होने पर फिर से तेजी आ सकती है।

(राम प्रसाद साहू, उज्ज्वल जौहरी और श्रीपाद आंटे द्वारा शेयर विश्लेषण)

आईटीसी

57%

पी/ई (मौजूदा)	पी/ई (वर्ष 20ई)
17.2	13.3

बिक्री वृद्धि (%)	7.9
पीबीटी वृद्धि (%)	10.0
बाजार पूंजीकरण (करोड़ रु.)	2,17,836
शेयर कीमत (रुपये)	177.2
1-महीने का प्रतिफल (%)	-17.0

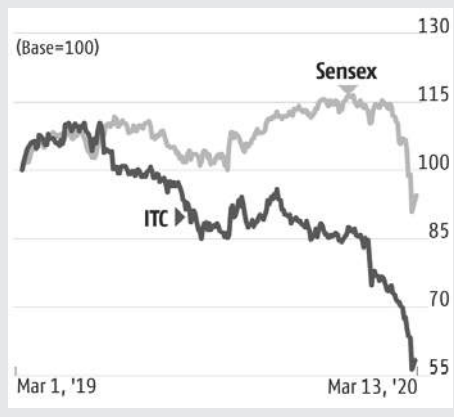

- महंगे मूल्यांकन वाले एफएमसीजी क्षेत्र में सस्ते शेयरों में शामिल
- उपभोक्ता व्यवसाय (प्रोसेस्ड फूड, पर्सनल केयर, बिस्कुट, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, फिएमा जैसे ब्रांड) का मार्जिन सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने से मिल रही मदद
- मास सिगरेट सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा चिंता बनी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि सिगरेट सेगमेंट में कर में ऊंची वृद्धि आईटीसी की प्रीमियम श्रेणी के लिए अच्छा संकेत हो सकती है
- तंबाकू सेवन के लिए कानूनी उम्र की सीमा में संभावित वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह और 3 प्रतिशत से ज्यादा का लाभांश प्रतिफल सकारात्मक हैं

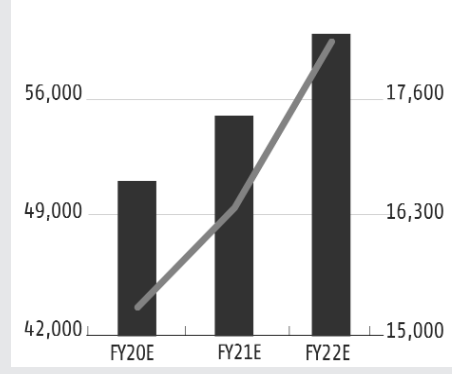

एसीसी

37%

पी/ई (मौजूदा)	पी/ई (वर्ष 20ई)
17.0	14.8

बिक्री वृद्धि (%)	6.0
पीबीटी वृद्धि (%)	35.9
बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)	23,395
शेयर कीमत (रुपये)	1,245.8
1-महीने का प्रतिफल (%)	17.0

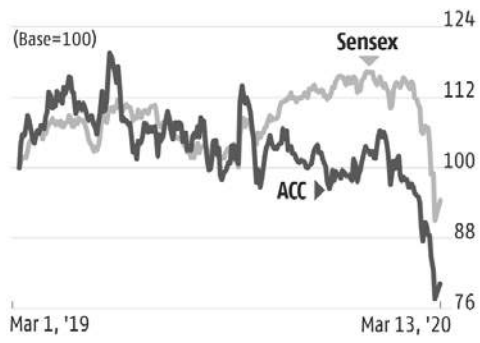

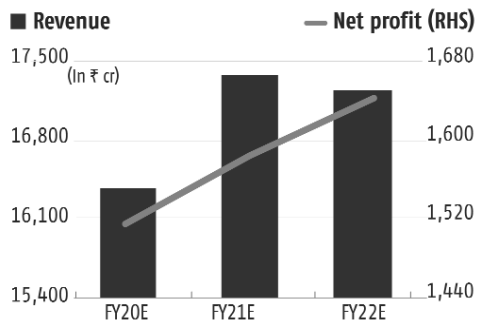

- कमजोर मांग से 2019 के अंत में कीमत गिरावट को बढ़ावा मिल जिससे बाजार धारणा प्रभावित हुई
- पूरे भारत में औसत सीमेंट प्राप्तियां 2020 के शुरू से सुधरी हैं। इससे भारतीय कंपनियों को को मदद मिलनी चाहिए
- पूर्वी भारत में ऊंची कीमतें कंपनी के लिए सकारात्मक हैं, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता मौजूद है
- पेट कोक और डीजल जैसी उत्पाद कीमतें अल्पावधि में कमजोर रही हैं और इससे लॉजिस्टिक तथा ऊर्जा लागत नियंत्रित करने में मदद मिलेगी
- लागत नियंत्रण और बढ़ती प्राप्तियों से प्रति टन लभ में तेजी आएगी
- पूर्वी भारत में ताजा क्षमताएं वर्ष 2020 के अंत तक ऑनलाइन हो जाएंगी जिससे एसीसी के लिए बाजार भागीदारी और वृद्धि बढ़ाने में मदद मिलेगी
- एसीसी का शेयर 104 डॉलर की प्रति टन रीप्लेसमेंट लागत पर कारोबार कर रहा है, जो अल्ट्राटेक की 180 डॉलर और श्री सीमेंट्स की 283 डॉलर के तुलना में काफी कम है

मारुति सुजूकी

19%

पी/ई (मौजूदा)	पी/ई (वर्ष 20ई)
24.5	25.1

बिक्री वृद्धि (%)	-9.2
पीबीटी वृद्धि (%)	-27.7
बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)	1,87,167
शेयर कीमत (रुपये)	6,196.0
1-महीने का प्रतिफल (%)	-11.1

- नई पेशकशों की मदद से मारुति को नई प्रतिस्पर्धा के बावजूद बाजार भागीदारी सुधरने की उम्मीद है
- डीजल के साथ बढ़ते कीमत अंतर और पेट्रोल-संचालित वाहनों (खासकर स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों) के लिए शहरी पसंद को देखते हुए ऑल-पेट्रोल पोर्टफोलियो पर ध्यान देना सकारात्मक है
- उच्च स्तर के स्थानीयकरण को देखते हुए कोरोनावायरस की वजह से चीन से आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव नहीं
- सीमित बीएस-4 इन्वेंट्री और नई पेशकशों के ज्यादा अनुपात से बेहतर मार्जिन मिलने का अनुमान
- मजबूत रबी फसल की उम्मीद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरने में मदद मिलेगी। इससे मारुति को राहत मिलेगी क्योंकि वह अपनी 38 प्रतिशत बिक्री दूरदराज इलाकों से हासिल करती है

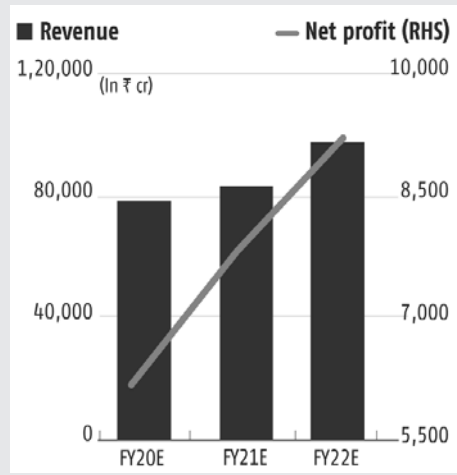

सिप्ला

23%

पी/ई (मौजूदा)	पी/ई (वर्ष 20ई)
22.4	17.6

बिक्री वृद्धि (%)	9.7
पीबीटी वृद्धि (%)	32.3
बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)	34,309
शेयर कीमत (रुपये)	425.6
1-महीने का प्रतिफल (%)	-4.0

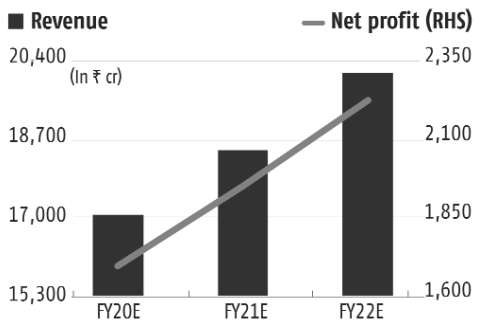

- नियामकीय चिंताओं और उम्मीद से कमजोर तीसरी तिमाही के प्रदर्शन से शेयर में गिरावट को बढ़ावा मिला
- कंपनी लगातार मजबूत घरेलू वृद्धि दर्ज कर रही है और उसने पुनर्गठन के बाद अपनी जेनेरिक बिक्री को मजबूत किया है
- ब्रांडेड, ट्रेड जेनेरिक्स और उपभोक्ता व्यवसायों के समेकन से आपसी तालमेल बढ़ाने में मदद मिलेगी
- घरेलू बिक्री (राजस्व में 40 प्रतिशत योगदान) चीन के मजबूत रेस्पिरेटरी फ्रैंचाइजी की मदद से और अन्य सेगमेंट में भी मजबूत स्थिति की मदद से कुल बाजार में अच्छा प्रदर्शन करेगी
- कंपनी को नई दवाओं की मदद से अपना अमेरिकी व्यवसाय मजबूत बनाए रखने में मदद मिल सकती है
- कंपनी के अपने स्वयं के प्रमुख परिचालन होने से अफ्रीका एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है जिससे वृद्धि दर में मदद मिलने की संभावना है

कोलगेट-पामोलिव

15%

पी/ई (मौजूदा)	पी/ई (वर्ष 20ई)
44.3	36.9

बिक्री वृद्धि (%)	4.6
पीबीटी वृद्धि (%)	-3.7
बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)	34,391
शेयर कीमत (रुपये)	1,264.5
1-महीने का प्रतिफल (%)	-7.8

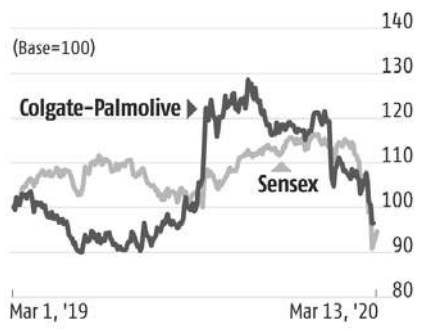

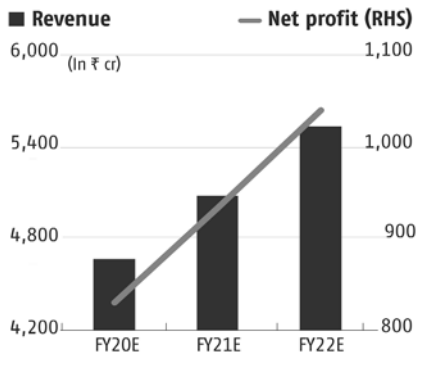

- बाजार भागीदारी पुनः बढ़ाने के प्रयास में नए सीईओ ने बड़े ब्रांड निवेश, उत्पाद विकास में तेजी और प्रत्यक्ष वितरण में वृद्धि के साथ बिक्री में इजाफा करने पर ध्यान दिया है
- प्रमुख सेगमेंट में सुधार से बाजार भागीदारी के साथ साथ परिचालन मुनाफा मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी
- ब्रांड, वैश्विक दक्षता, वितरण और प्रीमियम कैटेगरी के तौर पर मजबूत क्षमता से बाजार भागीदारी हासिल करने के लिहाज से मदद मिलेगी
- वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2017 के दौरान क्षमता पर बड़े खर्च से बिक्री में सुधार के साथ कंपनी को अपना व्यवसाय तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है
- कोलगेट नए वैरिएंट पेश कर और नए सेगमेंट की तलाश कर बॉडी ऐंड हैंडवॉश कैटेगरी में अपना दायरा बढ़ा रहा है
- विश्लेषकों को आरओई तेजी से बढ़ने और वित्त वर्ष 2022 में यह 56 से बढ़कर 90 प्रतिशत के पार पहुंच जाने की उम्मीद है

विप्रो

19%

पी/ई (मौजूदा)	पी/ई (वर्ष 20ई)
12.8	12.0

बिक्री वृद्धि (%)	5.2
पीबीटी वृद्धि (%)	17.7
बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)	1,22,404
शेयर कीमत (रुपये)	214.3
1-महीने का प्रतिफल (%)	-12.2

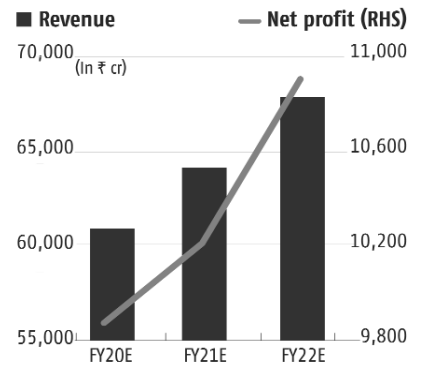

- इस शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है। निफ्टी आईटी सूचकांक में पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में इसमें 16 प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी आई
- प्रमुख आईटी कंपनियों के मुकाबले 24-25 प्रतिशत की मूल्यांकन गिरावट को देखते हुए शेयर में अब बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं दिख रहे हैं। यह मध्यावधि से दीर्घावधि निवेशकों के लिए बेहतर दांव हो सकता है, क्योंकि अल्पावधि वृद्धि का परिदृश्य थोड़ा कमजोर दिख रहा है
- मजबूत ऑर्डर प्रवाह से मध्यावधि से दीर्घावधि के दौरान निर्माण और उपभोक्ता सेगमेंट्स की वृद्धि में सुधार आ सकता है
- बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) सेगमेंट में दबाव की भरपाई उपभोक्ता, हेल्थकेयर और निर्माण सेगमेंट्स में बेहतर वृद्धि से होने की संभावना है
- जहां पूरे आईटी क्षेत्र में अल्पावधि मांग से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं, वहीं रुपये में गिरावट से मार्जिन में कुछ सुधार आएगा
- मजबूत बाजार पूंजीकरण अनुपात से भी स्थिति अनुकूल हुई है

चार्ट और टेबल में, बिक्री वृद्धि (सालाना आधार पर), कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) वृद्धि (सालाना आधार पर) दिसंबर 2019 में समाप्त पिछले 12 महीनों के लिए हैं। बाजार पूंजीकरण, शेयर भाव और मौजूदा पीई (कीमत-आय) 13 मार्च के हैं, तीर में दर्शाए गए आंकड़े विश्लेषकों के कीमत लक्ष्य के आधार पर अगले 12 महीनों में संभावित तेजी का संकेत देते हैं ईः अनुमानित,

स्रोतः कैपिटालाइन/ब्लूमबर्ग, आंकड़ेः बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा एकत्रित

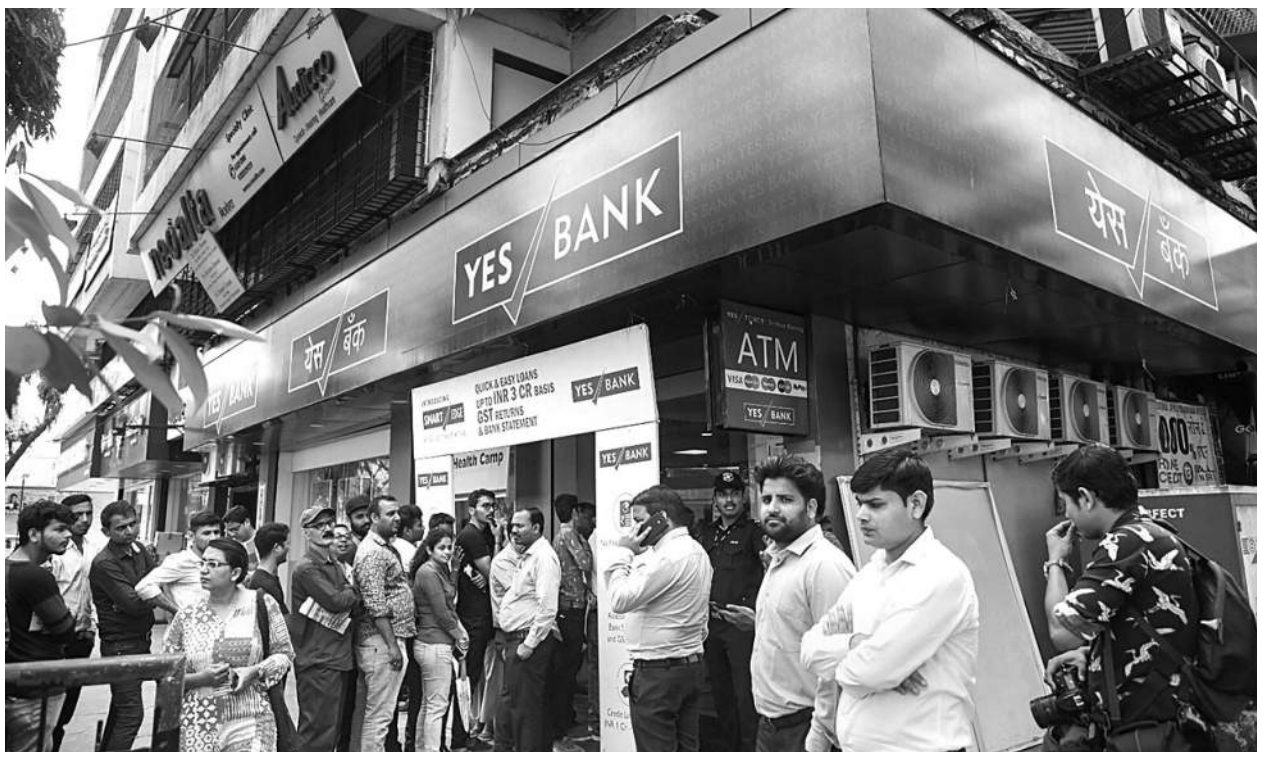

बैंक घोटालों से चिंतित डेट फंड निवेशक

आईएलऐंडएफएस घोटाला उजागर होने के बाद से ही डेट फंड निवेशक चिंतित हैं। अब येस बैंक घोटाले ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है

जयदीप घोष और संजय कुमार सिंह

बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड के मुख्य कार्याधिकारी ए बालासुब्रमण्यन कहते हैं, 'हर व्यक्ति को नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) में उतार-चढ़ाव को सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उनके लिए ऐसे फंडों से जुड़े रहना सही रणनीति होगी, जो कई दौर देख चुके हैं और मामूली उतार-चढ़ावों को पार कर सकते हैं।'

पिछले 18 महीनों में कई मौकों पर एनएवी में उतार-चढ़ाव को लेकर निवेशकों के धैर्य की परीक्षा हुई है। उदाहरण के लिए येस बैंक के बोर्ड के अधिकार छीनकर अपने हाथ में लेने और एडिशनल टियर वन (एटी-1) बॉन्डों को रद्द करने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से निप्पॉन इंडिया की पांच योजनाओं का एनएवी एक दिन में 9 फीसदी से 25 फीसदी तक गिरा। फ्रैंकलिन इंडिया, आईडीबीआई और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट जैसी अन्य फंड कंपनियों की योजनाओं को भी नुकसान झेलना पड़ा है।

डेट फंड निवेशक सितंबर 2018 में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज घोटाला सामने आने के बाद से लगातार दबाव में हैं। तब से कई बड़ी कंपनियां डेट म्युचुअल फंड योजनाओं के भुगतान में डिफॉल्ट या देरी कर चुकी हैं। इन कंपनियों में अनिल अंबानी समूह, जी एंटरप्राइजेज, दीवान हाउसिंग फाइनैंस आदि शामिल हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये घटनाएं बार-बार हो रही हैं। ऐसे माहौल में डेट निवेशकों को क्या करना चाहिए? कोटक म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह सलाह देते हैं, 'इसमें बिना जोखिम के कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, इसलिए निवेशकों को ऑफर दस्तावेज, मासिक पोर्टफोलियो की जानकारी देने वाली फैक्ट शीट को देखने और पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम को समझने के बाद डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ऐसा करने के लिए ज्यादातर निवेशकों के पास समय नहीं होता है, इसलिए उन्हें वित्तीय योजना के लिए कोई उचित वितरक या सलाहकार चुनना चाहिए।' हाल में येस बैंक में पैदा हुई समस्या थोड़ी अलग है। इसके बहुत से ऋण फंसते जा रहे हैं, इसलिए बैंक को नियामकीय शर्तें पूरी करने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने की जरूरत थी। लेकिन बैंक का प्रबंधन ऐसा नहीं कर पाया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को दखल और अस्थायी रोक के लिए बाध्य होना पड़ा। बैंक के पुनर्गठन के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके प्रारूप के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक 49 फीसदी हिस्सेदारी के बदले 2,450 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

> जब किसी कंपनी में कोई दिक्कत होती है तो फंड प्रबंधक के लिए उस कंपनी के बॉन्डों को द्वितीयक बाजार में बेचना मुश्किल होता है
>
> **महेंद्र जाजू**
> प्रमुख, मिरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट

एडीशनल टियर वन बॉन्ड रद्द

- येस बैंक के एडीशनल टियर वन (एटी-1) बॉन्ड रद्द किए गए
- येस बैंक ने 8,500 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड जारी किए
- इनमें 2,700 करोड़ रुपये के बॉन्ड म्युचुअल फंडों ने खरीदे
- बैंक की अन्य सभी डेट प्रतिभूतियों की रेटिंग डिफॉल्ट कर दी गई है
- म्युचुअल फंडों ने येस बैंक के करीब 100 करोड़ रुपये के अन्य (गैर एटी-1) बॉन्ड भी खरीदे हुए हैं
- इन बॉन्डों के मूल्य को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन एटी-1 बॉन्डों का मूल्य शून्य हो गया है

एटी-1 बॉन्डों में क्या है खास

डेट फंड निवेशकों के लिए समस्याएं बहुत अलग हैं। आम तौर पर जब किसी कंपनी में समस्या पैदा होती है तो बॉन्ड धारकों को सबसे पहले भुगतान किया जाता है। उसके बाद ऋणदाताओं और इक्विटी धारकों को भुगतान किया जाता है। लेकिन एटी-1 बॉन्ड पूरी तरह सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड नहीं हैं। उनकी जगह डेट और इक्विटी के बीच है। उनमें नियमित सीनियर बॉन्डों की तुलना में ऊंची कूपन दर मिलती है। अगर साझा इक्विटी टियर 1 अनुपात एक निश्चित सीमा से नीचे आता है तो इन एटी-1 बॉन्डों के मूल्य को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। येस बैंक का अधिग्रहण करने वाली कंपनी को बैंक का कर्ज वहन करना पड़ता। लेकिन अगर बैंक की बैलेंस शीट कर्ज से लदी होती तो कोई भी कंपनी उसके अधिग्रहण को आगे नहीं आती। यही वजह है कि आरबीआई ने एटी-1 बॉन्डों का मूल्य पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।

येस बैंक ने 8,500 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड जारी किए हैं, जिनमें से करीब 2,700 करोड़ रुपये के बॉन्ड म्युचुअल फंडों ने खरीदे हुए हैं। बैंक की अन्य सभी डेट प्रतिभूतियों की रेटिंग घटाकर डी या डिफॉल्ट कर दी गई है। म्युचुअल फंडों ने येस बैंक के करीब 100 करोड़ रुपये के अन्य (गैर एटी-1) बॉन्ड भी खरीदे हुए हैं। इन बॉन्डों के मूल्य को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन एटी-1 बॉन्डों का मूल्य शून्य हो गया है। येस बैंक के बॉन्डों में मोटे निवेश वाली फंड कंपनियों ने उन्हें अलग कर दिया है। कुछ बॉन्ड धारक डेट को इक्विटी में बदलने की मांग लेकर अदालत में गए हैं।

प्राइमइन्वेस्टर डॉट इन की सह-संस्थापक विद्या बाला कहती हैं, 'येस बैंक कई चुनौतियों से जूझ रहा था और एटी-1 बॉन्डों में नियमित कॉरपोरेट बॉन्डों की तुलना में ज्यादा जोखिम है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि म्युचुअल फंडों के उनमें अपना निवेश क्यों बनाए रखा।' यह संभव है कि फंड प्रबंधकों ने इन बॉन्डों से छुटकारा पाने की कोशिश की हो, लेकिन वे इसमें सफल न रहे हों। मिरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) महेंद्र जाजू ने कहा, 'जब किसी कंपनी में कोई दिक्कत होती है तो फंड प्रबंधक के लिए उस कंपनी के बॉन्डों को द्वितीयक बाजार में बेचना मुश्किल होता है।'

निवेशकों के लिए विकल्प

निवेशकों को यह जांचना चाहिए कि उनके फंड का इन बॉन्डों में कितना निवेश है। बाला ने कहा, 'अगर निवेश अधिक है और शेष पोर्टफोलियो की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो निवेशकों को उस फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर फंड का निवेश इन बॉन्डों में महज 1-2 फीसदी है और शेष पोर्टफोलियो अच्छा है तो निवेशक उस फंड के साथ बने रह सकते हैं।'

मौजूदा निवेशकों के लिए साइड पॉकेटिंग लाभप्रद रहेगा। ऐसा जी एंटरप्राइजेज के मामले में हुआ था, जिसने कुछ देरी के बाद भुगतान किया था।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया में निदेशक (प्रबंधक अनुसंधान) कौस्तुभ बेलापुरकर ने कहा, 'अगर आप मुख्य फंड में भी अपनी यूनिट बेचते हैं तो आपको स्थायी नुकसान नहीं होगा। जब कोई सकारात्मक समाधान होगा तो म्युचुअल फंडों को कुछ पैसा मिल सकेगा। आपको भी अलग पोर्टफोलियो के इन बॉन्डों से कुछ पैसा मिल सकता है।'

निवेशकों के लिए रणनीति

शाह ने कहा, 'जो निवेशक कम ऋण जोखिम उठाना चाहते हैं, उन्हें कम ऋण जोखिम वाले फंडों जैसे डायनैमिक बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड और पीएसयू डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ये फंड प्रतिफल देने के लिए ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव को ठीक से नियंत्रित करते हैं। जो निवेशक क्रेडिट जोखिम उठाना चाहता है, वह क्रेडिट रिस्क फंडों के बारे में विचार कर सकता है। ये फंड अधिक प्रतिफल के लिए कम रेटिंग वाली परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।'

बालासुब्रमण्यन ने कहा कि जहां तक किसी योजना को चुनने का सवाल है, निवेशकों को अपने धन का बड़ा हिस्सा उन अच्छी डेट योजनाओं में लगाना चाहिए, जो 6 महीने से 3 साल की अवधि वाली प्रतिभूतियों में निवेश करती है। उन्होंने कहा, 'इन योजनाओं के परिपक्व होने पर निवेश राशि का फिर से निवेश हो जाता है, इसलिए परिपक्वता पर ब्याज दर फिर से तय होती है।' नए निवेशकों को अच्छे पोर्टफोलियो वाले फंडों से जुड़े रहना चाहिए। जाजू ने कहा, 'मौजूदा माहौल आक्रामक नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाले फंडों से जुड़े रहने के लिए बेहतर है।' वह कहते हैं कि निवेशकों को ऐसे फंडों से बचना चाहिए, जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉडक्ट और एटी-1 बॉन्डों जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं।

कोरोनावायरस को कवर करेगी डिजिट की पॉलिसी

बिंदिशा सारंग

कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या दुनिया भर में लगभग 4,000 पर पहुंच गई है और इससे हजारों लोग संक्रमित हुए हैं। इसे देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सक्रियता दिखाई है। बीमा नियामक ने सामान्य बीमा कंपनियों से मरीजों के लिए कवर मुहैया कराने को कहा है। इस तरह का पहला उत्पाद सामान्य बीमा कंपनी डिजिट द्वारा शुरू किया गया है। हेल्थ केयर प्लस नाम से यह उत्पाद 18 से 60 साल उम्र तक के लोगों के लिए कवर मुहैया कराएगा। पॉलिसीबाजार डॉटकॉम में बिजनेस हेड (हेल्थ इंश्योरेंस) अमित छाबड़ा कहते हैं, 'यह आईआरडीए नियमों के तहत शुरू की गई एक निर्धारित लाभ वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है।' इसके कवर के दायरे में 25,000 रुपये से लेकर 200,000 रुपये तक की राशि शामिल है। प्रीमियम 299 रुपये से शुरू और 2,027 रुपये तक है। पॉलिसी को जुलाई 2020 तक खरीदा जा सकेगा और इसकी अवधि एक साल की होगी।

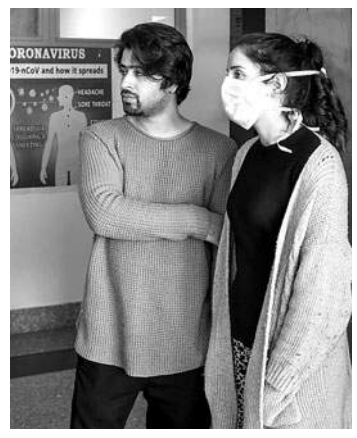

आईआरडीए ने सामान्य बीमा कंपनियों से मरीजों के लिए कवर मुहैया कराने को कहा है

छाबड़ा कहते हैं, 'यदि आप आईसीएमआर-नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलॉजी जैसे किसी अधिकृत संस्थान में कोविड-19 की जांच कराते हैं और इसका परिणाम 'पॉजीटिव' निकलता है तो बीमा कंपनी आपको पूरी बीमित रकम का भुगतान करेगी।' यदि आपको इस वायरस के लक्षणों की वजह से किसी अधिकृत स्थान पर सिर्फ क्वारंटाइन के तौर पर रखा जाता है, तो आपको क्लेम की राशि का 50 प्रतिशत मिलेगा, भले ही आपकी जांच बाद में निगेटिव निकले। सिम्बो इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग के सह-संस्थापक एवं सीईओ अनीक जैन कहते हैं, 'कई स्टैंडर्ड स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति कवर प्रदान करती हैं। क्लेम का भुगतान बीमारी की पहचान के बाद किया जाएगा। इस पॉलिसी में क्वारंटाइन के लिए भी बेनीफिट कवर मौजूद है जो एक बड़ा सुधार है।'

यह पॉलिसी कुछ क्षेत्रों की यात्रा प्रतिबंधित करती है। इसे खरीदने से पहले संदिग्ध मरीजों के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहिए। हालांकि भारत में कहीं भी ठहरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी उस व्यक्ति या उसके पारिवारिक सदस्य के लिए नहीं मिलेगी जिसने चीन और जापान जैसे देशों की यात्रा की हो। भले ही आपको सामान्य सर्दी हो, आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। क्या आपके पास नियोक्ता का या पर्सनल हेल्थ कवर है? यदि हां, तो कोरोनावायरस संक्रमण के लिए भर्ती होने पर आपको इस कवर का लाभ मिलेगा। अनीक जैन कहते हैं, 'मौजूदा बीमा योजनाएं अस्पताल में भर्ती होने का खर्च कवर करेंगी, लेकिन ओपीडी और क्वारंटाइन खर्च को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अपने बीमा प्लान में शामिल यात्रा संबंधी किसी चेतावनी पर भी सतर्कतापूर्वक विचार करें।'

भले ही आपने किसी व्यक्तिगत पॉलिसी या ग्रुप हेल्थ पॉलिसी के तहत क्लेम किया हो, लेकिन यह नई पॉलिसी नकदी मुहैया कराएगी, जो सुविधाजनक साबित होता है। प्रमाणित वित्तीय योजनाकार पंकज मठपाल कहते हैं, 'प्रीमियम कम है। खासकर कामकाजी या भीड़-भाड़ वाले इलाकों की यात्रा करने वाले या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले लोग इसे खरीदने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। कुछ शर्तों की वजह से आपको क्लेम आसानी से नहीं मिल सकता है। सामान्य जुकाम या श्वास संबंधी किसी अन्य बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति यह पॉलिसी नहीं खरीद सकेगा।' यदि उस इलाके में रहते हैं जहां कोरोनावायरस के मामले की पुष्टि हो चुकी है, तो याद रखें 'डिजीज-स्पेसिफिक पॉलिसी' किसी अन्य पॉलिसी के मुकाबले सस्ती है और इसे कामचलाऊ उपाय के तौर पर खरीदा जा सकता है। जिन लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उनके लिए स्वास्थ्य पॉलिसी का लाभ लेने के लिए यह अच्छा माध्यम होगा। चूंकि इसमें प्रीमियम कम है, इसलिए खतरनाक वायरस के खिलाफ इसे अपने बीमा उत्पादों में शामिल करना समझदारी भरा निर्णय साबित हो सकता है। इसके अलावा, सेवानिवृत लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं, भले ही उनके पास अतिरिक्त लाभ के लिए एक अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद हो। इसकी वजह यह है कि इस उम्र के लोगों में वायरस की चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है।

नए नियमों के अनुरूप पॉलिसी

किसलिए	विवरण
मौजूदा उपचार	बीमित रकम का 100 प्रतिशत
क्वारंटाइन में	बीमित रकम का 50 प्रतिशत
बीमित रकम	25,000 से 2,00,000 रुपये
सर्वाइवल अवधि	0 दिन
पॉलिसी अवधि	1 साल
शुरुआती प्रतीक्षा अवधि	15 दिन
उम्र सीमा	60 वर्ष तक
प्रस्ताव की वैधता अवधि	31 जुलाई, 2020

स्रोतः पॉलिसीबाजार

डायरेक्ट प्लान के निवेशकों को मिल सकता है ज्यादा लाभ

निवेशक म्युचुअल फंड हाउसों के जरिये लेनदेन के बजाय स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों से डायरेक्ट प्लान खरीद और बेच सकते हैं

बिंदिशा सारंग

म्युचुअल फंडों में डायरेक्ट प्लान निवेशकों के लिए खुशी का मौका है। दरअसल बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को सीधे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों से म्युचुअल फंडों की यूनिट खरीदने और बेचने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि जो अति धनाढ्य व्यक्ति (एचएनआई) और अन्य लोग अपने स्तर पर जांच-पड़ताल कर चुके हैं वे सीधे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से अलग-अलग फंडों की कितनी भी योजनाएं खरीद सकते हैं। उन्हें अलग-अलग म्युचुअल फंडों की वेबसाइटों पर नहीं जाना होगा।

म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म- बीएसई स्टार म्युचुअल फंड और एनएसई एनएमएफ 2 बहुत लोकप्रिय हैं। बीएसई स्टार म्युचुअल फंड ने फरवरी में महज एक दिन में 1,075 करोड़ रुपये के 10 लाख से अधिक के लेनदेनों को निपटाया है। इस कदम से उन्हें और प्रोत्साहन मिलने के आसार है।

कुबेरा डॉट इन के संस्थापक और सीईओ गौरव रस्तोगी ने कहा, 'ताजा पहल निवेशकों को म्युचुअल फंड हाउस के डायरेक्ट प्लान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हम पहले ही अपने लेनदेनों को निपटाने के लिए बीएसई स्टार म्युचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक्सचेंज का बुनियादी ढांचा बेहतर होना पूरे उद्योग के लिए बेहतर होगा।'

सेबी की मंजूरी

- सेबी ने निवेशकों को सीधे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों से म्युचुअल फंडों की यूनिट खरीदने और बेचने की मंजूरी दी
- अति धनाढ्य व्यक्ति और अन्य लोग सीधे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से अलग-अलग फंडों की योजनाएं खरीद सकते हैं
- अब म्युचुअल फंडों की विभिन्न वेबसाइटों पर नहीं जाना होगा
- म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म- बीएसई स्टार म्युचुअल फंड और एनएसई एनएमएफ 2 बहुत लोकप्रिय हैं

कई विकल्प

इस समय आप म्युचुअल फंड खरीदने के लिए नियमित या प्रत्यक्ष तरीका अपनाते हैं। नियमित तरीका थोड़ा महंगा है क्योंकि म्युचुअल फंड वितरक योजना चुनने और आपको लेनदेन में मदद करने के लिए कमीशन वसूलते हैं। वहीं प्रत्यक्ष तरीके में आप कुबेरा डॉट इन, पेटीएम मनी, ग्रो जैसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिये खरीदारी करते हैं। इसके अलावा सीएएमएस और कार्वी, म्युचुअल फंड यूटीलिटीज जैसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं। ये एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर बहुत सी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का स्वामित्व है।

इन्हें एसोसिएएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एम्फी) ने शुरू किया है। फीस आधारित आरआईए स्वप्निल केंधे ने कहा, 'अब निवेशक बिना किसी बिचौलिये की मदद के पूरा निवेश को एक जगह रख सकता है।'

अब तक केंधे सीएएमएस ऐप को तरजीह देते हैं, जो बिना किसी बिचौलिये के डायरेक्ट प्लान को मंजूरी देता है। उनका मानना है कि स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी अच्छा विकल्प होंगे। सीएएमएस आपको ऐसी सेवा मुहैया कराती है, जिसमें आप सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैं।

जहां तक म्युचुअल फंड यूटीलिटीज का सवाल है, यह आपको भारत में 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) में से 38 फंड हाउसों में निवेश की मंजूरी देता है। यह एल्गोरिद्म और तकनीक की मदद से एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो के जरिये राबो-एडवाइजरी मुहैया कराता है। हालांकि वे बहुत से राबो-सलाहकारों और मुफ्त लेनदेन प्लेटफॉर्मों के लिए थोड़ा कट-ऑफ समय कम रखते हैं ताकि वे उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) प्राप्त करने की पात्रता हासिल कर सकें। इसकी वजह यह है कि वे एक्सचेंजों के साथ लेनदेन करते हैं। ये एक्सचेंज इन ऑर्डरों को प्राप्त करते है और उन्हें रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के पास भेज देते हैं।

> इससे एक्सचेंज म्युचुअल फंड वितरण प्लेटफॉर्मों को म्युचुअल फंड यूटिलिटीज के समान मौके मिलेंगे
>
> **गणेश राम**
> बीएसई स्टार म्युचुअल फंड

दूसरे शब्दो में उनका एक अतिरिक्त चरण है। जब आपको सेवानिवृत्ति जैसे वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश में सलाह की जरूरत है लेकिन पूरे जीवन की वित्तीय योजना की जरूरत नहीं है तो राबो-सलाह एक अच्छा विकल्प है। आपकी सलाह की जरूरतें समय के साथ बदलती हैं और ये प्लेटफॉर्म इन्हें संभालते हैं और सही समय पर सही दिशानिर्देश मुहैया कराते हैं। जहां तक नए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों का सवाल है, वे आपको आधिकारिक समयसीमा तक म्युचुअल फंडों में निवेश करने देते हैं और इसलिए उसी दिन का एनएवी प्राप्त होता है। लेकिन आपको आपकी जरूरत के मुताबिक तैयार पोर्टफोलियो सुझाव नहीं मिलता है।

इस समय बहुत से पंजीकृत निवेश सलाहकार पहले ही स्टॉक एक्सचेंजों का इस्तेमाल म्युचुअल फंडों की खरीद-बिक्री, एसआईपी, सिस्टेमैटिक निकासी योजना, सिस्टेमैटिक हस्तांतरण योजना आदि में कर रहे हैं। अब ये सभी सुविधाएं डायरेक्ट निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होंगी। बीएसई स्टार म्युचुअल फंड के प्रमुख गणेश राम ने कहा, 'इससे एक्सचेंज म्युचुअल फंड वितरण प्लेटफॉर्मों को म्युचुअल फंड यूटिलिटीज के समान मौके मिलेंगे।' यह बात ध्यान में रखें कि डायरेक्ट म्युचुअल फंड निवेश पहली बार निवेश करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि बाजार का उतार-चढ़ाव ऐसे निवेशकों को अपने निवेश में फेरबदल या निकासी करने को बाध्य कर सकता है। इसके नतीजतन उनके अपने निवेश की लंबी अवधि की चक्रवृद्धि संभावनाओं को गंवाने का जोखिम होता है।

कोरोना से निपटने के लिए कोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपात कोष के लिए 1 करोड़ डॉलर देने की पेशकश की

अर्चिस मोहन

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) के प्रतिनिधियों के साथ कोरोनावायरस के गहराते संकट को नियंत्रित करने की तैयारियों का ब्योरा साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भी हालात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। रविवार को दक्षेस सदस्य देशों के नेताओं के बीच टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वार्ता हुई जिसमें नेताओं ने इस संक्रमण से निपटने के लिए ज्यादा सहयोग करने पर सहमति जताई जिनमें अपने-अपने देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा करना भी शामिल है।

श्रीलंका, मालदीव और भूटान जैसे देशों की निर्भरता पर्यटन क्षेत्र पर ज्यादा है जो हाल के हफ्ते में काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली और भूटा के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि यह साझा संघर्ष न केवल कोरोनावायरस के खिलाफ है बल्कि अर्थव्यवस्था में गिरावट के खिलाफ भी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोनावायरस के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति अपनाने की वकालत करते हुए रविवार को दक्षेस में कोविड-19 आपात कोष सृजित करने का प्रस्ताव किया और कहा कि भारत इस कोष के लिए 1 करोड़ डॉलर की प्रारंभिक पेशकश से शुरुआत कर सकता है।

दक्षेस में सात सदस्य देश हैं लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद बढ़ने से से पिछले छह सालों से इसमें निष्क्रियता की स्थिति बनी हुई है।

दक्षेस देशों के नेताओं के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद करते प्रधानमंत्री मोदी (पीटीआई)

- पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने दक्षेस देशों के संवाद में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया
- श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने मंत्रिस्तरीय समूह के गठन का प्रस्ताव दिया
- अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने टेली मेडिसिन साझा नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया

कश्मीर का मुद्दा

दक्षेस देशों के साथ कोरोना वायरस पर संवाद के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा कि वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदी हटा लेनी चाहिए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए चीन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दक्षेस देश उन बेहतरीन पहलों को अपना सकते हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य मामलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा शामिल हुए।

कैसे सुझाव

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वायरस से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दक्षेस मंत्रिस्तरीय समूह के गठन का प्रस्ताव दिया। शेख हसीना ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के बीच लगातार संवाद का सुझाव दिया जबकि गनी ने वायरस की समस्या से निपटने के लिए टेली-मेडिसिन का एक साझा नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मालदीव के राष्ट्रपति ने समन्वित पहल पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश इस हालात से अकेले नहीं निपट सकता। जफर मिर्जा ने कहा कि वायरस से बनी स्थिति से कोई देश मुंह नहीं मोड़ सकता पर सामूहिक प्रयास ही वायरस से निपटने में दक्षेस क्षेत्र में ठोस रणनीति तैयार करने में मदद करेगा।

देश में 107 लोग संक्रमित

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या रविवार को बढ़कर 107 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इनमें वे दो लोग भी शामिल हैं जिनकी दिल्ली और कर्नाटक में मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोनावायरस के अब तक सात मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 11, कर्नाटक में छह, महाराष्ट्र में 32, लद्दाख में तीन और जम्मू-कश्मीर में दो संक्रमित हैं।

इसके अलावा राजस्थान में कोरोनावायरस के दो और मामले सामने आए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में एक-एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। केरल में कोरोना वायरस के सबसे अधिक 22 मामले सामने आए हैं। इनमें वे दो लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले महीने इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कुल 93 संक्रमित लोगों में से 17 विदेशी हैं। इनमें 16 लोग इतालवी हैं।

ईरान और इटली में फंसे हुए 450 से अधिक भारतीयों को रविवार को दो विमानों से वापस लाया गया और उन्हें अलग केंद्रों में रखा गया।

एजेंसियां

स्पेन में एक दिन में 2,000 लोग संक्रमित

दुनिया में कोरोनावायरस से 153,864 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जबकि 5,800 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में इटली के बाद स्पेन वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। शनिवार को स्पेन में 5,753 मामले की पुष्टि हुई। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस से संक्रमण के 2,000 नए मामले सामने आए, 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जर्मनी ने इटली, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रिया से आने वाले लोगों को खुद ही दो हफ्ते तक अलग रहने को कहा है।

फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैफे, रेस्तरां, सिनेमा, नाइटक्लब और दुकानों जैसी गैर-जरूरी जगहों को बंद कर दिया जाए। नॉर्वे सोमवार से अपने बंदरगाह और हवाईअड्डे को बंद करेगा हालांकि विदेश से वापस आ रहे नॉर्वे के नागरिकों को इसमें छूट दी जाएगी। वहीं रूस की सरकार के आदेश पर पोलैंड और नॉर्वे से लगती सीमा को विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया है। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने वायरस संक्रमण से मौत के पहले मामले की पुष्टि की।

मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में देखा जाए तो ईरान में संक्रमित लोगों की मरने तादाद बढ़कर 724 हो गई जबकि 12,729 संक्रमित हैं। ईरान में वायरस से एक ही दिन में 113 और लोगों की मौत हो गई। ईरान ने रविवार को इसकी घोषणा की। वायरस संक्रमण से प्रभावित इस देश में एक ही दिन में इतनी अधिक मौत होने का यह पहला मामला है। इन मौतों के बाद ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 724 हो गई।

संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। फिलीस्तीन में मस्जिद और चर्च में प्रार्थना बंद करा दी है। रवांडा में कोरोनावायरस से पहले मामले की पुष्टि हुई है और यह संक्रमण भारतीय नागरिक में पाया गया है। कजाखस्तान ने कोरोनावायरस को लेकर आपातकाल की घोषणा की है। चीन में रविवार को संक्रमण के कारण 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों संख्या बढ़कर 3,199 हो गई है।

दक्षिण कोरिया में स्वास्थ्यकर्मी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कोरोनावायरस की जांच में संक्रमित नहीं पाए गए हैं।

वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के सभी कर्मचारियों को 16 मार्च से 12 अप्रैल तक घर से काम करने और फोन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए यूरोपीय देशों पर लगाए अपने यात्रा प्रतिबंध ब्रिटेन पर भी लागू कर दिए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बताया कि नई यात्रा पाबंदियां सोमवार रात से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक और ब्रिटेन या आयरलैंड में वैध स्थायी निवासी घर आ सकते हैं।

कोच्चि में दुबई जाने वाली उड़ान से कोरोनावायरस से संक्रमित ब्रिटिश नागरिक समेत 20 यात्रियों को हिरासत में लिया गया है।

एजेंसियां

कोरोना से निपटने की तैयारी पर्याप्त नहीं

सचिन मामबटा और सोहिनी दास

सरकार ने मॉल और भीड़ वाली जगहों को बंद करने की घोषणा देश में कोरोनावायरस संक्रमण को नियंत्रित करने का अहम पहलू हो सकता है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और 10 शीर्ष प्रभावित देशों के डेटा के विश्लेषण से यह अंदाजा होता है कि भारत ऐसी महामारी के लिए जरूरी संसाधनों के लिहाज से पीछे रहेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 13 मार्च तक खत्म हुए हफ्ते के दौरान 123 देशों में 132,536 मामले की पुष्टि हुई है। चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, स्विटजरलैंड और जापान जैसे शीर्ष 10 देशों में मामले की पुष्टि हुई है। कोविड-19 के 90 फीसदी मरीज इन्हीं देशों से हैं। इन देशों के मुकाबले भारत में प्रति 1,000 लोगों में से कुछ को ही अस्पताल का बेड और डॉक्टर उपलब्ध होगा।

देश में एक बड़े तबके के पास हाथ धोने के सामान और बीमारी को दूर रखने की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की सुविधाएं नहीं हैं। देश में काफी तादाद में लोगों की माली हालत इस वजह से भी खराब हो जा रही है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ जाती है। इससे यह अंदाजा मिलता है इस महामारी के फैलने पर स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें आएंगी और असमानता की खाई बढ़ेगी। विश्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण से भी इस असमानता का अंदाजा होता है कि भारत और कोरोनावायरस से अब तक प्रभावित प्रमुख देशों के बीच कितना अंतर है। वर्ष 2011 में भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 0.7 अस्पताल और इतने ही डॉक्टर थे जबकि चीन में इसी साल 3.8 और इटली में 3.5 अस्पताल थे। वहीं चीन में 1.8 और इटली में 4.1 डॉक्टर थे। कोविड-19 से बचने के लिए हाथ-धोने की सिफारिश की जाती है। 2017 के आंकड़ों से यह अंदाजा मिलता है कि करीब 50.7 फीसदी ग्रामीण आबादी के पास हाथ धोने की बुनियादी सुविधा यानी साबुन और पानी तक नहीं है। शहरी आबादी में 20.2 फीसदी आबादी और कुल 40.5 फीसदी आबादी के पास कोई सुविधा नहीं है। भारतीय लोग बड़ी बीमारी की चपेट में आने पर खर्च की वजह से गरीबी में फंस जाते हैं। 2011 में स्वास्थ्य सेवाओं पर हैसियत से ज्यादा खर्च ईरान में 0.03 फीसदी जबकि भारत 4.16 फीसदी रहा। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि भारत स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करने वाले देशों में नहीं रहा है। वर्ष 2016 में विश्व बैंक के पास उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा होता है कि भारत में सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य पर 3.14 फीसदी खर्च किया गया जबकि चीन में यह खर्च 9.05 फीसदी तक रहा वहीं इटली में 13.47 फीसदी जबकि ईरान में स्वास्थ्य पर 22.6 फीसदी खर्च किया गया।

भारत में 'आयुष्मान भारत' के जरिये स्वास्थ्य बीमा देने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं कि अस्पताल इस योजना के मरीजों को लेने से इनकार कर रहे हैं। मणिपाल एजुकेशन ऐंड मेडिकल ग्रुप (एमईएमजी) के चेयरमैन रंजन पई का कहना है, 'जब ऐसी महामारी होती है तब किसी भी देश का स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा चरमरा जाता है। मुझे लगता है कि सरकार काफी सक्रियता दिखा रही है। मैंने इससे पहले वैश्विक स्तर पर कोई अफरा-तफरी नहीं देखी है।' विनिर्माण सेगमेंट के मुताबिक मास्क, श्वसन से जुड़े उपकरण की कमी से भी वैश्विक स्तर पर हलचल है और भारत में भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) के राजीव नाथ कहते हैं, 'चीन से कई उपकरणों के आयात में कमी की वजह से देश के स्वास्थ्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा क्योंकि चीन पर इन उपकरणों को लेकर काफी निर्भरता रही है। वैश्विक स्तर पर मास्क और ग्लोव की कमी का फायदा लेने के लिए घरेलू कंपनियां विनिर्माण पर जोर दे रही हैं।' नाथ का कहना है कि वे विनिर्माण क्षमता और वेंटीलेटर तथा ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता से जुड़े आंकड़े जुटा रहे हैं। 3 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इसने 47 देशों में 5 लाख सुरक्षात्मक उपकरण और सामान भेजे हैं लेकिन अब भी आपूर्ति कम पड़ रही है। इसका अनुमान है कि वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए निर्माण में 40 फीसदी की बढ़ोतरी जरूरी है। डब्ल्यूएचओ ने 'कोविड 19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड' बनाया है।

अस्पताल में बेड की कितनी सुविधा

प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर अस्पताल में बेड

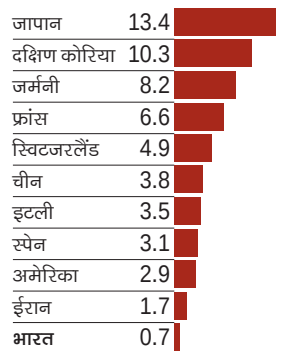

नोटः दक्षिण कोरिया और जापान के आंकड़े 2012 के हैं। बाकी सभी देशों के आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। स्रोतः विश्व बैंक

पर्याप्त नहीं डॉक्टर

प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर डॉक्टर

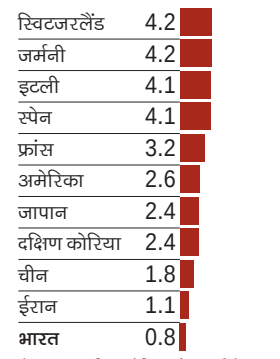

नोटः भारत, दक्षिण कोरिया और इटली के डेटा 2017 के हैं। चीन और ईरान के आंकड़े 2015 के हैं। बाकी सभी देशों के आंकड़े वर्ष 2016 के हैं

मल्टीप्लेक्स कंपनियों को 26 फीसदी घाटा

सोहिनी दास

कोरोनावायरस (कोविड-19) ने अर्थव्यवस्था के हरेक क्षेत्रों के साथ मनोरंजन उद्योग को भी लगभग तबाह कर दिया है। मौजूदा हालात ने भारत के मल्टीप्लेक्स चेन (एक से अधिक पर्दों वाले सिनेमाघर) के सामने कठिन चुनौती पेश की है। विभिन्न राज्य सरकार ने मौके की नजाकत समझते हुए अपने-अपने राज्यों में सिनेमाघर बंद करने के आदेश दिए हैं। इससे अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' समेत कई फिल्मों की रिलीज (फिल्मों का प्रदर्शन) टल गई है। मनोरंजन उद्योग पर नजर रखने वाले लोगों के अनुसार पिछली तिमाही के मुकाबले मार्च में राजस्व में कम से कम 20-25 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।

पिछले शुक्रवार को इरफान की फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' रिलीज हुई थी, लेकिन पहले दिन इसने मात्र 4.03 करोड़ रुपये ही कमाई की। तरण आदर्श जैसे विश्लेषकों का कहना है कि कोरोनावायरस के कारण कई राज्यों में इस फिल्म के कारोबार को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार अंग्रेजी मीडियम की कमाई बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को 25 प्रतिशत कम हो गई। इस समय यह फिल्म ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कारोबार कर रही है। टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म 'बागी 3' की कमाई भी शनिवार को 25 प्रतिशत कम हो गई। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ ही कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा जैसे राज्यों में सिनेमाघर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। एक मल्टीप्लेक्स चेन के मालिक ने कहा कि भारत में करीब 3,000 मल्टीप्लेक्स हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक बंद हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई और मल्टीप्लेक्स बंद हो सकते हैं।

देश में करीब एकल पर्दे वाले करीब 6,600 सिनेमाघर हैं। एसबीआईकैप सिक्योरिटीज ने हाल की अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान एकल पर्दे वाले सिनेमाघरों का कारोबार खासा कमजोर रहा है। इन्हें भी बंद किया जा रहा है।

कोरोना के डर से दर्शक हुए कम